



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]  
No. 366]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2005/चैत्र 18, 1927  
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2005/CHAITRA 18, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2005

सं. 1 (आर ई-2005)/2004—2009

का. आ. 530(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 1.2 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 8 अप्रैल, 2005 तक यथा अद्यतन वार्षिक परिशिष्ट को शामिल करते हुए इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथा निहित विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 को एतद्वारा अधिसूचित करती है। यह नीति 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/94/180/विदेश व्यापार नीति/एएम 05/पी सी-1]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**अनुबन्ध****विदेश व्यापार नीति**

( 1 सितम्बर, 2004—31 मार्च, 2009 )

( 1 अप्रैल, 2005 तक अद्यतन )

**प्रस्तावना****सन्दर्भ**

विश्व व्यापार में भारत द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए देश के विदेश व्यापार के समग्र विकास हेतु विस्तृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। यद्यपि निर्यात में वृद्धि का विशेष महत्व है, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था को उद्वेलित करने के लिए हमें जरूरी आयातों को सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। विकास के लिए इन नीतियों के योगदान को अधिकतम करने हेतु व्यापार और अन्य आर्थिक नीतियों के बीच सामंजस्य और सुसंगति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, वार्षिक निर्यात-आयात नीति घोषित करने की मौजूदा परम्परा को जारी रखते हुए इससे कहीं आगे जाकर भारत की विदेश नीति की विकासात्मक अवश्यकताओं का समेकित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। नयी विदेश व्यापार नीति इसी सन्दर्भ में जारी की जा रही है।

**उद्देश्य**

व्यापार अपने आप में अन्तिम उद्देश्य नहीं है बल्कि यह आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास का माध्यम है। प्रमुख उद्देश्य केवल विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं बल्कि संबंधित आर्थिक कार्यक्रमों को उद्वेलित करना है। विदेश व्यापार नीति इस विचारधारा से प्रेरित है और दो प्रमुख उद्देश्यों से प्रभावित है, जोकि इस प्रकार हैं:-

1. अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में हमारी भागीदारी की प्रतिशतता को आगामी पांच वर्षों के भीतर दो गुनी करना: तथा
2. रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए आर्थिक विकास के प्रभावी उपकरण के तौर पर कार्य करना।

**रणनीति**

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाते हुए इन उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रस्तावित है:

1. हमारे व्यवसायकर्ताओं, उद्योगपतियों और व्यापारियों की स्वाभाविक उद्यमियता को बढ़ावा देने के लिए विश्वास और पारदर्शिता का माहौल बनाने हेतु नियंत्रणों को हटाना।
2. प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सौदे की लागत को कम करना।

3. इस मूल सिद्धान्त के आधार पर कि शुल्कों और प्रशुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए, अतः निर्यात उत्पादों में इस्तेमाल की गई निविष्टियों पर सभी प्रशुल्कों और शुल्कों को निष्प्रभावी बनाना ।
4. विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र में भारत को एक विश्व ताकत के रूप में विकसित करना ।
5. उन क्षेत्रों का पता लगाना तथा इन्हें विकसित करना जिनपर विशेष बल दिया जाना है, जिससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रेरक स्रोतों को विकसित करना ।
6. भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के प्रौद्योगिकीय और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं और उपकरणों का आयात करके, इस प्रकार गुणवत्ता के स्वीकृत मानदण्डों को अन्तरराष्ट्रीय रूप से प्राप्त करते हुए मूल्य संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि करना ।
7. शुल्क वापसी के ढांचे की प्रणाली से बचना और यह सुनिश्चित करना कि हमारे घरेलू क्षेत्र निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से किए गए मुक्त व्यापार समझौतों/क्षेत्रीय व्यापार समझौतों/प्राथमिक व्यापार समझौतों का उल्लंघन नहीं हुआ है ।
8. अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सम्पूर्ण विदेशी व्यापार श्रृंखला से संबंधित वास्तविक और आभासी दोनों के बुनियादी नेटवर्क को विकसित करना ।
9. व्यापार बोर्ड की भूमिका को पुनः परिभाषित करके इसे पुनः जीवित करना, इसे उचित मान्यता देना तथा व्यापार नीति में विशेषज्ञों को शामिल करना ।
10. हमारी निर्यात रणनीति में हमारे दूतावासों को मुख्य भूमिका निभाने के लिए गतिशील बनाना और विदेश में हमारे वाणिज्यिक प्रभागों को इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म से जोड़ना ताकि वास्तविक रूप से व्यापार आसूचना और पूछताछ के दायरे को बढ़ाया जा सके ।

भागीदारी

नई नीति में कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक/व्यापारिक निर्यातक और विनिर्माता निर्यातक, व्यापार और उद्योग जगत सरकार के भागीदार हैं। लम्बे समय तक चलने वाली और अनावश्यक मुकदमेबाजी भागीदारी को बिगाड़ती है। मुकदमेबाजी की जरूरत को दूर करने के लिए सृजनात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने हेतु उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है, जो मुकदमेबाजी को काफी कम करेगी और भागीदारी के रिश्ते को मजबूत बनाएगी।

उदार व्यापार प्रणाली का गति विज्ञान कई बार डम्पिंग के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाता है। जब ऐसा घटित होता है तो इस नुकसान को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

प्रारूप (रोड मैप)

यह नीति भारत के विदेश व्यापार के विकास हेतु अनिवार्य प्रारूप है। हमें जिस दिशा में अग्रसर होना है उसके आधारभूत सिद्धांत और मुद्दे इसमें शामिल हैं। कोई व्यापार नीति केवल अपने गति-विज्ञान की वजह से ही अपने सभी ब्यौरों के बावजूद पूर्णतः व्यापक नहीं हो सकती है। इसके लिए समय समय पर संशोधन करना स्वाभाविक तौर पर आवश्यक होगा। हम अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अवश्यंभावी परिवर्तनशील गति-विज्ञान पर आधारित निरन्तर अद्यतन करने के माध्यम से ऐसा करने का प्रस्ताव करते हैं। व्यापार और उद्योग जगत के साथ भागीदारी के माध्यम से हम इस प्रारूप (रोड मैप) पर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं।

(कमल नाथ)  
वाणिज्य और उद्योग मंत्री  
भारत सरकार

नई दिल्ली

31 अगस्त, 2004



## अध्याय - एक (क)

विधिक ढाँचा

- |                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| प्रस्तावना           | 1.1 | प्रस्तावना में वृहत ढांचे को इंगित किया गया है तथा यह विदेश व्यापार नीति का अभिन्न अंग है।  |
| अवधि                 | 1.2 | विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्यात एवं आयात नीति 2002-2007 यथासंशोधित को सम्मिलित करते हुए एवं आयात नीति 2004-2009 की अवधि के लिए विदेश व्यापार नीति को अधिसूचित करती है। यह नीति 1 सितम्बर, 2004 से लागू होगी तथा 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेगी, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए।  |
| संशोधन               | 1.3 | केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में इस नीति में संशोधन का अधिकार रखती है। ऐसे संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से किए जाएंगे।  |
| अन्तर्वर्ती व्यवस्था | 1.4 | पूर्व निर्यात/आयात नीतियों के अंतर्गत जारी की गई कोई भी व्यवस्था अधिसूचना या सार्वजनिक सूचना या अन्य व्यवस्था जो इस नीति के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू थी, वह जब तक इस नीति के प्रावधानों में असंगत न हों, लागू रहेगी तथा उन्हें इस नीति के तहत जारी किया माना जाएगा।<br>इस नीति से पूर्व जारी किए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमत पत्र उस उद्देश्य और अवधि के लिए जिसके लिए ये लाइसेंस प्रमाणपत्र और अनुमत पत्र जारी किए गए हैं मान्य रहेंगे जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो। |
|                      | 1.5 | यदि इस नीति के तहत मुक्त रूप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियमित किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे प्रतिबंध से पूर्व स्थापित अपरिवर्तनीय साख-पत्र के प्रति ऐसे निर्यात या आयात का पोत लदान ऐसे प्रतिबंध से लागू होने की मूल वैधता अवधि के भीतर हो जाए।                               |

अध्याय - एक (ख)विशेष ध्यान देने योग्य पहल

विशेष ध्यान देने  
योग्य पहल

1ख.1

विश्व व्यापार में 5 वर्ष के अन्दर अपनी भागीदारी का प्रतिशत दुगुना करने तथा विशेष रूप से अर्द्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण तथा चमड़े से बने सामान के क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ाने कुछ विशेष ध्यान देने योग्य पहल पहचान लिए गए हैं ।

भारत सरकार इन क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास करेगी जिनके लिए क्षेत्र विशेष रणनीति तय करेगी जिसको समय समय में अधिसूचित किया जाएगा ।

अभी इन विशेष क्षेत्रों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी :-

घोषित किए जाने  
वाले नए क्षेत्रीय  
पहल

अन्य क्षेत्रों में भी समय-समय पर नए क्षेत्रीय पहल भी घोषित किए जाएंगे ।

(1) कृषि

(क) फलों, सब्जियों, फूलों, तुच्छ बन उत्पादों, दुग्ध, मुर्गीपालन तथा उनके मूल्य वृद्धि उत्पादों के लिए विशेष कृषि उपज योजना नामक एक नई योजना बनायी गयी । (पैरा 3.8)

(ख) कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई.जैड) के विकास के लिए ए एस आई डी ई के अन्तर्गत धन दिया जाएगा।

(ग) हटा दिया गया है ।

(घ) हटा दिया गया है ।

(ङ) ई पी सी जी के अन्तर्गत आयातित माल ए ई जैड में किसी भी स्थान में लगाने की अनुमति होगी ।

- (च) प्रतिबंधित मदों जैसे कि पैनल, के आयात की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत अनुमति होगी।
- (छ) कृषि निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत कीटनाशक जैसे इनपुट के आयातों की अनुमति होगी।
- (ज) रु0 250 करोड़ के न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात वृद्धि के नये कस्बों को अधिसूचित किया जाएगा।

## (ii)

**हथकरघा**

- (क) हथकरघा निर्यात को बढ़ाने के लिए एम.ए.आई./एम डी ए योजना के तहत विशिष्ट निधि निर्धारित की जाएगी।

- (ख) विशिष्ट कटाई छटाई के शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वितीय वर्ष के निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत होगी।

- (ग) हाथ से बनाई हुई चटाई के नमूनों पर शुल्क मुक्त आयात की हकदारी पिछले वितीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत होगा।

- (घ) हाथ से बनाई हुई चटाई के पुराने टुकड़ों की खेप का शुल्क मुक्त आयात का पुनः निर्यात मरम्मत के बाद अनुमत होगा।

- (ङ.) रु0 250 करोड़ के न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात वृद्धि के नये कस्बों को अधिसूचित किया जाएगा।

- (च) हस्तशिल्प हेतु “वूल मार्ग” की तर्ज पर “सिल्क माक” ट्रेडमार्क विकसित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इससे हस्तशिल्प वस्तुओं हेतु विशिष्ट पहचान वाले विशेष बाजार विकसित करने में मदद मिलेगी।

## (III)

**हस्तशिल्प**

- (क) नये हस्तशिल्प विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थापित किए जायेंगे जो निर्यात के लिए कॉटेज क्षेत्र से खरीदे गए उत्पाद को तैयार करेंगे।

(ख) कटाई और छाटाई की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 5 प्रतिशत होगी। हकदारी ब्रांड बैडेड है जिसकी सुविधा सहायक विनिर्माताओं के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातकों को भी दी जायेगी।

(ग) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद उन निर्यातकों की तरफ से जो परोक्ष रूप से निर्यात करने में सुदृढ़ नहीं हैं के कटे हुए छटे हुए और उपभोज्यों को आयात करने के लिए प्राधिकृत होगी।

(घ) हस्तशिल्प के प्रोत्साहन हेतु लिए एमएआई/एमडीए योजना के अधीन विशेष कोष निर्धारित किए जायेंगे।

(ङ) शुल्क मुक्त आयात पर ट्रिमिंग इम्बेलिशमेन्ट और उपभोज्यों पर सीवीडी की छूट होगी।

(च) रु0 250 करोड़ के न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात वृद्धि के नये कस्बों को अधिसूचित किया जाएगा।

(iv) रत्न और

आभूषण:

(क) 8 कैरेट और अधिक के सोने का आयात प्रतिभूति योजना के अधीन अनुमेय होगा बशर्ते आयात के साथ शुद्धता, भार और धातु मात्रा दर्शाता हुआ एक ऐसा प्रमाण पत्र भी हो।

(ख) सोना प्लेटिनम के अलावा धातुओं के लिए उपभोज्यों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत तक होगी।

(ग) व्यापारिक नमूनों की शुल्क मुक्त निर्यात हकदारी 300,000 रुपये होगी।

(घ) नकार दिए आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुनः आयात हकदारी निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 2 प्रतिशत होगी

- कटे एवं पोलिश किए हुए रत्न और आभूषणों को  
(ड.) आयकर अधिनियम के खण्ड-10 के अधीन छूट  
के उद्देश्य के लिए तैयार माल की तरह माना  
जायेगा।

**(V) चमड़ा****और जूते**

- (क) विनिर्दिष्ट मदों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी चालू  
वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क  
मूल्य का 5 प्रतिशत होगी।
- (ख) जूतों (चमड़ा और सिंथेटिक दोनों) दस्ताने, यात्रा  
बैग और हैंड बैग के लिए ट्रिमिंग्स, इम्बेलिशमेन्ट  
और जूते उपांगों के आयात के लिए शुल्क मुक्त  
हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के पोत  
पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 3 प्रतिशत होगी।  
हकदारी पैकिंग सामग्री, जैसे छपे हुए और बिना छपे  
हुए जूतों के डिब्बे, लकड़ी के छोटे कार्टन, जूतों की  
पैकिंग के लिए टिन या प्लास्टिक सामग्री पर भी  
लागू होगी।
- (ग) प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों को सीमा शुल्क से छूट  
होगी।
- (घ) अनुपयुक्त आयातित सामग्री जैसे की खालें एवं  
चमड़ा और नम नीला चमड़ा का पुनर्निर्यात अनुमेय  
है।
- (ड.) लीनिंग और इन्टरलीनिंग सामग्री सीमा शुल्क  
अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 01-03-2003 की  
क्रम सं. 168 पर अधिसूचित सीवीडी की छूट होगी।
- (च) आई टी सी (एचएस) के अध्याय 43 के अधीन  
आने वाले कच्चा, टैन्ड और ड्रेस रोम और चमड़े पर  
सीवीडी की छूट होगी।

समुद्री क्षेत्र के लिए  
पैकेज

(क) विनिर्दिष्ट खास निविष्टियों रसायनों और संगंधित तेलों आदि का शुल्क मुक्त आयात पिछले वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर अनुमत होगा ।

(ख) टूना फिशिंग के लिए मोनोफिलामेंट लांग लाइन तंत्र के आयात को शुल्क की रियायती दरों पर अनुमत करना

(ग) विनिर्दिष्ट अपशिष्ट मानदण्डों को शर्तों के साथ समुद्री खाद्य अपशिष्ट की निकासी हेतु स्व-नकार प्रक्रिया लागू करना ।

प्रगति मैदान के  
लिए इष्टतम  
विकास कार्यक्रम

1ख.2 हमारी औद्योगिक और व्यापारिक उपलब्धियों का अधिकतम लाभ उठाने और मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से जगह और सेवाओं में वृद्धि के लिए प्रगति मैदान को एक विश्वस्तर का काम्पलेक्स बनाया जाएगा जो आगन्तुकों के अंतःप्रवेश और बहिर्गमन के अनुकूल होगा। काम्पलेक्स की उपलब्ध सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, इन्हें बढ़ाया जाएगा और इन्हें वैविध्य प्रदान किया जाएगा । वहाँ एक अत्यंत आधुनिक, “ स्टेट आफ द आर्टे” पर्यावरण नियंत्रित, वातानुकूलित प्रदर्शनी क्षेत्र और स्थाई प्रदर्शनी माटर्स होंगे । इसके अलावा, दस हजार शिष्टमंडलों के लिए एक बड़ा सम्मेलन केन्द्र विकसित किया जाएगा जिसमें बहुउद्देशीय और परिवर्तनीय हाल, जिनमें उच्च तकनीकी उपकरण लगे होंगे । पूरे वर्ष चलने वाले खाद्य एवं पेय रेस्त्राओं को विकसित किया जाएगा जिसमें विभिन्न किस्म और सस्ते-मंहगे सभी प्रकार के पकवानों के बेचने के लिए बहुत सी दुकानें होंगी । प्रगति मैदान के अहाते में नौ हजार से अधिक वाहनों को पार्क करने के लिए एक बहुस्तरीय पार्किंग स्थल होगा।

अध्याय - एक (ग)व्यापार बोर्ड

## व्यापार उद्योग बोर्ड

- 1.ग.1 विदेश व्यापार नीति से संबंधित मामलों में सरकार के सलाह देने के लिए व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा तथा इसे स्पष्ट और सक्रिय भूमिका दी जाएगी वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने व भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार बोर्ड तथा सरकार के बीच लगातार पारस्परिक क्रिया होगी ।

## विचारणीय विषय

- 1.ग.2 व्यापार बोर्ड के निम्नलिखित विचारणीय विषय होंगे :-

- 1) बदलते हुए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में निर्यात को बढ़ाने के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजना बनाने तथा इसे क्रियान्वित करने में सरकार को सलाह देना
- 2) विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन की समीक्षा, नियंत्रण की पहचान तथा निर्यात अग्रिम को सर्वोत्तम करने के लिए औद्योगिक सुस्पष्ट उपाय सुझाना ।
- 3) आयात व निर्यात के वर्तमान संस्थागत फ्रेमवर्क की जाँच करना तथा वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सरल और कारगर व्यावहारिक उपाय सुझाना
- 4) आयात निर्यात के नीति दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं को जाँच करना तथा ऐसी योजनाओं में एकरूपता तथा चैनलाईज करने के लिए उपाय सुझाना
- 5) भारत के विदेश व्यापार के संवर्धन से संबंधित मामलों की जाँच करना तथा देश के सामान व सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मजबूत करना ।
- 6) उपर्युक्त लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए अध्ययन करना ।

- |                |   |
|----------------|---|
| संयोजन         | 1.ग.3 सरकार व्यापार नीति में विशेषज्ञ अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति को व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी । सरकार अन्य 25 व्यक्तियों को भी नामित करेगी जिनमें 10 व्यक्ति व्यापार नीति में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे । इसके अलावा मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन तथा पदेन सदस्यों को राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ कामर्स का अध्यक्ष अथवा महासचिव नियुक्त करेगी । |
| बैठकें         | 1.ग.4 बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाएगी तथा रखे गए मुद्दों की मदों के सन्दर्भ में बोर्ड सरकार को सिफरिश को भेजेगा ।  |
| उप समिति       | 1.ग.5 व्यापार बोर्ड को सह-समिति बनाने का अधिकार होगा और विशेष क्षेत्रों तथा उद्देश्यों पर सिफारिशों को बनाने के लिए विशेषज्ञों को कार्यरत करने का अधिकार होगा।  |
| सचिवालय और बजट | 1.ग.6 व्यापार बोर्ड का एक सचिवालय और बजट शीर्ष होगा तथा इसकी सेवाएँ वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत आएंगी ।   |



## अध्याय - दो

निर्यात एवं आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

- |  |     |   |
|--|-----|---|
| आयात और निर्यात मुक्त जब तक कि विनियमित न हो | 2.1 | निर्यात और आयात उन मामलों को छोड़कर जहाँ वे इस नीति के प्रावधानों अथवा तत्समय लागू अन्य कानूनों द्वारा विनियमित होते हैं, मुक्त होंगे। मदवार निर्यात और आयात नीति, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित “आई टी सी(एच एस)” में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।   |
| कानून का अनुपालन                             | 2.2 | प्रत्येक निर्यातक या आयातक को, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों, इस नीति के प्रावधानों तथा उसको दिए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति या उसे प्रदान अनुमति की शर्तों और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। सभी आयातित माल भी देशी उत्पादित माल पर यथा लागू स्वदेशी कानूनों, नियमों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण और सुरक्षा मानदण्डों के अधीन होंगे। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत आवश्यक किम्बरलै प्रोसेस (के पी) प्रमाण-पत्र जब तक पोतलदान पार्सल के साथ संलग्न न हो, अनगढ़े हीरों का आयात अथवा निर्यात अनुमत नहीं होगा। |
| नीति की व्याख्या                             | 2.3 | आई टी सी(एच एस), प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), अथवा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) अथवा डी ई पी बी दर की अनुसूची में किसी मद के वर्गीकरण, के संबंध में या इस नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के बारे में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न अथवा शंका उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रश्न अथवा शंका को महानिदेशक, विदेश व्यापार को भेजा जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।  |

किसी लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति के नीति अनुसार जारी होने के विषय में कोई शंका या प्रश्न उठने पर अथवा ऐसे दस्तावेजों की आवश्यकता और अंश पर किसी प्रश्न अथवा शंका के उठने पर उन दस्तावेजों को महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

प्रक्रिया

2.4 महानिदेशक, विदेश व्यापार किसी एक मामले में अथवा मामलों की श्रेणी में किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाने हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने आदेशों तथा इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1), प्रक्रिया पुस्तक (भाग-2), डी ई पी बी दर की अनुसूची और आई.टी.सी. (एच एस) में सम्मिलित होगी तथा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित होगी। ऐसी प्रक्रियाओं को, इसी प्रकार, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) विदेश व्यापार नीति की अनुपूरक है तथा इसमें सम्बद्ध प्रक्रियाओं और अन्य व्यौरों का उल्लेख है। नीति की विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध लाभों को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।

नीति/प्रक्रिया से छूट

2.5 इस नीति अथवा किसी प्रक्रिया के प्रावधानों में ढील प्राप्त करने के लिए इस आधार पर किया गया अनुरोध कि आवेदक को वास्तव में कठिनाई है अथवा नीति या प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने पर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो उसे आवश्यक छूट के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार के पास भेजा जा सकता है। उस पर महानिदेशक ऐसा आदेश या ऐसी छूट या राहत जैसा भी उचित या समुचित हो, दे सकते हैं।

महानिदेशक, विदेश व्यापार लोकहित में किसी भी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी को इस नीति के किसी प्रावधान से या किसी प्रक्रिया से छूट दे सकते हैं या ऐसी छूट देते समय वह ऐसी शर्तें लगा सकते हैं जैसा कि वह उचित समझे। यदि वह अनुरोध नीति/प्रक्रिया के अध्याय-4 (रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित किसी प्रावधान को छोड़कर) के प्रावधानों के बारे में हो तो ऐसे अनुरोधों पर केवल अग्रिम लाइसेंसिंग समिति से सलाह लेकर यदि अनुरोध नीति/प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय-5 के प्रावधान के सम्बन्ध में है तो ई पी सी जी समिति से सलाह लेकर ही विचार किया जाए। तथापि अध्याय-4, अध्याय-5 और रत्न और आभूषण क्षेत्र से भिन्न प्रावधानों के संबंधों में ऐसे किसी अनुरोध पर केवल नीति छूट समिति की सलाह लेने के बाद ही विचार किया जाएगा।

प्रतिबंध के सिद्धान्त	2.6	विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु कोई भी आवश्यक उपाय अपनाया और लागू किया जा सकता :-  (1) सार्वजनिक आचरण का संरक्षण (2) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण (3) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कापीराइट का संरक्षण और भ्रामक कृत्यों की रोकथाम । (4) कारागार श्रमिकों के प्रयोग की रोकथाम (5) कला, इतिहास अथवा पुरातत्व मूल्य की राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण। (6) सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण । (7) विखंडनीय सामग्री अथवा जिससे वह प्राप्त की गई है, के व्यापार का संरक्षण, और (8) हथियारों, गोला-बारुद और युद्ध के साज-सामान के व्यापार की रोकथाम
* प्रतिबंधित माल	2.7	कोई भी माल जिसका आई टी सी (एच एस) के अधीन निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित किया गया है, उसका इस संबंध में जारी किए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति या सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा ।
लाइसेंस/प्रमाण पत्र/ अनुमति की शर्तें	2.8	प्रत्येक लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति विनिर्दिष्ट वैधता अवधि के लिए वैध होगा तथा लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति में दी गई शर्तें, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :- 1. माल की मात्रा, विवरण एवं मूल्य, 2. वास्तविक प्रयोक्ता शर्त, 3. निर्यात दायित्व, 4. प्राप्त किया जाने वाला मूल्य संवर्धन, 5. न्यूनतम निर्यात मूल्य
लाइसेंस/प्रमाणपत्र/ अनुमति अधिकार नहीं	2.9	कोई भी व्यक्ति लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति को अधिकार से नहीं ले सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या लाइसेंसिंग प्राधिकारी को, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र देने से इंकार करने या नवीकरण नहीं करने का अधिकार होगा।

- जुर्माना 2.10 यदि लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति धारक लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे इस नीति के तहत बनाए गए अधिनियम, नियमों और आदेशों तथा उस समय लागू किसी अन्य नियम के अनुसार दंडित किया जा सकता है।
- राज्य व्यापार 2.11 कोई माल, जिसके आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आई टी सी(एच एस) नामक पुस्तक में यथा- विनिर्दिष्ट अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि वह उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो। तथापि विदेश व्यापार महानिदेशक, इनमें से किसी माल के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति दे सकता है।
- ऐसे माल के सम्बन्ध में, जिसके लिए राज्य व्यापार उद्यमों को विशेषाधिकार मंजूर किया गया हो, अथवा विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कीमत, गुणवत्ता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय-विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी कोई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है जिसमें आयात और निर्यात शामिल हैं। ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद और विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे।
- आयातक-निर्यातक कोड संख्या 2.12 जब तक विशेष छूट नहीं दी जाती किसी भी व्यक्ति द्वारा आयातक-निर्यातक कोड नम्बर (आई ई सी) के बिना किसी माल का निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा। आयातक-निर्यातक कोड नम्बर, प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के आधार पर मंजूर किया जायेगा।
- पड़ोसी देशों के साथ व्यापार 2.13 महानिदेशक विदेश व्यापार समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा ऐसी योजनाएं बना सकते हैं जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों।

- माल लाने-ले-जाने की सुविधा 2.14 भारत के पड़ोसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच हुई द्विपक्षीय संधियों के अनुसार विनियमित होगी तथा अन्तराष्ट्रीय समझौतों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन होगी ।
- ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार 2.15 ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार समय-समय पर आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीमें बना सकते हैं जो अपेक्षित हों तथा इस नीति में दिया गया कुछ भी जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरूप नहीं है, लागू नहीं होगा ।
- वास्तविक प्रयोक्ता शर्त 2.16 पूंजीगत माल, कच्चा माल, मध्यस्थ, संघटक, उपभोज्य पदार्थ, अतिरिक्त पुर्जे, हिस्से पुर्जे उपसाधित्र यंत्र और अन्य सामान जिनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है । तथापि, यदि इनके आयात के लिए लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र की जरूरत हों, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है बशर्ते कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यह शर्त समाप्त न कर दी गई हो।
- पुरानी वस्तुएं 2.17 सभी पुरानी वस्तुएं आयात हेतु प्रतिबंधित होंगी तथा उन्हें इस नीति के प्रावधानों, आई टी सी(एच एस), प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), सार्वजनिक सूचना या इस संबंध में जारी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के अनुसार उनका आयात किया जा सकता है।
- पुरानी वस्तुएं जिसमें रिफरबिशड/रिकंडीशंड स्पेयर्स भी शामिल है, के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है ।
- नमूनों का आयात 2.18 नमूनों का आयात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।
- उपहारों का आयात 2.19 इस नीति के अधीन जहां ऐसा माल अन्यथा मुक्त रूप से आयात किया जा सकता हो, उपहारों के आयात की अनुमति होगी । अन्य मामलों में सीमाशुल्क निकासी(सी सी पी) की अनुमति महानिदेशक, विदेश व्यापार से प्राप्त करनी होगी।
- यात्री असबाब 2.20 वस्तुतः घरेलू वस्तुओं और निजी प्रयोग की वस्तुओं को यात्री के निजी सामान की सीमा के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा

अधिसूचित असबाब नियमों में उनकी शर्तों के अनुसार आयात किया जा सकता है।

ऐसी मदों के नमूने जो अन्यथा इस नीति के अधीन मुक्त रूप से आयात योग्य हैं, का भी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना वैयक्तिक असबाब के रूप में आयात किया जा सकता है।

विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना, अपने वैयक्तिक असबाब के रूप में, उनके पास आए विशिष्ट निर्यात आर्डरों के लिए अपेक्षित ड्राइंग, पैटर्न्स, लैबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्ट्स, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंट्स का आयात करने की अनुमति है।

- |   |      |  |
|---|------|--|
| निर्यात आधार पर आयात                            | 2.21 | नया अथवा पुराना पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, हिस्से एवं उपकरणों, कंटेनर जो निर्यात हेतु माल के पैकिंग के लिए हों उनका सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विधिक बचनबद्धता/बैंक गारंटी के निष्पादन पर किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है। बशर्ते कि मद को बिना किसी शर्त/लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता के मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता हो जैसा कि आई टी सी (एच एस) अनुसूची-2 के अन्तर्गत अपेक्षित है। |
| विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात     | 2.22 | आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर पूंजीगत माल, उपकरण संघटक अतिरिक्त पुर्जे, अनुसंगी चाहे आयातित हो या स्वदेशी, उनकी मरम्मत, परीक्षण गुणवत्ता सुधार या टेक्नोलौजी में सुधार अथवा मानकीकरण के लिए किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना विदेश भेजा जा सकता है और उनका पुनः आयात किया जा सकता है।   |
| विदेश में परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात | 2.23 | विदेश में परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया गया हो।  |
| खुले समुद्र में बिक्री                          | 2.24 | भारत में आयात हेतु समुद्र में वस्तुओं की बिक्री इस नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है।   |

- पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन आयात 2.25 पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन नई पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं है ।
- सीमाशुल्क से माल की निकासी 2.26 वह माल जो पहले ही आयातित/पोतलदान/पहुंच गया हो लेकिन सीमाशुल्क से उसकी निकासी न हुई हो उस माल को बाद में जारी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति के प्रति निकासी की जा सकती है ।
- बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन 2.27 जहाँ कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहाँ कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहाँ आयातक को सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास यथानिर्धारित तरीके से एक विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन करना होगा। स्वदेशी प्राप्ति पत्र/अनुमति धारक को स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/नामजद अधिकरणों से माल प्राप्त करने से पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को प्रस्तुत करना होगा।
- बैंक गारंटी से छूट 2.27.1 इस नीति के तहत उन सभी निर्यातकों, जिनका कारोबार चालू वित्तीय वर्ष तथा उससे पहले लाइसेंसिंग वर्ष में न्यूनतम 5 करोड़ का रहा तथा जिसके निर्यातों का तीन वर्षों का रिकार्ड अच्छा हो, को बैंक गारंटी के निष्पादन से मुक्त किया गया है तथा वे उस नीति की किसी भी योजना के तहत बैंक गारंटी के बदले विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत कर सकते हैं ।
- आयात के लिए निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम 2.28 राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं।
- कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मदों, हथियार और गोला-बारूद तथा खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों में रख सकता है ।
- ऐसी वस्तुओं की इस नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरूरी हो, लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमतिपत्र के प्रति घरेलू खपत के लिए निकासी की जा सकता है।
- ऐसे माल पर निकासी के साथ यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान किया जाएगा।

एक वर्ष की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि में, जिसकी अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, यदि घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी नहीं की जाती तो इनका आयातक इन वस्तुओं का पुनः निर्यात कर सकता है।

- |                             |      |   |
|-----------------------------|------|---|
| मुक्त निर्यात               | 2.29 | आयात और निर्यात की आई.टी.सी(एच एस) या इस नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकेगा।   |
|                             |      | तथापि, महानिदेशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आई टी सी (एच एस) में शामिल न की गई किसी वस्तु का लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना निर्यात किया जा सकता है।  |
| नमूनों का निर्यात           | 2.30 | नमूनों और निःशुल्क वस्तुओं का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।  |
| यात्री असबाब का निर्यात     | 2.31 | बाहर जाने वाले भारतीय यात्रियों के वस्तुतः निजी समान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर ले जाने की अनुमति है। तथापि, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित तौर पर उल्लिखित मदों के लिए लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/ अनुमति लेना जरूरी होगा। |
| उपहारों का निर्यात          | 2.32 | किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में खाद्य मदों सहित 5,00,000/- रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरूप किया जा सकेगा।<br>तथापि, निर्यात की आई टी सी(एच एस) में निषेधात्मक सूची की मदों को उपहार के तौर पर बिना लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/ अनुमति के निर्यात नहीं किया जा सकता।                                       |
| अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात | 2.33 | आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित मदों के अलावा संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, आटोमोबाइल अथवा किसी अन्य माल के स्वदेशी अथवा आयातित वारण्टी अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात ऐसे माल की वारण्टी अवधि के भीतर मुख्य उपस्कर के साथ या बाद में, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के मद्दे निर्यात किया जा सकता है।              |



- तीसरा पक्ष निर्यात 2.34 नीति के अध्याय 9 में यथापरिभाषित अनुसार तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात की अनुमति होगी।
- आयातित वस्तुओं का निर्यात 2.35 इस नीति के अनुसार आयातित माल का बिना किसी लाइसेंस प्रमाण-पत्र/अनुमति के उसी रूप में या वास्तव में उसी रूप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते आयात या निर्यात की जाने वाली मद विशेष आयात लाइसेंस या निर्यात की निषेधात्मक सूची के अन्तर्गत आयातित मदों को छोड़कर आई टी सी (एच एस) में आयात की प्रतिबंधात्मक सूची या निर्यात की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो।  
मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति आयातित ऐसी वस्तुओं के निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति अनुमत होंगे।
- 2.36 आई टी सी(एच एस) में निर्यात अथवा आयात की प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित मदों (निषिद्ध मदों को छोड़कर) का आयात सीमाशुल्क बॉण्ड के तहत मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना किया जा सकता है बशर्ते कि मद को बिना किसी शर्त/लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता के मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता हो जैसा कि आई टी सी (एच एस) अनुसूची-2 के अन्तर्गत अपेक्षित है।
- प्रतिस्थापन माल का निर्यात 2.37 निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये जाएं तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निकासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकेगी, बशर्ते कि प्रतिस्थापन माल आई टी सी (एच एस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित न हो।
- मरम्मत किए गए सामान का निर्यात 2.38 निर्यात करते समय आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे या अन्यथा उपयोग के लिए अयोग्य पाये जायें तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे सामान को लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना और समय-समय पर इस संबंध में जारी सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी।

- निर्यात के लिए निजी  
वाण्डेड गोदाम
- 2.39 राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डी टी ए में निजी वाण्डेड गोदाम की स्थापना की जाए।  
ऐसे गोदाम सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना स्वदेशी विनिर्माताओं से माल खरीदने के पात्र होंगे। अधिसूचित गोदामों को स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा की गई आपूर्ति को वास्तविक निर्यात माना जाएगा बशर्ते की उसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।
- निर्यात संविदाओं का  
कोटिकरण
- 2.40 सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा के वर्ग में रखा जाएगा परन्तु निर्यात प्राप्तियां मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी।  
तथापि विशेष निर्यातों के प्रति निर्यात प्राप्तियाँ रुपयों में भी वसूल की जा सकती है बशर्ते कि यह ए सी यू के सदस्य देश या नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित अप्रवासी बैंक के मुक्त रुप से परिवर्तनीय बोस्ट्रो खाने के जरिए हों। इसके साथ वोस्ट्रो खाने के जरिए रुपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाने में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के प्रति हो। इस कारोबार के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक (बैंक सेवा प्रभार को घटाने के बाद) दी गई मुक्त विदेशी मुद्रा इस नीति की निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात वसूली के रुप में मानी जाएगी।  
जिन संविदाओं के लिए भुगतान एशियन क्लयरिंग यूनियन (ए सी यू) के जरिए किए जाएंगे उन्हें ए सी यू डालर के वर्ग में रखा जाएगा। केन्द्रीय सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक्जिम बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के प्रति निर्यात ठेके और बीजक भारतीय रुपयों में किए जा सकते हैं।
- निर्यात प्राप्तियाँ की  
वसूली
- 2.41 यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके विरुद्ध अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों और नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

- निर्यात वस्तुओं की मुक्त आवाजाही 2.42 किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अभिकरण द्वारा निर्यात हेतु अनुमत मदों की खेप को किसी भी कारण से रोका/बिलम्बित नहीं किया जाएगा। किसी भी संदेह की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी, निर्यातक से त्वचनबद्धता की मांग कर सकता है।
- स्टॉक को जब्त न करना 2.42.1 किसी भी अभिकरण द्वारा स्टॉक को जब्त नहीं किया जायेगा ताकि विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों और निर्यात वस्तुओं की सुपुर्दगी की तारीख में बाधा न डाली जा सके। कुछ खास मामलों में, संबंधित अधिकरण प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर स्टॉक को जब्त कर सकती है। तथापि, इस प्रकार जब्त किए गए माल को 7 दिन के भीतर छोड़ना होगा।
- निर्यात संवर्धन परिषद 2.43 निर्यात संवर्धन परिषदों का मूल उद्देश्य देश के निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें वृद्धि करना है। प्रत्येक परिषद विशेष वर्ग के उत्पाद परियोजनाओं और सेवाओं के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची तथा उनका मुख्य कार्य प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।
- पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र 2.44 कोई भी व्यक्ति जो आयात निर्यात के लिए (1) लाइसेंस/प्रमाण पत्र/ अनुमति पत्र (आई टी सी(एच एस) में सूचीबद्ध/प्रतिबंधित मदों के अतिरिक्त) (2) किसी अन्य लाभ या इस नीति के अन्तर्गत किसी अन्य छूट के लिए आवेदन करता है तो उसको प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा बशर्ते कि इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उसे छूट न दी गई हो।
- 2.45 हटा दिया गया है।
- ई डी आई पहल के जरिये व्यापार सुविधा 2.45.1 विदेश व्यापार महानिदेशालय की कोशिश अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को अमल में लाते हुए व्यापार दस्तावेजों के अधिकतम सरलीकरण, मानकीकरण और सामंजस्य प्राप्त करने के लिए काम करना है। इस दिशा में विदेश व्यापार महानिदेशालय दस्तावेजों को इलेक्ट्रानिक रूप से दर्ज करने, उन्हें पुनः प्राप्त करने और दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की ओर कदम बढ़ा रहा है जो सीमाशुल्क और बैंकों सहित अन्य समुदाय के साथ संदेश के आदान प्रदान और सहमत प्रोटोकाल पर आधारित है।

- डी जी सी आई और एस वाणिज्यिक व्यापार डाटा 2.45.2 प्रयोक्ताओं को पेशेवर ढंग से वाणिज्यिक निर्णय लेने के योग्य बनाने हेतु, डी जी सी आई और एस व्यापार डाटा को व्यवसायिक दृष्टिकोण से संरचना के प्रारूप पर आधारित न्यूनतम समय अन्तराल वाले अनुयोग उपलब्ध किए जाएंगे ।
- ई डी आई पहल अनुकूलन के उन्नयन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन 2.45.3 सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन के दृष्टिकोण से, विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रयोक्ता समुदाय को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा । ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक में वर्णित है ।
- निपटान आयोग के जरिए निर्यात दायित्व चूक का विनियमीकरण और सीमाशुल्क और ब्याज का निपटान 2.46 ऐसी फर्मों को सहायता प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने ऐसे कारणों जो कि उनके नियंत्रण में नहीं थे, के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत भुगतान नहीं किए हैं और कमजोर इकाईयों के विलयन, अर्जन और पुर्नवास को सरल बनाने के लिए 0.1.04.2005 से ऐसे मामलों का निर्णय लेने के लिए उत्पाद एवं सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड में निपटान आयोग बनाने को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है ।
- 2.47 हटा दिया गया है ।
- सेवा कर से छूट 2.48 निर्यातित माल या सेवाओं के संबंध में, यदि माल और सेवाएं सेवा कर के अधीन है, तो यह छूट प्राप्त होगी ।
- डी टी ए में सेवा कर की वापसी 2.48.1 सभी माल और सेवाओं पर, जो घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटों से तथा ई ओ ये/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निर्यात की गयी है, लगाए गए सेवा कर से छूट की अनुमति दी जाएगी ।
- एस ई जेड में सेवा कर से छूट 2.48.2 एस ई जेड में यूनिटों को सेवा कर से छूट दी जाएगी ।

### शिकायत निवारण

- निर्यात/आयात के सुविधा प्रदान कर्ता के रूप में विदेश व्यापार महानिदेशालय 2.49 विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातों और आयातों के सुविधाकारक के रूप में कार्य करने को वचनबद्ध है । हमारा केन्द्र बिन्दु सही संचालन पर है जो कि स्पष्ट, पारदर्शी और उत्तरदायी निकासी प्रणालियों पर निर्भर करता है ।

सिटिजन चार्टर

2.49.1 विदेश व्यापार महानिदेशालय का एक सिटीजन चार्टर है जिसमें कि आयातकों और निर्यातकों के प्रति इसकी बचनबद्धता दर्शाई गई है। इसमें ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए समय सूची भी दी गई है और विभिन्न स्तरों पर शिकायत समितियों के विवरण दिए गए हैं।

शिकायत निवारण प्रणाली

2.49.2 नीति और प्रक्रिया से संबंधित व्यापार और उद्योग की शिकायतों के तीव्र सुधार को आसान बनाने लिए सरकारी संकल्प द्वारा एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित की गई है।

सरकार देरी को माफ करने वास्तविक मामलों में निर्यातकों द्वारा उलंघन को विनियमित करने, हकदारी पर उठे विवाद को सुलझाने, लाइसेंसों के प्रयोग हेतु विस्तार की स्वीकृति आदि के लिए 27.10.2004 स्थापित शिकायत निवारण समिति के माध्यम से पिछली नीति से सम्बन्धित सभी शेष समस्याओं और विवादों को समाधान करने के लिए बचनबद्ध है।

2.49.3 हटा दिया गया है।

## अध्याय - तीन

### संवर्धनात्मक उपाय

निर्यातों के मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई)

- 3.1 राज्य सरकारों को अपने राज्यों हेतु निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु वाणिज्य विभाग ने एक योजना बनाई है जिसको ए0एस0आई0डी0ई0 कहा जाता है।

राज्यों को राशि आबंटित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने वार्षिक योजना में सकल निर्यात तथा निर्यात में बढ़ोत्तरी के दर के दोहरे मानक के आधार पर उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।

राज्य इस राशि को मूलभूत ढाँचे के विकास हेतु उपयोग करेगा जैसे कि उत्पादन केंद्रों को पत्तनों के साथ जोड़ने के लिए सड़के बनाना, इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो और कन्टेनर फ्रेट स्टेशन को स्थापित करना, नए राज्य स्तर के निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों/जोनों की संरचना और मौजूदा जोनों में सामान्य सुविधाओं को बढ़ाना, मूलभूत ढाँचे की परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी, लघु पत्तनों और घाटों का विकास, सामान्य बहिस्त्राव संशोधन सुविधाओं की स्थापना में सहायता, ऊर्जा आपूर्ति का स्थायीकरण करना तथा वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किन्हीं अन्य गतिविधियों में भाग लेना।

बाजार पहुँच की पहल (एमएआई)

- 3.2 बाजार पहुँच की पहल (एमएआई) योजना मध्यम स्तर के निर्यात संवर्धन प्रयत्नों के लिए है जिसमें देशों तथा उत्पाद पर सुस्पष्ट केन्द्र बिन्दु होगा।

वित्तीय सहायता निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग और व्यापार एसोसियेशनों, राज्य सरकार की एजेंसियों, विदेशों में भारतीय वाणिज्यिक मिशनों तथा अन्य पात्र हस्तियों, जिनको समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, के लिए उपलब्ध है।

एम.ए.आई. योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है, जिसमें बाजार का अध्ययन, शो रूम/गोदाम सुविधाएँ स्थापित करना, बिक्री संवर्धन मुहिम, अन्तर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रचार मुहिम, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में हिस्सा, बाण्ड प्रमोशन, भेषजीय उत्पादन पंजीकरण प्रभार

तथा इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए परीक्षण प्रभार भी शामिल है। इनमें से प्रत्येक निर्यात संवर्धन गतिविधियों को सरकार से उनके कुल लागत के 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उनकी गतिविधियों और कार्यान्वयन एजेन्सी के आधार पर दिया जा सकता है, जैसा कि विस्तृत दिशानिर्देशों में उल्लिखित है। मार्गदर्शन का पूरा विवरण <http://commerce.nic.in> में देखा जा सकता है।

विपणन विकास 3.2.1 निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग और व्यापार एसोसियेशनों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न निर्यात संवर्धन गतिविधियों को वित्तीय सहायता पहुँचाने के लिए विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना बनाई गई है।

संशोधित एमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल, 2004 से उन निर्यातकों को एमडीए सहायता उपलब्ध है जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रु० है।

इसमें व्यापार मेलों, विदेशों या भारत में क्रेताओं और विक्रेताओं के सम्मेलन में भागीदारी, व्यापार संवर्धन सेमिनार भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त उन निर्यातकों को जो कि चार केन्द्र बिन्दु क्षेत्र जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सीआईएस क्षेत्र, एएसईएन देश, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में से किसी एक में यात्रा करते हैं, उनको यात्रा अनुदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागदारी के लिए सहायता उपलब्ध है।

अन्य क्षेत्रों में व्यापार मेलों इत्यादि में शामिल होने के लिए बिना यात्रा अनुदान के वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

व्यापार संबंधित मामलों हेतु विधिक खर्चों को चुकाना 3.2.1 निर्यात संवर्धन परिषदों की अनुशंसा पर योग्य निर्यातकों को व्यापार संवर्धित मामले में मुकदमें पर खर्च को चुकाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

उत्कृष्ट निर्यात के शहर 3.3 कुछ विशिष्ट भौगोलिक स्थलों में अनेक शहर अच्छे खासे औद्योगिक स्थापना स्थलों के रूप में उभरे हैं जो भारत के निर्यात में पर्याप्त योगदान देते हैं। इन औद्योगिक क्लस्टर मदों को मान्यता देना आवश्यक हो गया है ताकि उनकी क्षमता को अधिकतम किया जा सके और उच्च मूल्य बाजार में जाने के लिए उनका दर्जा बढ़ाने में सहायता की जा सके।

1000 करोड़ या उससे अधिक निर्यात करने वाले कुछ चुने हुए शहरों को उनकी निर्यात क्षमता के आधार पर उत्कृष्ट निर्यात के शहर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तथापि हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि व मत्स्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट निर्यात के शहर के लिए यह सीमा 250 करोड़ रुपया होगी।

इन क्षेत्रों में साधारण सेवा प्रदायक ईपीसीजी योजना की सुविधा के हकदार होंगे।

यूनिटों के मान्यता प्राप्त एसोसिएशन, केन्द्रित तकनीकी सेवाओं की संरचना हेतु बाजार पहुँच में पहल योजना के अन्तर्गत निधि पर प्राप्त कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र एसआईडीई योजना से अभिन्न महत्वपूर्ण मूलभूत संरचना के अन्तराल को पहचानने हेतु प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्राप्त करेंगे।  
उत्कृष्ट निर्यात के अधिसूचित कस्बे परिशिष्ट 7 में दिए गए हैं।

ब्रांड संवर्धन तथा 3.4.1 भारत सरकार की नीति यह है कि वह विनिर्माताओं और गुणवत्ता निर्यातकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करे कि वे अपने-अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता के मानदण्डों को प्राप्त करें। केन्द्रीय सरकार गुणवत्ता जागरूकता पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने और कुल गुणवत्ता प्रबंध के विचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और व्यापार संस्थाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करेगी।

परीक्षण गृह 3.4.2 केन्द्रीय सरकार परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर के स्तर का बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण और उन्नयन में सहायता करेगी।

गुणवत्ता संबंधी 3.4.3 विदेशी क्रेताओं से प्राप्त हुई गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की जांच शिकायतें/ विवाद विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित गुणवत्ता शिकायतों की क्षेत्रीय उप-समिति (आर एस सी क्यू सी) द्वारा की जाएगी। विशेषतः गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु और सामान्यतः ऐसी अन्य शिकायतों के संबंध में, दिशा-निर्देश प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-16 में दिए गए हैं।



व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले व्यापारिक विवाद 3.4.4 यदि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में यह बात आती है अथवा उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि कोई निर्यात अथवा आयात इस तरीके से किया गया है, जो

(i) किसी बाहरी देश के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए हानिकारक हो,

(ii) निर्यात अथवा आयात में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रति हानिकर हो;

(iii) जिससे देश की बदनामी हुई हो,

तो ऐसी स्थिति में विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित निर्यातक अथवा आयातक के विरुद्ध अधिनियम, इसके अधीन बने नियमों तथा आदेशों और इस नीति के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं ।

### 3.5 स्टार व्यापार सदन

स्टार व्यापार सदन 3.5.1 व्यापारी और विनिर्माता निर्यातक, सेवा प्रदायक, निर्यातोन्मुखी एकक (ई ओ यू)/विशेष आर्थिक जौन (एस ई जेड), कृषि निर्यात जौन (ए ई जेड) में स्थित यूनितें, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनॉलॉजी पार्क (ई एच टी पी), साफ्टवेयर तकनॉलॉजी पार्क (एस टी पी) और जैव तकनालाजी पार्क (बी टी पी) स्टार निर्यात सदन स्तर के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे ।

स्तर श्रेणी 3.5.2 आवेदक की श्रेणी का निर्धारण चालू तथा पिछले तीन वर्षों की कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/एफओआर निर्यात निष्पादन पर निर्भर करेगा।

#### श्रेणी

#### निष्पादन (रुपयों में)

एक स्टार निर्यात सदन	15 करोड़
दो स्टार निर्यात सदन	100 करोड़
तीन स्टार निर्यात सदन	500 करोड़
चार स्टार निर्यात सदन	1500 करोड़
पाँच स्टार निर्यात सदन	5000 करोड़

#### टिप्पणी :-

1. लघु उद्योग/अति लघु क्षेत्र/कुटीर क्षेत्र, के वी आई सी/के वी आई वी के साथ पंजीकृत यूनिट, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यूनिट, हस्तकरघा, हस्त शिल्प, हाथ

से बुना कालीन, रेशम के कालीन निर्यात करने वाले यूनिट तथा परिशिष्ट-9 में यथा सूचीबद्ध लेटिन अमेरिका/सी आई एस/उप सहारन अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातक, आई एस ओ 9000 (श्रृंखला) वाले यूनिट/आईएसओ 14000 (श्रृंखला) स्तर वाले/ डब्ल्यूएचओजीएमपी/ एचएसी सीपी/एसईआईसीएमएम स्तर-2 तथा उच्च स्तर प्राप्त एजेंसियां जो परिशिष्ट 6क में सूचीबद्ध की गई हैं। सेवा और कृषि उत्पादों के निर्यात, स्टार निर्यात सदन स्तर की स्वीकृति हेतु, निर्यात के दोहरे वरीयता के पात्र होंगे। यह लाभ केवल विनिर्माता निर्यातकों को ही उपलब्ध होगा।

2. पुनः निर्यात आधार पर किए गए निर्यात की गणना मान्यता प्रदान करने के लिए नहीं की जाएगी।

3. मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी लिमिटेड कम्पनी की सहायक कम्पनी द्वारा किये गये निर्यात को लिमिटेड कम्पनी के निर्यात निष्पादन में गिना जाएगा। इस प्रयोजन के लिए कम्पनी के सहायक कम्पनी में अधिकतर शेयर होने चाहिए।

4. जहाँ कहीं मान्यता के लाभ का दावा, चालू वर्ष के कारोबार के आधार पर किया गया है, इस पर अभी विचार किया जाएगा जब निर्यातक ने पिछले तीन वर्षों में भी निर्यात किया है।

विशेषाधिकार

3.521 एक स्टार निर्यात सदन निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार होंगे:-

(i) स्व-घोषणा आधार पर आयात और निर्यात दोनों के लिए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति और सीमाशुल्क निकासी।

(ii) तरजीह पर निवेश-उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण 60 दिन के भीतर

(iii) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों के अनिवार्य लेन-देन से छूट, तथापि बैंकिंग चैनलों से रुपया भेजना जारी रहेगा।

(iv) ई ई एफ सी खाते में विदेशी मुद्रा का 100 प्रतिशत रखना होगा,

(v) सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से 360 दिन तक करना।

(vi) लक्ष्यो परियोजना (टारगेट प्लस स्कीम) के अधीन स्वीकृति के लिए हकदार होगा।

(vii) इस नीति के अधीन योजनाओं में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की छूट होगी।

वैधता अवधि

3.5.3 1.9.2002 को या उससे बाद जारी अथवा नवीकृत सभी स्तर प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से वैध होंगे। इस अवधि के दौरान आवेदक जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, 31.3.2009 तक ऐसी मान्यता की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है।

ऐसे प्रमाण-पत्र की समाप्ति पर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा-निर्धारित अवधि के भीतर स्तर प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन देना आवश्यक होगा। उक्त अवधि के दौरान स्तर-धारक आम सुविधाओं और लाभों के लिए दावा करने का हकदार होगा।

3.6 सेवाओं का निर्यात

सेवा निर्यात

3.6.1 सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के तहत आने वाली सभी 161 व्यापार योग्य सेवाएं शामिल हैं। यहाँ ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान को मुक्त विदेशी मुद्रा में लिया जाएगा। सेवाओं की सूची प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट - 10 में दी गई हैं। नीति के सभी प्रावधान जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, आवश्यक परिवर्तनों के साथ सेवाओं के निर्यात के लिए भी लागू होंगे जो वस्तुओं के लिए लागू हैं।

सेवाओं के लिए निर्यात  
संवर्धन परिषद

3.6.2 सेवा निर्यातकों को फियो के पास पंजीकरण कराना होगा। तथापि, सॉफ्टवेयर निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकरण कराना होगा।

सेवाओं के लिए नई  
निर्यात संवर्धन परिषद

सेवा क्षेत्र को दिशा मार्गदर्शन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेवाओं के लिए एक विशेष निर्यात संवर्धन परिषद बनाई जायगी।

**सेवा निर्यात संवर्धन परिषद निम्न कार्य करेगी:**

- (i) मुख्य सेवाओं के लिए मुख्य बाजारों की तलाश करेगी और मैट्रिक्स के प्रत्येक भाग के लिए कार्यक्रम के माध्यमों से बाजार का विकास करेगी।
- (ii) ब्राण्ड स्थापित करने और लक्ष्य बाजारों में मार्केटिंग कार्यक्रम तैयार करने में क्षेत्रीय सेवा प्रदायक के साथ सहयोग करेगी।
- (iii) नीति, प्रक्रिया और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मुद्दों के संबंध में सेवा उद्योग की मान्य नोडल बोडी के साथ समन्वय

स्थापित करने में आवश्यक हस्तक्षेप करेगी।

- आम सुविधा केन्द्र** 3.6.3 सरकार क्षेत्र विशेष में गृह आधार पर सेवा प्रदायकों जैसे इंजिनियरिंग तथा वास्तुविद डिजाइन, मल्टी-मिडिया कार्यक्रमों, साफ्टवेयर का निकास करने वालों आदि उपयोग हेतु आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना और विकास करेगी तथा राज्य स्तर और जिला स्तर के कस्बों से सेवा निर्यात नजरिये में गृह आधारित व्यावसायिकों को भारी संख्या में बुलाया जायेगा।
- उद्देश्य** 3.6.4 **भारत से सेवित स्कीम**
- 3.6.4.1 सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देना उद्देश्य है ताकि सशक्त और विशिष्ट “भारत से सेवित” बांड को तुरंत समस्त विश्व में मान्यता और आदर प्राप्त हो जाए।
- पात्रता** 3.6.4.2 सभी सेवा प्रदायकों जिन्होंने विगत अथवा चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 लाख रुपए का कुल विदेशी मुद्रा अर्जन किया है शुल्क क्रेडिट हकदारी हेतु पात्रता के हकदार होंगे।  
उन व्यक्तियों हेतु जो सेवा प्रदायक हैं, कुल विदेशी मुद्रा अर्जन मापदंड विगत वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए होगा।  
इस योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट के लाभ की हकदार वही विदेशी विनिमय जमा राशियाँ होंगी जो आवेदक द्वारा सेवा शुल्क तथा प्रदत्त विशिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त की गई हैं। इस दृष्टि से वे सेवाएँ/जमा राशियाँ जो इसकी पात्र नहीं हैं, को प्रक्रिया पुस्तक भाग-1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।
- हकदारी** 3.6.4.3 सभी सेवा प्रदायक ( होटलों और रेस्टोरेंटों को छोड़कर ) विगत वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे।
- होटल और रेस्टोरेंट** 3.6.4.4 पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक सितारा और उससे अधिक होटल ( मैनेज्ड होटल और हैरिटेज होटल शामिल हैं ) और पर्यटन विभाग भारत सरकार के पास पंजीकृत पर्यटन क्षेत्र के अन्य सेवा प्रदायक विगत वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे।

विशिष्ट रेस्टोरेंट विगत वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 20 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे ।

**टिप्पणी :** एक और दो सितारा होटलों और विशिष्ट रेस्टोरेंटों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों तथा स्रोतों से जैसे कि विनिर्दिष्ट हों के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा को स्कीम के तहत शुल्क क्रेडिट हकदारी के परिकलन के उद्देश्य हेतु गिना जाए ।

अनुमत आयात

3.6.4.5 शुल्क क्रेडिट हकदारी को स्पेयर्स, कार्यालय उपकरण और पेशेवर उपकरण, कार्यालय फर्नीचर और उपभोग्यों सहित निर्यात और आयात मर्चों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण में शामिल पेय पदार्थ, स्प्रिट तथा सिरका और समुद्री खाद्य (संसाधित और अर्द्ध संसाधित) लेकिन दूध और दुग्ध उत्पाद सब्जियाँ, बागवानी और कृषि उत्पाद रहित किसी भी पूंजीगत माल के आयात हेतु प्रयोग किया जा सकता है बशर्त कि यह उनके मुख्य व्यापार का एक हिस्सा हो ।

होटलों और विशिष्ट रेस्टोरेंटों के मामले में शुल्क क्रेडिट हकदारी को खाद्य वस्तुओं और अल्कोहल युक्त पेयों हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है । स्कीम के तहत आयात होने के लिए अनुमत उत्पादों का प्रदान की गई सेवाओं के साथ सम्बन्ध होना चाहिए।

गैर-हस्तांतरणीयता

3.6.4.6 हकदारी और आयातित माल गैर-हस्तांतरणीय होगा । तथापि इस योजना के तहत आयातित माल का हस्तांतरण समूह कम्पनियों और प्रबंधित होटलों के अन्तर्गत अनुमत होगा । जैसा कि अध्याय 9 में उल्लिखित है तथा ऐसे होटलों के संदर्भ में जिनमें वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त होगी ।

हैल्थ केयर और शिक्षा

3.6.4.7 हैल्थ केयर और शैक्षणिक संस्थानों को विश्वस्तर के स्टेट-आफ-द-आर्ट मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त करने की दृष्टि से, इन क्षेत्रों के सेवा प्रदायक, अन्य सेवा प्रदायकों की तरह, विगत वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे ।

(i) हैल्थ केयर संस्थानों हेतु विदेशी मुद्रा कारोबार में मैडीकल ट्रीटमेंट, सर्जरी, टैस्टिंग, कंसलटेंसी और संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली हैल्थ केयर के माध्यम से अर्जित फीस शामिल होगी।

(ii) शैक्षणिक संस्थानों हेतु विदेशी मुद्रा कारोबार में संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले कोर्सों और कंसल्टेंसी के माध्यम से अर्जित फीस शामिल होंगी।

(iii) किसी भी मामले में, इसमें किसी अन्य स्रोत के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा जिसमें इक्विटी भागीदारी, जोनेशन आदि शामिल नहीं होगी।

(iv) शुल्क मुक्त हकदारी के तहत आयातित पूंजीगत माल और उपभोग्य माल का संबंधित शैक्षणिक अथवा हैल्थ केयर संस्थानों की गतिविधियों से संबंध होगा।

विशेष प्रावधान

3.6.4.8 सरकार के पास जनहित में अधिकार सुरक्षित होगा कि वह समय-समय पर सेवा निर्यातों की श्रेणी अथवा किस्म निर्धारित करेगी जो पात्रता अथवा हकदारी की गणना हेतु पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, सरकार समय-समय पर उस माल को भी अधिसूचित करेगी जो स्कीम के तहत जारी शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाणपत्र के तहत आयात हेतु अनुमत नहीं होंगे।

3.6.4.8.1 स्कीम 100 प्रतिशत ई ओ यू और एस ई जेड, एस टी पी आई और ई एच टी पी स्कीमों के अन्तर्गत कार्यरत ईकाइयों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इन ईकाइयों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के कारोबार तथा डी टी ए ईकाइयों के कारोबार की क्लबिंग की भी अनुमति नहीं होगी।

### लक्ष्योपरि योजना ( टारगेट प्लस स्कीम )

उद्देश्य

3.7.1 स्कीम का उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि हेतु स्टार निर्यात सदनों को पुरस्कृत करना जिन्होंने निर्यात में अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त किया है। अधिक निष्पादन प्राप्त करने वाले स्टार निर्यात सदन निर्धारित समस्त वार्षिक निर्यात लक्ष्य से काफी अधिक किए निर्यात के आधार पर शुल्क क्रेडिट हेतु पात्र होंगे (चूंकि\*\* 2004-05 हेतु निर्धारित लक्ष्य 17% है, चालू वर्ष में पुरस्कारों हेतु पात्र बनने के लिए निष्पादन की निम्नतर सीमा\*\* 20% निर्धारित की गई है)

पात्रता मापदंड

3.7.2 सभी स्टार निर्यात सदन ( एग्जिम नीति 2002-2007 के पैरा 3.7.2.1 में यथा परिभाषित स्तर धारकों समेत) जिन्होंने विगत लाइसेंसिंग वर्ष में 10 करोड़ रुपए की मुक्त विदेशी

मुद्रा में न्यूनतम निर्यात कारोबार किया है, वे लक्ष्योपरि स्कीम के तहत विचार किए जाने हेतु पात्र है।

हकदारी

3.7.3 इस स्कीम के तहत हकदारी विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में प्रतिशतता संवर्धन वृद्धि पर आधारित होगी जो इस प्रकार है :

प्रतिशतता संवर्धन वृद्धि शुल्क क्रेडिट हकदारी

(संवर्धन वृद्धि के % तौर पर)

\*\*20% और 20% से अधिक परन्तु 5%

\*\*25% से कम

\*\*25% या उससे अधिक परन्तु 10%

100% से कम

100% और उससे अधिक 15% ( 100% का)

टिप्पणी : (i) 100 प्रतिशत से अधिक की संवर्धित वृद्धि शुल्क क्रेडिट हकदारी की गणना हेतु नहीं गिनी जाएगी।

(ii) इस स्कीम के उद्देश्य हेतु, निर्यात निष्पादन किसी अन्य निर्यातक को स्थानान्तरित अथवा से स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात के मामले में, सहायक विनिर्माता/विनिर्माता निर्यातक का नाम घोषित किया जाएगा।

(iii) निर्यातक के पास विकल्प होगा कि वह लक्ष्योपरि स्कीम अथवा विशेष कृषि उपज योजना के तहत लाभ उठाने हेतु आवेदन करेगा परन्तु दोनों का लाभ एक ही निर्यातित उत्पाद के लिए नहीं ले सकता, बशर्ते कि पैरा 3.7.3 के तहत हकदारी गिनने के लिए प्रतिशतता संवर्धित विकास गिनने हेतु कुल पात्र निर्यातों को ध्यान में रखा जायेगा, लेकिन शुल्क क्रेडिट हकदारी की गणना हेतु पात्र निर्यातों को उस मात्र से घटा दिया जाएगा जिसके लिए पैरा 3.8.2 के तहत लाभ का दावा किया गया है।

(iv) मुक्त शिपिंग बिल जो सीमा शुल्क द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किये गये हैं और रत्न और आभूषण शिपिंग बिलों के तहत किये निर्यातों समेत सभी निर्यात, लेकिन पैरा 3.7.5 के तहत विनिर्दिष्ट निर्यातों को छोड़कर लक्ष्योपरि

स्कीम के तहत लाभों हेतु पात्र होंगे।

(v) स्कीम के तहत कट और पालिशड हीरों के निर्यात के बारे में केवल उन्हीं पोतलदानों को पात्र निर्यात की गणना हेतु ध्यान में रखा जाएगा जहाँ न्यूनतम मूल्य संवर्धन 10 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।

आवेदक कम्पनियाँ

3.7.4 वे कम्पनियाँ, जो स्टार निर्यात सदन हैं और किसी समूह कम्पनी का भी हिस्सा हैं, के पास यह विकल्प होगा कि वो या तो अलग कम्पनी के रूप में आवेदन करे अथवा एक समूह के रूप में आवेदन करे जो कि समूह के कुल करोबार में वृद्धि के आधार पर होगा (इस योजना के प्रयोजन के लिए अध्याय 9 में दी गई समूह कम्पनी की परिभाषा लागू होगी। इसके अलावा, समूह की केवल ऐसी कम्पनियों पर विचार किया जायेगा जो स्टार निर्यात सदन हैं)।

यदि कोई समूह कम्पनी/अपने एक या अधिक अलग-अलग स्टार निर्यात सदन कम्पनियों के निर्यात के आधार पर आवेदन करती है तो हकदारी का परिकलन आवेदक कम्पनी के पिछले लाइसेंसिंग वर्ष और वर्तमान लाइसेंसिंग वर्ष में निर्यात निष्पादन के आधार पर किया जायेगा। यह जरूरी होगा कि चालू लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान समूह की सभी स्टार निर्यात सदन कम्पनियों का समायोजित निर्यात निष्पादन पिछले वर्ष में समूह की सभी स्टार निर्यात सदन कम्पनियों के समग्र निर्यात निष्पादन से कम नहीं होना चाहिए।

यदि कोई समूह, समूह के करोबार (अर्थात् सभी स्टार निर्यात सदन कम्पनियों का कारोबार) में कुल वृद्धि के आधार पर आवेदन करता है तो समूह की स्टार निर्यात सदन कम्पनियों में से कोई भी एक कम्पनी समूह की सभी स्टार निर्यात सदन कम्पनियों की ओर से आवेदन कर सकती है।

3.7.5 इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्यातों को निर्यात निष्पादन या हकदारी परिकलन करने के लिए नहीं गिना जायेगा:-

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अधीन शामिल आयातित वस्तुओं का निर्यात या ट्रांशिपमेंट के जरिये किया गया निर्यात।



(ख) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआईबी टी पी योजनाओं के अधीन संचालित एककों का निर्यात कारोबार या उन द्वारा विनिर्मित और डीटीए के जरिये निर्यातित उत्पाद ।

(ग) मान्य निर्यात (चाहे भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया हो और भुगतान ईईएफसी खाते से किया गया हो)।

(घ) सेवा निर्यात।

(ङ.) अपरिष्कृत, काटे न गये और अर्ध पालिशड हीरे और अन्य बहुमूल्य पत्थर।

(च) किसी भी रूप में स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम और अन्य बहुमूल्य धातुएँ, जिसमें इनसे बने सादे और जड़ित आभूषण शामिल हैं ।

(छ) निर्यातक की ओर से अन्य निर्यातक द्वारा किया गया निर्यात निष्पादन।

अनुमत आयात

3.7.6

शुल्क क्रेडिट अतिरिक्त पुर्जों, कार्यालय उपकरण, व्यावसायिक उपकरण और कार्यालय फर्नीचर सहित पूंजीगत माल किन्हीं निवेशों के आयात के लिए प्रयोग की जा सकती है बशर्ते कि यह उनके अपने अथवा “आयात निर्यात फार्म” में यथाघोषित सहायक विनिर्माता के उपयोग के लिए निर्यात आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के तहत मुक्त रूप से आयात योग्य है ।

निम्नलिखित को छोड़कर निर्यात-आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 1 से 24 में सूचीबद्ध कृषि उत्पादों का आयात अनुमत होगा ।

(i) निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 7 के तहत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क के साथ लहसुन, मटर और सभी अन्य सब्जियाँ ।

(ii) निर्यात आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 8 के तहत 30 प्रतिशत से अधिक के

शुल्क सहित नारियल, एरेका नट, सन्तरे, नीबू, ताजे अंगूर, सेब और नाशपाती और अन्य सभी फल ।

(iii) निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण (लौंग को छोड़कर) के अध्याय 9 के तहत 30 प्रतिशत से अधिक के शुल्क सहित सभी मसाले।

(iv) निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 9 के अनुसार चाय, काफी और काली मिर्च।

(v) निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 12 के तहत सभी तिलहन ।

इसके अलावा निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के अध्याय 40 के अनुसार इस स्कीम के अधीन प्राकृतिक रबर के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

अध्याय 15 के तहत वर्गीकृत सभी खाद्य तेलों का आयात, स्कीम के तहत केवल एस टी सी और एम एम टी सी के जरिए अनुमत होगा ।

सेंवेट/शुल्क वापसी

3.7.7 लक्ष्योपरि योजना (टारगेट प्लस स्कीम) के तहत नकद या डेबिट के जरिये किए गये अतिरिक्त सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान को राजस्व विभाग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार समयोजित किया जायेगा ।

विशेष प्रावधान

3.7.8 सरकार को जन हित में यह अधिकार रहेगा कि वे समय-समय पर उन निर्यातों और निर्यात उत्पादों के वर्ग को निर्दिष्ट करे जो बढ़ रही वृद्धि/हकदारी के परिकलन हेतु पात्र नहीं होंगे ।

इसी प्रकार, सरकार समय-समय पर उन वस्तुओं की सूची को भी अधिसूचित कर सकती है जिनका आयात इस योजना के तहत जारी किए गए शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र के अन्तर्गत अनुमत नहीं होगा ।

### 3.8 विशेष कृषि उपज योजना

उद्देश्य

- 3.8.1 इस योजना का उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्यातकों प्रोत्साहन देकर फलों, सब्जियों, फूलों, साधारण वन्य उपज डेयरी, पौल्ट्री, माँस और इनके मूल्य संवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना है।

हकदारी

- 3.8.2 ऐसे उत्पादों के निर्यातक 1 अप्रैल, 2004 मार्च, 2005 की अवधि के लिए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे। तथापि डेयरी, पौल्ट्री, माँस तथा इनके मूल्य संबंधित उत्पाद केवल 1 अप्रैल, 2005 या उसके बाद किए गए निर्यातों के लिए मिलने वाले लाभ के हकदार होंगे। इसके मद्दे आयातित स्क्रिप और मर्दे मुक्त रूप हस्तांतरणीय होंगी।

- 3.8.21 स्कीम के अन्तर्गत, प्रक्रिया पुस्तक 2004-2009 के परिशिष्ट-37क में दी गई सभी मर्दों का निर्यात पैरा 3.8.2. के अनुसार निर्यात लाभों के योग्य होगा। जो मर्दे, निर्यात आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में निर्यात की अनुसूची 2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबन्धित अथवा निषिद्ध हैं, पैरा 3.8.2 के अन्तर्गत किन्हीं लाभों की पात्र नहीं होगी।

- 3.8.22 निम्नलिखित निर्यात पर ड्यूटी क्रेडिट अधिकार के लिए विचार नहीं किया जाएगा :

क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अन्तर्गत आने वाले आयातित माल की निर्यात या ट्रांसशिपमेंट के द्वारा किया गया निर्यात

ख) मान्य निर्यात (चाहे भुगतान मुक्त विदेशी विनिमय में प्राप्त किया जाना हो और भुगतान ई ई एफ सी खाते से होनी हो)

अनुमत आयात

- 3.8.3 शुल्क क्रेडिट का प्रयोग यथा निर्दिष्ट निविष्टियों या पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु किया जा सकता है बशर्ते आई टी सी (एचएस) के तहत इनका मुक्त रूप से आयात किया जा सके। निर्यात के पत्तन के अलवा अन्य किसी पत्तन से आयात की

अनुमति राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार दी जा सकती है।

3.8.3.1 प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) के परिशिष्ट 37(ख) में उल्लिखित मर्दे इस योजना के अन्तर्गत आयात के लिए अनुमत नहीं की जाएंगी।

सेंवेट/शुल्क-मुक्त

3.8.4 विशेष कृषि उपज योजना के तहत नकद या डेबिट के जरिये किए गये अतिरिक्त सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान को राजस्व विभाग द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार सेंवेट क्रेडिट/शुल्क वापसी के रूप में समयोजित किया जायेगा।

विशेष प्रावधान

3.8.5 सरकार को जन हित में यह अधिकारी रहेगा कि वे समय-समय पर उन निर्यातों और निर्यात उत्पादों के वर्ग को निर्दिष्ट करे जो बढ़ रही वृद्धि/हकदारी के परिकलन हेतु पात्र नहीं होंगे।

## अध्याय - चार

शुल्क मुक्त/वापसी स्कीम

**शुल्क मुक्त/ वापसी स्कीम** 4.1 शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद के लिए आवश्यक निविष्टियों का आयात किया जाता है। शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंस जारी किया जाता है। शुल्क वापसी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर लगे शुल्क के निर्यात पश्चात् छूट/वापसी की जाती है। शुल्क वापसी स्कीम में (क) डी एफ आर सी (शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र) और (ख) डी ई पी बी शामिल (शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम) हैं।

डी एफ आर सी निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निवेशों के शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति (रिप्लैनिशमेंट) अनुमत करता है। डी ई पी बी स्कीम में निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर आयात प्रभारों की वापसी की अनुमति है।

**शुल्क मुक्त/वापसी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात की गई वस्तुओं का पुनः आयात** 4.1.1 अग्रिम लाइसेंस/डी एफ आर सी/डी ई पी बी के अन्तर्गत निर्यात की गई वस्तुओं का पुनः आयात उसी रूप या आंशिक रूप से उसी रूप में पुनः आयात किया जा सकता है बशर्ते कि वे समय-समय पर जारी राजस्व विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

**मूल्य संवर्धन** 4.1.2 इस अध्याय के मामले में (रत्न और आभूषण छोड़कर) मूल्य संवर्धन इस प्रकार होगा :-

ए-बी

वी.ए =  $\frac{\text{बी}}{\text{बी}} \times 100$ , जहाँ

बी

वी.ए मूल्य संवर्धन

ए वास्तविक निर्यात का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति के मार्ग पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के लिए

बी लाइसेंस के तहत आने वाले आयातित निवेशों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य तथा कोई अन्य आयातित माल जिसपर शुल्क वापसी का लाभ का दावा किया जा रहा है।

## अग्रिम लाइसेंस

अग्रिम लाइसेंस

- 4.1.3 निर्यात उत्पाद में (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए) वास्तव में शामिल की जाने वाली निविष्टियों के आयात की अनुमति देने के लिए शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, स्कीम के अधीन ईंधन, तेल, ऊर्जा, कैटालिस्ट आदि जिनकी खपत निर्यात उत्पाद के लिए उपयोग की जाती है, भी जारी किया जा सकता है।

अग्रिम लाइसेंस के अधीन लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक ऐसे अनिवार्य कलपुर्जों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है जिनके परिणामी उत्पाद को सायन (एस आई ओ एन) के अधीन निवेशों और निर्यात मदों के आधार पर अग्रिम लाइसेंस जारी किए जाने की अनुमति है। अग्रिम लाइसेंस सियोन के अन्तर्गत दिए गए निर्यात मदों के इनपुट के आधार पर जारी किए जाते हैं। तथापि, वे प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.7 के अनुसार स्वतः घोषित मानदण्डों या तदर्थ मानदण्डों के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं :-

अग्रिम लाइसेंस विनिर्माता, निर्यातक अथवा सहायक विनिर्माता के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातक को निम्नलिखित हेतु जारी किया जा सकता है।

- i. वास्तविक निर्यात (एस ई जैड को किए निर्यात समेत) और, या
- ii. अन्तर्वर्ती आपूर्तियाँ, और/या
- iii. माल के विनिर्माण में आवश्यक निवेशों के आयात हेतु नीति के पैरा

8.2(ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित श्रेणियों को माल की आपूर्ति हेतु मुख्य ठेकदार को।

इसके अलावा, नीति के पैरा 8.2(घ)(ङ)(च) और (छ) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को माल की आपूर्ति के बारे में, ऐसी परियोजना के मुख्य ठेकेदार के उप-ठेकेदार द्वारा भी अग्रिम लाइसेंस का लाभ उठाया जा सकता है बशर्ते की उप-ठेकेदार का नाम मुख्य ठेके में उल्लिखित हो।

ऐसा लाइसेंस संयुक्त राष्ट्र संघ को की गयी आपूर्तियों संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता कार्यक्रम अथवा अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के अन्तर्गत हेतु भी जारी किया जा सकता है जिसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जाएगा ।

4.1.4 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के मद्दे पैरा 4.1.3 में परिभाषित निवेशों के शुल्क मुक्त आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी किया जाता है । ऐसे लाइसेंस (मान्य निर्यातों हेतु अग्रिम लाइसेंस के अलावा) मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, एंटीडम्पिंग शुल्क, और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, से छूट प्राप्त होंगे । तथापि, पैरा 8.2(ज) और (झ) के तहत शामिल आपूर्तियों हेतु आयात लागू एंटी-डम्पिंग और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगा ।

4.1.5 अग्रिम लाइसेंस और/अथवा उनके तहत आयातित माल निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद भी हस्तान्तरणीय नहीं होंगे । तथापि, लाइसेंसधारक को निर्यात दायित्व की पूर्ति करने के बाद शुल्क मुक्त निवेशों में से विनिर्मित उत्पाद को बेचने का विकल्प प्राप्त होगा ।

4.1.6 अग्रिम लाइसेंस सकारात्मक मूल्य संवर्धन के साथ जारी किया जा सकता है ।

तथापि, ऐसा निर्यात जिसका भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है वह प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-32 में यथाविनिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा ।

4.1.7 अग्रिम लाइसेंस जारी करने की तारीख को प्रभावी प्रक्रिया और नीति के अनुसार जारी किया जाएगा ।

आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस की वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) विनिर्दिष्ट अनुसार होगी ।

4.1.8 अग्रिम लाइसेंस की सुविधा वहाँ भी उपलब्ध होगी जहाँ निर्यातक को कुछ निवेशों की निशुल्क आपूर्ति की जाती है ।

ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन की गणना हेतु, निशुल्क निवेशों के नोशनल मूल्य के साथ अन्य शुल्क मुक्त निवेशों को भी ध्यान में रखा जाएगा तथापि, यदि सभी निविष्टियों की बिना लागत आपूर्ति की जाती है तो ऐसे निविष्टियों नीति के पैराग्राफ 4.2.7 के अधीन आएंगे ।

निर्यात दायित्व

4.1.9 अग्रिम लाइसेंस के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि प्रक्रिया पुस्तक भाग-1 में उल्लिखित अनुसार होगी ।

बी आई एफ आर  
यूनिटों हेतु प्रावधान

4.1.9 बी आई एफ आर के पास पंजीकृत किसी फर्म/कम्पनी अथवा यूनिट अधिग्रहण करने वाली किसी फर्म/कम्पनी जो बी आई एफ आर के अन्तर्गत हो, संचालन एंजेसी द्वारा तैयार किए पुनर्वास पैकेज के अनुसार निर्यात निष्पादन अवधि विस्तार की अनुमति होगी बशर्ते कि बी आई एफ आर का बाद में अनुमोदन प्राप्त हो जाए ।

तथापि, उन मामलों में जहाँ पुनर्वास पैकेज में निर्यात दायित्व अवधि विस्तार का उल्लेख न हो निर्यात दायित्व पूर्ति हेतु मामले के गुण-दोष के आधार पर लाइसेंस के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी ।

इसी प्रकार संबंधित राज्य सरकार की पुनर्वास स्कीम के अनुसार ऐसी सुविधा हेतु एस एस आई यूनिट भी पात्र होंगी । तथापि उन मामलों में जहाँ राज्य पुनर्वास स्कीम में निर्यात दायित्व विस्तार अवधि का उल्लेख ना हो, निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु मामले के गुण-दोष के आधार पर लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक अनुमति दी जाएगी ।

वार्षिक आवश्यकता के  
लिए अग्रिम लाइसेंस

4.1.10 अग्रिम लाइसेंस वास्तविक निर्यातों अर्न्तवर्ती आपूर्तियों या मान्य निर्यातों के लिए वार्षिक अपेक्षाओं के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं।

एक से पाँच सितारा निर्यात सदन, वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम लाइसेंस के लिए पात्र होंगे । निर्यातकों की अन्य सभी श्रेणियां जिनका विगत निर्यात निष्पादन हो वे भी वार्षिक आवश्यकता अग्रिम लाइसेंस के लिए हेतु पात्र होंगे ।

इसके अलावा व्यापारी निर्यातक को उनकी वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम लाइसेंस दिया जा सकेगा बशर्ते कि वे संगत लाइसेंस में सह निर्माता के नाम (नामों) के पृष्ठांकन के लिए सहमत हों ।

विगत लाइसेंसिंग वर्ष में इस स्कीम के अन्तर्गत आयात के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अनुसार हकदारी वास्तविक और/या मान्य निर्यात के मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 300 प्रतिशत अथवा एक करोड़ रुपये, जो भी अधिक हो, तक होगी । ऐसे लाइसेंस में सकारात्मक मूल्य संवर्धन शामिल होगा।



अग्रिम रिलीज आदेश 4.1.11 अग्रिम लाइसेंसधारक, (वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम लाइसेंसधारक और डी एफ आर सी धारक जो सीधे आयात के बदलने स्वदेशी स्रोतों राज्य व्यापार अभिकरणों/ई ओ यू/एस ई जेड/ई एच टी पी/ एस.टी.पी. यूनिटों से निविष्टियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे उन निविष्टियों को अग्रिम रिलीज आदेशों के प्रति विदेशी मुद्रा/भारतीय रूपए में प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

डी एफ आर सी के हस्तांतरणकर्ता भी ए.आर.ओ सुविधा के लिए पात्र होगा । तथापि, ई.ओ.यू/ ई.एच.टी.पी/ एस.टी.पी/एस ई जेड से ए.आर.ओ को परिवर्तन किए बिना लाइसेंस के प्रति आपूर्तियां प्राप्त की जा सकती हैं ।

ए. आर. ओ की वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथानिर्धारित अनुसार होगी ।

बैंक टू बैंक ऋण का 4.1.12 अग्रिम लाइसेंसधारक(वार्षिक अपेक्षाओं के लिए अग्रिम लाइसेंसधारक) और डी एफ आर सी धारक अग्रिम रिलीज अन्तर्देशीय साख पत्र आदेश के लिए आवेदन करने के बजाय प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र का लाभ उठा सकता है ।

निषिद्ध मर्दे 4.1.13 इस स्कीम के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों के तहत आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित आयातों का निषिद्ध मर्दों का आयात नहीं किया जाएगा ।

इसके अलावा, राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात हेतु आरक्षित मर्दों को अग्रिम लाइसेंस के मर्दे आयात नहीं किया जा सकता । तथापि, ये मर्दे अग्रिम लाइसेंस धारक को जारी ए आर ओ के मर्दे राज्य व्यापार उद्यमों से खरीदी जा सकती है ।

इसी प्रकार आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित निर्यातों की निषिद्ध मर्दों का इस स्कीम के अन्तर्गत जारी लाइसेंस के तहत निर्यात नहीं किया सकता, इसके अलावा प्रतिबधित मर्दों का निर्यात, निर्यात लाइसेंस अथवा अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता अथवा सभी शर्तों के मर्दे आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के तहत होगा ।

शुल्क वापसी की 4.1.14 अग्रिम लाइसेंस के मामले में, शुल्क भुगतान किए गए माल पर शुल्क वापसी उपलब्ध होगी, कोई भी आयातित या स्वदेशी शुल्क प्रदत्त सामग्री को वित्त मंत्रालय (शुल्क वापसी निदेशालय) द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार शुल्क वापसी उपलब्ध

होगी। तथापि, लाइसेंस में यथाउल्लिखित शुल्क प्रदत्त सामग्रियों को ही शुल्क वापसी दी जाएगी।

### शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र

शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र (डी एफ आर सी)

4.2 वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों के आयात के लिए व्यापारी-निर्यातक अथवा विनिर्माता-निर्यातक को मूल सीमाशुल्क, शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए बिना शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

तथापि, ऐसी निविष्टियाँ आयात के समय उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान के शर्तों के अधीन होंगी।

4.2.1 डी एफ आर सी, रत्न और आभूषण क्षेत्र की ऐसी मदों जिनके लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4क.2.1 में मूल्य संवर्धन दिया गया है, को छोड़कर 20 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संवर्धन पर जारी किए जायेंगे।

4.2.2 उस वास्तविक निर्यात के लिए शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है जिसके लिए मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा उन निर्यातों के लिए भी शुल्क मुक्त प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है (एस ई जेड को आपूर्तियों सहित) जिसके लिए भुगतान अपरिवर्तनीय मुद्रा/आपूर्तियों के लिए भी जारी की जा सकती है जो नीति के पैराग्राफ 8.2 के अधीन प्रभावी है। (डी एफ आर सी धारकों की आपूर्तियों के लिए मान्य) तथापि, ऐसा निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-11 में यथानिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।

4.2.3 विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित सिओनस के अन्तर्गत शामिल केवल निर्यात उत्पादों के संबंध में शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।

तथापि सिओनस जो "वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन है या जहाँ आयात की पूर्व शर्त सहित निविष्टि की अनुमति है या जहाँ निर्यात को पूरा न किया गया हो या आवेदन पत्र को भरते समय या सामान्य मानदण्डों के तहत ईंधन के आयात के

लिए हो, इन सब निवेशों के लिए डी एफ आर सी वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त सहित जारी किया जाएगा ।

तथापि, ईंधन, के लिए आयात पात्रता उसी कम्पनी को हस्तांतरित की जा सकती है जो बाजार में ईंधन के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राधिकृत हो ।

ऐसे मामले जिनमें मानक निवेश उत्पाद मानदण्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, एपीडाईन तथा सिओडो एपीडाईन के आयात को अनुमत करते हैं, इनके लिए डी एफ आर सी जारी किया जाएगा बशर्ते इन मदों को विशेषतः आयात मदों की सूची से न हटा दिया गया हो ।

सॉयन (एस आई ओ एन) जोकि निवेशों के लिए पूर्व आयात की शर्त लगाता हो, के मामले में डी आफ आर सी जारी नहीं किया जाएगा ।

4.2.4 शिपिंग बिल में यथा उल्लिखित सिओन के अनुसार निविष्टियों के आयात के लिए शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। ऐसे लाइसेंसों की वैधता प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी । डी. एफ. आर. सी. और/या इसके मद्दे आयातित सामग्री मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगी। तथापि, वास्तविक प्रयोक्ता की सशर्त डी एफ आर सी या उसके बदले में आयातित सामग्री (सामग्रियाँ) अहस्तांतरणीय होंगी ।

4.2.5 निर्यात उत्पाद, जो संशोधित वैट के लिए पात्र हैं, सेनवेट ऋण/सेवा कर ऋण के लिए पात्र होंगे ।

तथापि, स्कीम के अन्तर्गत गैर-उत्पाद शुल्क योग्य, गैर-शुल्क योग्य या केन्द्रीय वैट योग्य उत्पाद, स्कीम के तहत आयात के समय प्रदत्त अतिरिक्त सीमाशुल्क के बदले में निर्यात के समय शुल्क वापसी के पात्र होंगे।

- 4.2.6 शुल्क वापसी निदेशालय (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त किसी भी सामग्री जिसपर शुल्क अदा किया गया हो चाहे आयातित हो अथवा स्वदेशी, के संबंध में निर्यातक शुल्क वापसी लाभों के लिए पात्र होंगे।

तथापि, शुल्क वापसी उन सामग्रियों पर दी जाएगी जिन पर शुल्क दिया गया हो और सिओन के अन्तर्गत न आती हों।

पुनः निर्यात के लिए  
जाबिंग मरम्मत आदि

- 4.2.7 राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार जो माल आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित रूप में उल्लिखित निःशुल्क आपूर्ति की शर्तों पर निषिद्ध मद नहीं है जाबिंग प्रयोजन के लिए उसका लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना आयात के अनुमति दी जा सकती है।

सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, मरम्मत, रिकंडिशनिंग, रिइंजीनियरिंग, टेस्टिंग आदि करने के लिए इसी प्रकार के माल के आयात की अनुमति होगी चाहे वह मूल निर्यात आयात नीति/आयात और निर्यात पुस्तक के आई. टी. सी एच. एस वर्गीकरण के अधीन आयात के लिए प्रतिबंधित हों।

तथापि, उपरोक्त प्रावधान सभी शर्तों के अधीन या लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता के अनुसार जो आई टी सी(एच एस) की अनुसूची-2 के अनुसार लागू होंगे।

### शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम (डी ई पी बी)

शुल्क हकदारी पास  
बुक स्कीम (डी ई पी  
बी)

- 4.3 शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम का उद्देश्य है निर्यात उत्पाद के आयात अंश पर लागू मूल सीमाशुल्क को अप्रभावी करना है। निर्यात उत्पाद के अधीन शुल्क ऋण को प्रदान करने के माध्यम से अप्रभावीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

डी ई पी बी योजना तक लागू रहेगी जब तक निर्यातकों के साथ परामर्श करके कोई अन्य नई योजना नहीं बनाई जाती।

- 4.3.1 डी ई पी बी के अधीन निर्यातक, अपनी ऋण की पात्रता के कारण मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विनिर्दिष्ट प्रतिशता का दावा करने का पात्र होगा।

कच्चे माल, अन्तरवर्तियों, संघटकों, कलपूजों, पैकेजिंग सामग्री आदि के आयात हेतु क्रेडिट, ऐसे निर्यात उत्पादों और दर के लिए उपलब्ध होगा जो विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों।

4.3.2 डी ई पी बी धारक के पास अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान नकद करने का विकल्प होगा।

वैधता

4.3.3 आयात के लिए डी ई पी बी की वैधता की अवधि प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में विनिर्दिष्टा के अनुसार होगी।

हस्तांतरणीयता

4.3.4 डी ई पी बी और/अथवा इसके प्रति आयातित मदे मुक्त हस्तांतरणीय हैं। तथापि, डी ई पी बी का हस्तांतरण आयात के लिए डी ई पी बी में आयात के लिए विनिर्दिष्ट उस पत्तन पर होगा जहाँ से निर्यात किया गया है।

तथापि, निर्यात के अन्य पत्तन से आयातों को राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई टी आर ए अधिसूचना की शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

शुल्क वापसी की उपयुक्तता

4.3.5 सामान्य रूप से डी. ई. पी. बी. स्कीम के अधीन किए गए निर्यात शुल्क वापसी के हकदार नहीं होंगे। तथापि, डी ई पी बी के अधीन निविष्टियों पर नकद अदा किया गया अतिरिक्त सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सेनेवैट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में समायोजित किया जाएगा।

### रत्न और आभूषण

रत्न और आभूषण के लिए स्कीम

4क रत्न और आभूषण निर्यातक रत्न और आभूषण के विनिर्माण के लिए आवश्यक शुल्क मुक्त निविष्टियों का आयात कर सकते हैं।

प्रतिपूर्ति लाइसेंस

4क.1 रत्न और आभूषण निर्यातक प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति लाइसेंस (आर ई पी) प्राप्त करके अपने निवेशों का शुल्क मुक्त आयात करने के पात्र होंगे।

4क.1.1 प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 26 में सूचीबद्ध रत्न और आभूषण उत्पादों के निर्यातक, अपने निवेशों के आयात और प्रतिपूर्ति के लिए उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित दर पर और उसमें दी गई मदों के लिए, प्रतिपूर्ति लाइसेंस के पात्र होंगे।

प्रतिपूर्ति लाइसेंस, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4क.28 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उपभोज्यों के आयात के लिए भी जारी किया जा सकता है।

प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए कटे हुए और पॉलिश किए हीरों का निर्यात

4क.2 कम से कम तीन वर्षों का निर्यात अनुभव रखने वाले और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के वार्षिक औसत कारोबार करने वाले रत्न और आभूषण निर्यातक अथवा जिमोलॉजीकल इस्टिच्यूट आफ अमेरिका (जी आई ए), दि रोबर्ट मोउवाड कैम्पस, इन्टरनेशनल जिमोलॉजिकल इस्टिच्यूट (आई जी आई) और यू एस ए में यूरोपियन जिमोलोजिकल लेबोरेटरी (ईजीएल), हॉग रोड बूर डायमण्ड, एन्टवर्प (एच आर डी) वर्ल्ड डायमण्ड सेंटर आफ डायमण्ड हाई काउंसिल एन्टवर्प बेल्जियम सेंट्रल जेम लेबोरेटरी, मिआगी बिल्डिंग 5-14 यूएनो टायतो-कू टोक्यो जापान के भारत में स्थित प्राधिकृत कार्यालय/एजेंसियों को उक्त प्रयोगशालाओं/एजेंसियों द्वारा निर्धारित प्रमाणन/ग्रेडिंग प्रयोजन के लिए, कटे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों, प्रत्येक वजन 0.25 कैरिट और उससे अधिक के निर्यात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इनके द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ग्रेडिंग रिपोर्ट के साथ बिना किसी आयात शुल्क के इनका पुनः आयात किया गया हो।

4क.2.1 प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिये कटे हुए और पालिश किये हीरों के निर्यात के समय निर्यातक को सीमाशुल्क प्राधिकारी को यह वचनवद्धता देनी होगी कि कटे हुये और पालिश किये हीरों का प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिये निर्यात के तीन माह के भीतर पुनः आयात किया जायेगा।

निर्यात बीजक में प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए निर्यात किए जाने वाले प्रत्येक हीरे के अनुमानित मूल्य, ऊंचाई, व्यास, भार का स्पष्ट उल्लेख किया जाये ताकि उनके आयात के समय उनकी पहचान के लिए उक्त विनिर्देशन के साथ मूल की तुलना की जा सके। बाद में, इन कटे और पालिश किए हीरों का नीति के प्रावधानों के अनुसार निर्यात किया जा सके।

स्वर्ण/चांदी/  
प्लेटिनम के  
आभूषणों के लिए  
स्कीमें

4क.3 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं के निर्यातक इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ण, प्लेटिनम, चांदी, माउंटिंग्स, फाइंडिंग्स, अपरिष्कृत रत्न, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर सिन्थेटिक पत्थर और असंसाधित मोती आदि जैसी अपनी अनिवार्य निविष्टियों का आयात कर सकते हैं ।

नामित एजेंसियां

4क.4 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों और उनकी वस्तुओं की स्कीमों का लाभ उठाने वाले निर्यातक (ई ओ यू/एस ई जेड स्कीम के तहत संचालित ईकाइयों को छोड़कर) नामित एजेंसियों से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं । नामित एजेंसियां ये हैं - एमएमटीसी लिमिटेड, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पी ई सी) नीति के पैराग्राफ 3.5.2 के तहत पांच सितारा निर्यात सदन और भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक को रिफाइनिंग के लिए गोल्ड स्क्रेप का निर्यात करने तथा स्टैंडर्ड गोल्ड बार्स के रूप में आयात करने की अनुमति है ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक मानक स्वर्ण छड़ों के रूप में शोधन और आयात हेतु स्वर्ण छीजन का आयात कर सकता है । सोने के आयात के विषय में विस्तृत प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित मार्ग निर्देशों के अनुसार की जाएगी ।

निर्यात की मदें

4क.5 निम्नलिखित मदों का, यदि निर्यात किया जाता है, तो वे इन स्कीमों के अन्तर्गत रत्न और आभूषण क्षेत्र हेतु पैरा-4 के तहत स्कीमों की सुविधाओं के लिए पात्र होंगी ।

(क) 8 कैरेट या अधिक सोना वाले सोने के जेवरात चाहे सादे हों अथवा जड़ित जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषणों तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के शामिल नहीं हैं )

(ख) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले आंशिक रूप से संसाधित आभूषण सहित चांदी के जेवरात, चांदी के बर्तन, चांदी के स्ट्रिप्स और वस्तुएं इसमें मैडल और सिक्के शामिल हैं (इनमें वैध टेंडर वाले सिक्के और कोई इंजीनियरी माल शामिल नहीं है।)

(ग) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक भार प्लेटिनम वाले जेवरात जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषण तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के व इंजीनियरिंग माल शामिल नहीं हैं)।

मूल्य परिवर्धन

4क.6

रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए मूल्य परिवर्धन प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4क.2.1 में दिए अनुसार होगी।

क - ख

वी. ए =  $\frac{\text{-----}}{\text{ख}} \times 100$  जहाँ

वी. ए. मूल्य परिवर्धन

क. = प्राप्त निर्यात का पोत पर्यन्त मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य

ख. = लागत बीमा भाड़ा मूल्य अर्थात् रत्न आदि जैसे अन्य मदों के मूल्य सहित अनुमत अवशिष्ट के साथ निर्यात उत्पाद में वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम अंश का मूल्य/जहाँ कहीं भी सोने को ऋण आधार पर दिया गया है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में ब्याज के भुगतान को भी लागत बीमा भाड़ा मूल्य में शामिल किया जाएगा।

छीजन मानदंड

4क.7

सोने/चांदी/प्लेटिनम जेवरात के लिए स्कीमों के तहत, विनिर्माण अपशेष अथवा छीजन प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4क.2 में विनिर्दिष्ट के अनुसार अनुमत होगी।

विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्ति के प्रति निर्यात

4क.8

जहाँ निर्यात आदेश, तीन वर्ष के अनुभव वाले नामित एजेंसी/स्तर धारियों/निर्यातकों जिन्होंने पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ का कारोबार किया है, को दिया जाता है वहां विदेशी क्रेता विनिर्माण और निर्यात के लिए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम, एलॉय, चांदी/स्वर्ण/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माउंटिंग का अग्रिम और प्रभार मुक्त रूप में नामित एजेंसियों/स्तर धारकों/निर्यातकों को आपूर्ति कर सकता है।



नामित अभिकरणों द्वारा सीधे या उनकी सहयोगी कम्पनियां या स्तरधारियों/निर्यातकों जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है। फाईंडिंग्स का आयात और निर्यात नेट टू नेट आधार पर किया जाएगा। विदेशी क्रेता, नामित एजेंसियों/स्तरधारियों/निर्यातकों को सादे, अर्ध परिष्कृत सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषण जिनमें मरम्मत/ पुनःनिर्माण और निर्यात के लिए फाईंडिंग/माउंटिंग/कम्पोनेन्ट्स शामिल हैं, की भी आपूर्ति (अग्रिम और प्रभार मुक्त रूप से) कर सकता है बशर्ते कि न्यूनतम मूल्य संवर्धन 10 प्रतिशत हो। तथापि, यदि इस प्रकार के आयातित अर्ध परिष्कृत सोना/ चांदी/प्लेटिनम आभूषणों का जड़ित आभूषण के रूप में निर्यात किया जा सकता है। उनका मूल्य संवर्धन 15 प्रतिशत प्राप्त किया जायेगा। निर्यात के ऐसे मामलों में 2 प्रतिशत के छीजन की अनुमति होती है।

इस संबंध में प्रक्रिया, प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) में दिए अनुसार होगी।

- |   |       |   |
|---|-------|---|
| नामित एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के निर्यात | 4क.9  | निर्यातक, इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्यात उत्पादों के लिए सोने/चांदी/प्लेटिनम को निवेश के रूप में अग्रिम अथवा निर्यात के बाद प्रतिपूर्ति के तौर पर नामित एजेंसियों से प्राप्त कर सकता है।  |
| अग्रिम लाइसेंस के प्रति निर्यात           | 4क.10 | <p>निम्नलिखित हेतु शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस दिया जा सकता है :-</p> <p>(क) कम से कम 0.995 शुद्धता का सोना, और 8 कैरेट और अधिक के माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाईंडिंग्स।</p> <p>(ख) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी, माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाईंडिंग्स जिनमें भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो।</p> <p>(ग) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लेटिनम, माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाईंडिंग्स जिनमें भार में 50 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम हो।</p> |
|   | 4क.11 | ऐसे लाइसेंसों में निर्यात दायित्व की शर्त रहेगी जिसे इस संबंध में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4क में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा।  |

अग्रिम लाइसेंसधारक इस बारे में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सीधे आयात के बदले नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं ।

रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस	4क.12	<p>नीति के पैरा 4क.8, 4क.9 और 4क.10 में दिए गए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए स्कीमों के तहत रत्न प्रतिपूर्ति रत्न और आभूषण लाइसेंस जारी किया जा सकता है। सादा स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी जेवरात और उनकी वस्तुओं के मामले में, ऐसे लाइसेंसों का मूल्य, निर्धारित न्यूनतम मूल्य परिवर्धन से अधिक की वसूली के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा ।</p> <p>जड़ित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम जेवरात और उनकी वस्तुओं के मामले में, अनुमेय वेस्टेज समेत स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी पर मूल्य परिवर्धन का हिसाब लगाने के बाद, निर्यातित मर्चों में उपयुक्त जड़ितों के मूल्य को ध्यान में रखकर रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस का मूल्य निर्धारित किया जाएगा ।</p> <p>ऐसे रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगे।</p>
रत्न प्रतिपूर्ति दर और मद	4क.13	<p>प्रतिपूर्ति का पैमाना और आयात की मद, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 12ख के अनुसार निर्धारित होगी ।</p>
हीरा अग्रदाय लाइसेंस	4क.14	<p>कटे और पालिश किये हीरों, आधे कटे हीरे, किसी भी रूप में कटे हुए सहित मिश्रण के लिए यदि अपेक्षित हो, कटे और पालिश किए हुए हीरों के आयात और कटे और पालिश किये हीरों के निर्यात के लिए हीरा अग्रदाय लाइसेंस जारी किया जा सकता है।</p> <p>ऐसे लाइसेंसों के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति, इस बारे में जारी प्रक्रिया के अनुसार करनी होगी ।</p>
पात्रता	4क.14.1	<p>कटे और पालिश किए हीरों के निर्यातक जो स्तरधारी हो, को कटे और पालिश किए हीरों के पिछले वर्ष के निर्यात निष्पादन के 5 प्रतिशत तक कटे और पालिश किए हीरों के आयात के लिए लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।</p>

- निर्यात दायित्व 4क.14.2 स्कीम के तहत निर्यात दायित्व प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के अध्याय 4 के पैराग्राफ 4क के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ।
- निर्यात संवर्धन दौरे/ ब्राण्डेड आभूषणों का निर्यात 4क.15 वाणिज्य विभाग की अनुमति से नामित एजेन्सियों और उनके सहयोगी तथा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की अनुमति से अन्य, विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने/भाग लेने के लिए स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं ।
- स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थरों, मणियों और वस्तुओं तथा ब्राण्डेड आभूषण को व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की अनुमति है । ये निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दी गई शर्तों के अधीन होंगे ।
- निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर लाना-ले जाना 4क.16 विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्न और आभूषण के निर्यात पार्सलों तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी द्वारा रत्न और आभूषण को व्यक्तिगत तौर पर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लाने- ले जाने की अनुमति होगी ।
- डाक द्वारा निर्यात 4क.17 विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात के मामले में जिसमें विदेशी डाकघर के माध्यम से स्पीड पोस्ट के द्वारा भी निर्यात शामिल है, आभूषण के पार्सल का मूल्य 50,000 अमरीकी डालर तथा भार में 20 किग्रा. से ज्यादा नहीं होगा । विस्तृत प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अध्याय-4 में दिया गया है ।
- निजी/सार्वजनिक बांडिड गोदाम 4क.18 कटे और पालिश किए गए हीरों, कटे और पालिश किए गए रंगीन रत्नों, अनकटे और सेट न किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों के आयात और पुनः निर्यात के लिए एस ई जैड/डी टी ए में निजी एवं सार्वजनिक बाण्डेड गोदाम स्थापित किए जा सकते हैं । कटे और पालिश किए गए हीरों और कटे और पालिश किए गए रंगदार रत्नों का आयात और पुनः निर्यात 5 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संवर्धन की प्राप्ति के अधीन होगा ।

हीरा और जवाहरात  
डॉलर खाते

4क.19 अपरिष्कृत या कटे और पालिश किए हीरों/रत्नों के सादे आभूषण, मिनाकरी और/या हीरे से जड़ित/अजड़ित और/या अन्य पत्थर की खरीद/बिक्री करने वाली फर्मों तथा कम्पनियाँ जिनका हीरों के आयात या निर्यात में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव है और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत कारोबार है, के नामजद हीरा डॉलर खातों के जरिये अपना व्यापार जारी रख सकती है।

हीरा डॉलर लेखा स्कीम इस अध्याय के चालू लाइसेंसिंग स्कीम के अंतर्गत चलाई जाएगी। यह स्कीम वैकल्पिक होगी तथा जो आयातक/ निर्यातक जो रुपये खाते को चालू रखना चाहते हैं, मौजूदा नीतियों के अन्तर्गत उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी।

ऐसे खातों में डॉलर, बैंक वित्त और/या निर्यात आय से उपलब्ध होगा और इनका प्रयोग केवल

(1) विदेशी/स्थानीय स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों की आयात/खरीद  
(2) स्थानीय स्रोतों से कटे और पालिश हीरों, रंगीन रत्न और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद (3) विदेशी/नामित एजेंसियों से स्वर्ण का आयात/ खरीद तथा बैंक से डॉलर भरणों का भुगतान और (4) निर्यातकों को रुपये लेखा में हस्तांतरण। इस हीरा डॉलर खाता योजना (डी डी ए एस) के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रक्रिया हीरा जड़ित आभूषणों पर भी लागू होगी। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में रेखांकित प्रक्रिया रत्न जड़ित आभूषणों पर लागू होगी।

एक गैर डी डी ए धारक को भी कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति है, भुगतान डालर में मिलेगा तथा इसे 7 दिन के भीतर रूपयों में बदलना होगा। कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की गैर डी डी ए धारक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति को भी उसके निर्यात दायित्व को पूरा किया गया ही माना जाएगा और/या इसे प्रतिपूर्ति लाइसेंस का हक प्राप्त हो जाएगा।

**अध्याय - पाँच****निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम**

ई.पी.सी.जी स्कीम

5.1

पूर्व उत्पादन, उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं (कम्प्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम के साथ उनके रक्त के डी/सी के डी समेत) का 5 प्रतिशत सीमाशुल्क के आधार पर इस योजना के तहत आयात किया जा सकता है बशर्ते कि लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 8 गुणा के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाए ।

कृषि यूनिटों के मामले में, 5 प्रतिशत सीमाशुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात अनुमत होगा बशर्ते कि लाइसेंस जारी होने की तिथि से 12 वर्षों तक बचाए गए शुल्क (स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर) के 6 गुणा के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की गयी है ।

तथापि, लघु उद्योग एककों हेतु, लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक, (स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल पर) बचाए गए शुल्क के 5 गुणा के बराबर निर्यात दायित्व पूरा करने के अधीन, 5 प्रतिशत सीमाशुल्क पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि स्कीम के तहत ऐसे आयातित पूंजीगत माल का पत्तन पर उतरते समय लागत बीमा भाड़ा मूल्य 25 लाख रुपये से ज्यादा न हो तथा ऐसे आयातों के पश्चात प्लांट और मशीनरी में कुल निवेश लघु उद्योग एककों के निवेश सीमा से अधिक न हो ।

तथापि, 100 करोड़ या इससे अधिक के बचाए गए शुल्क वाले ई पी सी जी लाइसेंस के सम्बन्ध में निर्यात दायित्व 12 वर्षों की अवधि में पूरा करना अपेक्षित होगा ।

यदि ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातों पर सी वी डी नकद रूप में अदा किया गया है तो, सी वी डी बचाए गए निवल शुल्क के लिए नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि इसे सेन्वेट न किया गया हो ।

पूंजीगत माल में स्पेयर्स, (नवीकृत स्पेयर्स सहित) औजार, जिग्स, फिक्चर, डाइज और माउल्ड्स शामिल होंगे । लाइसेंसधारक द्वारा

पूँजीगत वस्तुओं के एसेम्बल या विनिर्माण हेतु ऐसी पूँजीगत वस्तुओं के हिस्से-पुर्जों के आयात के लिए ई पी सी जी लाइसेंस भी जारी किया जा सकता है।

ईपीसीजी स्कीम के अधीन पुराने पूँजीगत माल का कालावधि पर बिना किसी प्रतिबन्ध के आयात किया जा सकता है।

तथापि मोटर कारों, खेल कूद के लिए उपयोगी वाहनों/बहुदेशीय वाहनों के आयात की अनुमति केवल होटलों, टूर एजेन्टों, टूर प्रचालकों अथवा टूर परिवहन प्रचालकों और गोल्फ रिजाट्स का स्वामित्व रखने वाली/संचालन करने वाली कम्पनियों को होगी जिनका चालू और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कुल विदेशी मुद्रा अर्जन 1.5 करोड़ रूपए हो। तथापि मोटर कारों, खेल कूद के लिए उपयोगी वाहनों/बहुदेशीय वाहनों के पुर्जों जैसे कि चैसिस इत्यादि ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात नहीं किए जा सकते।

आई टी सी (एच एस) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रतिबन्धित मर्चों के आयात की अनुमति आयात सुविधा समिति से अनुमोदन के बाद स्कीम के तहत दी जाएगी।

- 5.1क स्कीम के तहत मौजूदा प्लान्ट और मशीनरी के लिए आयातित/आयात किए जाने वाले स्पेयर्स (नवीकृत/रीफर्बिस्ड स्पेयर्स सहित), औजार, स्पेयर रिफ्रैक्टरीज, उत्प्रेरक और उपभोग्यों की भी अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि लाइसेंस जारी होने की तिथि से 8 वर्षों तक की अवधि में निर्यात दायित्व बचाए गए शुल्क के 8 गुणा के बराबर हो।

परियोजनाओं के लिए  
ईपीसीजी

- 5.1ख स्कीम के तहत परियोजनाओं के आयात हेतु पूँजीगत माल के आयात के लिए ई पी सी जी लाइसेंस भी जारी किया जा सकता है जो कि सीमाशुल्क छूट प्राप्त अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 01.03.2002 के क्रम. सं. 441 के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित हैं जिसमें आयातों पर मूल सीमाशुल्क 16 प्रतिशत की सी वी डी के साथ 10 प्रतिशत है।

ऐसे ई पी सी जी लाइसेंसों के लिए निर्यात दायित्व बचाए गए शुल्क का आठ गुणा होगा। बचाया गया शुल्क उपर्युक्त सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत प्रभावी शुल्क और ईपीसीजी स्कीम के तहत रियायती शुल्क के बीच का अन्तर होगा।

- खुदरा क्षेत्र हेतु ई पी सी जी 5.1 ग खुदरा क्षेत्र में आधुनिक मूल भूत ढाँचा तैयार करने हेतु खुदरा व्यापारी जिनके पास न्यूनतम आच्छादित क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है, पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए ई पी सी जी स्कीम के तहत रियायती शुल्क का लाभ दिया जा सकता है। खुदरा व्यापारी को निर्यात दायित्व अर्थात् 8 वर्षों में बचाए गए शुल्क का 8 गुणा पूरा करना होगा।
- पात्रता 5.2 इस स्कीम के अंतर्गत सहायक विनिर्माता(ओं) सहित अथवा उनके बिना विनिर्माता निर्यातक/विक्रेता(ओं), सहायक विनिर्माता(ओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातक और सेवा प्रदायक पूंजीगत माल का आयात करने के पात्र हैं।
- पूंजीगत माल के आयात की शर्त 5.3 पूंजीगत माल का आयात, निर्यात दायित्व की पूर्ति तक वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा।
- निर्यात दायित्व 5.4 स्कीम के अन्तर्गत निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-  
 (1) स्कीम के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसी वस्तुओं के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा।  
 (2) उन्हीं वस्तुओं के निर्यात द्वारा भी, जिसके लिए ई पी सी जी लाइसेंस प्राप्त किया गया है निर्यात दायित्व पूरा किया जा सकता है जिन्हें लाइसेंस धारक/विनिर्दिष्ट सहायक विनिर्माता(ओं) की विभिन्न विनिर्माण यूनिटों से प्राप्त, विनिर्मित अथवा उत्पादित किया गया हो।
- जब पूंजीगत माल पूर्व/पश्च उत्पादन के लिए आयात किए गए हों और लाइसेंस स्पेयर्स के आयात के लिए लिया गया है तो लाइसेंस धारक उस प्लान्ट/प्रोजेक्ट से विनिर्मित उत्पादों के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करेगा कि जिससे पूर्व/पश्च उत्पादन पूंजीगत माल/स्पेयर्स संबंधित है।
- ई पी सी जी लाइसेंसधारक द्वारा निर्यात के लिए दी गई सेवाओं अथवा विनिर्मित उत्पादों के लिए भंडारण और वितरण सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए पूंजीगत माल के आयात की अनुमति ईपीसीजी लाइसेंस के तहत होगी।

इस योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में बढ़ाई गयी अवधि यदि कोई हो, सहित कुल निर्यात दायित्व अवधि के अन्दर में उसके द्वारा प्राप्त किए गए उसी उत्पाद और समान उत्पाद प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर, के निर्यातों के औसत स्तर से ज्यादा होगा ।

वैकल्पिक रूप से, ई पी सी जी लाइसेंस धारक द्वारा उसी फर्म/कम्पनी अथवा समूह कम्पनी/प्रबंधित होटल जिनके पास ई पी सी जी लाइसेंस है, में विनिर्मित या प्राप्त अन्य मालों/सेवाओं के निर्यातों द्वारा भी निर्यात दायित्व पूरा किया जा सकेगा ।

तथापि, ऐसे मामलों में, ई पी सी जी स्कीम के तहत लगाया गया अतिरिक्त निर्यात दायित्व मूल और स्थानापन्न उत्पाद(दों)/सेवा(ओं) दोनों हेतु पिछले तीन वर्षों में यूनिट/कम्पनी/समूह कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा किए गए औसत निर्यातों से अधिक होगा, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.7.6 में दिए गए वैकल्पिक उत्पाद(ों)/सेवा (ओं) के लिए औसत में छूट है ।

शेष निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए लाइसेंस धारक द्वारा पूरे किए जाने वाले बढ़ रहे निर्यातों में निर्यातों की वास्तविक उत्पाद/सेवा और वैकल्पिक उत्पाद (ों)/सेवा (ओं) का कोई भी संयोजन हो सकता है । माल का निर्यातक सेवाओं के निर्यात अथवा विलोमतः निर्यात दायित्व पुनः नियत करने का विकल्प चुन सकता है ।

लाइसेंसधारक स्कीम के तहत शेष निर्यात दायित्व के अनुपात में लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए बचाई गई शुल्क राशि के 8 गुणा पर आधारित शेष निर्यात दायित्व को पुनः नियत करने के लिए विकल्प चुन सकता है। निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए दिशा निर्देश प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.19 में दी गई है ।

उपर्युक्त सुविधाएँ केवल विनिर्माता निर्यातकों/सेवा प्रदायकों को सभी लाइसेंसों पर उपलब्ध होंगी जहाँ बढ़ाई गई निर्यात दायित्व अवधि सहित निर्यात दायित्व अवधि आवेदन की तारीख पर वैध है । इस संबंध में वैकल्पिक मद और/या बचाई गई शुल्क राशि पर आधारित निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के



लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर अथवा उसके बाद किए गए निर्यातों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए माना जाएगा ।

(2) इस स्कीम के अधीन प्राप्त किए गए निर्यात दायित्व आयातक द्वारा अग्रिम लाइसेंस, डी एफ आर सी, डी ई पी बी या ड्रॉबैक योजना के अधीन समान उत्पाद के लिए प्राप्त किए गए निर्यात दायित्व के अतिरिक्त होगा।

(3) निर्यात दायित्व डीटीए को आईटीए-1 की आपूर्ति द्वारा भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो ।

(4) निर्यात वास्तविक निर्यात होंगे । तथापि नीति के पैराग्राफ 8.2 (क), (ख), (घ), (च) (छ) और (ज) में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात भी नीति के पैरा 8.3 के तहत उपलब्ध सामान्य लाभों के साथ निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए माने जाएंगे।

आर एण्ड डी सेवाओं के लिए प्राप्त मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान भी ईपीसीजी स्कीम के तहत वसूली के लिए माने जाएंगे । विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 के संबंध में, पतन निर्वहन सेवाओं के लिए रूपए के रूप में प्राप्त भुगतान भी, स्कीम के तहत निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए माना जाएगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकिंग चैनलों के माध्यम से मुक्त विदेशी मुद्रा में “काउण्टर बिक्री” से प्राप्त भुगतान, निर्यात दायित्व की पूर्ति पैरा 5.1ग के अनुसार गिनी जाएगी ।

बीआईएफआर यूनिटों  
के लिए प्रावधान

5.5.1 बी आई एफ आर के साथ पंजीकृत कोई फर्म/कम्पनी या यूनिट खरीदने

वाली कोई फर्म/कम्पनी, जो कि बी आई एफ आर के अधीन है, को संचालन करने वाली एजेन्सी द्वारा तैयार एवं बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापना पैकेज के अनुसार निर्यात दायित्व बढ़ाने की अनुमति होगी ।

तथापि, ऐसे मामलों में, जहाँ पुनः स्थापना पैकेज में निर्यात दायित्व विस्तार की अवधि का उल्लेख न हो, वहाँ निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए मामले के गुणावगुण के आधार पर लाइसेंस जारी करने की तारीख से 12 वर्षों की समयावधि अनुमत होगी।

इसी प्रकार, लघु उद्योग इकाईयाँ भी संबंधित राज्य सरकार की पुनः स्थापना योजना के अनुसार ऐसी ही सुविधा के लिए हकदार होगी । तथापि, ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य पुनः स्थापना योजना में निर्यात दायित्व विस्तार अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई वहाँ निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए मामले के गुण दोष के आधार पर लाइसेंस जारी करने की तारीख से 12 वर्षों की समयावधि अनुमत होगी।

एग्रो इकाईयों के लिए  
ईपीसीजी

5.5.2 कृषि निर्यात क्षेत्रों में कृषि इकाईयों को जारी ई पी सी जी लाइसेंसों के मामले में, निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए लाइसेंस को जारी करने की तारीख से 12 वर्षों की समयावधि अनुमत होगी ।

कृषि निर्यात क्षेत्रों में कृषि इकाईयों को कृषि निर्यात क्षेत्र के भीतर ईपीसीजी के तहत आयातित पूंजीगत माल (i) के स्थानान्तरण की सुविधा भी होगी ।

विधिक वचनबद्धता/बंध पत्र या 15 प्रतिशत बैंक गारंटी (जैसा भी मामला हो) ईपीसीजी लाइसेंस के लिए दिया जा सकता है जो कि कृषि निर्यात क्षेत्रों में इकाईयों को दिया गया है । बशर्ते कि ईपीसीजी लाइसेंस परिशिष्ट 8 में अधिसूचित मुख्य कृषि उत्पाद (i) अथवा उनकी मूल्य संवर्धन वस्तुओं के निर्यात के लिए लिया गया है ।

- स्वदेशी रूप से पूंजीगत माल को प्राप्त करना और घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ 5.6 ई पी सी जी लाइसेंस धारक व्यक्ति पूंजीगत वस्तुएं आयात करने के बजाए इन्हें घरेलू निर्माता से प्राप्त कर सकता है। ई पी सी जी लाइसेंसधारक को पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला घरेलू विनिर्माता नीति के पैरा 8.3 के तहत मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र होगा।
- घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ 5.7 ई पी सी जी लाइसेंस धारक और घरेलू विनिर्माता के बीच ऐसे वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हुए फर्म के करार के मामले में, घरेलू निर्माता उक्त पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण हेतु आवश्यक संघटकों सहित निविष्टियों के आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।
- घरेलू विनिर्माता ई पी सी जी लाइसेंस धारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति के बाद संघटकों सहित निविष्टियों की प्रतिपूर्ति भी कर सकता है।
- निर्यात दायित्व का निर्धारण 5.7क सीधे आयात के मामले में, ई पी सी जी लाइसेंस के संबंध में निर्यात दायित्व को वास्तव में आयातित पूंजीगत माल (इसमें स्पेयर्स, जिग्स, फिक्स्चर्स, डाइज और मोल्ड्स शामिल हैं) के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर बचाये गये शुल्क के अनुसार होगा। घरेलू प्राप्ति के मामले में ई पी सी जी लाइसेंस के संबंध में निर्यात दायित्व को पूंजीगत माल (इसमें स्पेयर्स, जिग्स, फिक्स्चर्स, डाइज और मोल्ड्स शामिल हैं) के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर बचाये गये केन्द्रीय सीमा शुल्क के अनुसार होगा।
- 5.8 कृषि निर्यात क्षेत्रों में सेवा प्रदायकों को कृषि निर्यात क्षेत्रों के भीतर पूंजीगत माल को हटाने या दूसरी जगह ले जाने की सुविधा होगी बशर्ते कि वे ऐसे कार्यकलापों का सही रिकार्ड रखेंगे। तथापि, लाइसेंसधारक द्वारा ऐसे उपकरण बेचे या ठेके पर नहीं दिए जाएंगे।
- ईपीसीजी के तहत औसत निर्यातों का रख रखाव 5.9 पैरा 5.4 (झ) की शर्तों के अनुसार, ईपीसीजी लाइसेंसधारक को निर्यात दायित्व की सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दी गई छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़ कर उसी अथवा समान उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यातों के औसत के बराबर निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखना होगा।

उपर्युक्त के बावजूद, लाइसेंस धारक किसी विशेष वर्ष (i) में औसत निर्यातों का स्तर बनाए रखें बशर्ते कि यह अन्य वर्ष (i) में औसत पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्यातों द्वारा पूरा किया गया हो ।

मौजूदा ई पी सी जी मशीनरी का तकनीकी उन्नयन

5.10 ई पी सी जी लाइसेंस धारक ईपीसीजी लाइसेंस के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन का चुनाव कर सकता है ।

मौजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन को संचालित करने की शर्त निम्नानुसार है:-

(1) ईपीसीजी के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम समयावधि लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 वर्ष है ।

(2) पुराने पूंजीगत माल के तहत किए गए न्यूनतम निर्यात पहले ईपीसीजी लाइसेंस पर लगाए गए कुल निर्यात दायित्व का 40 प्रतिशत होना चाहिए ।

(3) निर्यात दायित्व को इस प्रकार पुनः निर्धारित किया जाएगा कि दोनों पूंजीगत माल के लिए निर्धारित कुल निर्यात दायित्व दोनों पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क की कुल राशि का 6 गुणा होगा ।

(4) पूंजीगत माल की पुनः स्थापना संचालित करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.20 में दी गई है ।

(5) तकनीकी उन्नयन के लिए सुविधा सिर्फ एक बार उपलब्ध होगी और किया जाने वाला न्यूनतम आयात आवेदक फर्म द्वारा प्लांट और मशीनरी में मौजूदा निवेश का कम से कम 10 प्रतिशत होगा ।

फास्ट ट्रैक कम्पनियों के लिए प्रोत्साहन

5.11 स्कीम के तहत निर्यातों को गति प्रदान करने की दृष्टि से फास्ट ट्रैक कम्पनियों को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसे मामलों में जहाँ लाइसेंसधारक ने लाइसेंस में विनिर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व की अवधि के आधे या आधे से कम समय में स्कीम के तहत निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत अथवा अधिक पूरा कर लिया हो (निर्यातों के औसत स्तर सहित), बकाया निर्यात दायित्व को माफ कर दिया जाएगा और संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस को विमुक्त कर दिया जाएगा ।

तथापि, ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैरा 5.12 के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं उपलब्ध होगा ।

## अध्याय - छः

निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क  
(ई एच टी पी) साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी)  
और बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी)

पात्रता

6.1 अपने सारे उत्पादन और सेवाओं (डी टी ए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट (ई. ओ. यू.) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी) योजना साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) योजना या बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी) स्कीम, के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं तथा ऐसी यूनिटें माल के निर्माण सहित मरम्मत, री मेकिंग, री कंडीशनिंग, री-इन्जीनियरिंग और सेवा प्रदान करने में लगी हो सकती हैं। तथापि इन योजनाओं के तहत व्यापारी यूनिट शामिल नहीं है।

माल का निर्यात तथा  
आयात

6.2 (क) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है सिवाय उन मदों के जो आई टी सी (एच एस) में निषिद्ध हैं। विशेष रसायन, जैविक, उपकरण और तकनीकियों (एस सी ओ एम ई टी) का निर्यात किया जायेगा बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों।

(ख) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट, डी टी ए अथवा डी टी ए में बाण्डेड गोदमों अथवा भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी उससे संबंधित गतिविधियों के लिए पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का बिना शुल्क दिए आयात कर सकती है बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मद न हो। किसी अन्य कानून के तहत आयात के लिए अनुमति दी जाएगी। यूनिटों को, ग्राहकों से ऋण पर पूंजीगत वस्तुओं सहित, मुफ्त में या स्वीकृति कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी। पूंजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा।

(ग) निर्यात अभिमुख विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार व्यवस्था लागू नहीं होगी।

(ध) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी में साफ्टवेयर एककों द्वारा प्रयोग के लिए केन्द्रीय सुविधा स्थापित करने हेतु कुछ विशिष्टीकृत वस्तुओं का शुल्क मुक्त रूप से आयात कर सकती हैं या डीटीए से प्राप्त कर सकती है। ये साफ्टवेयर एकक ई ओ यू/डी टी ए एकक हो सकते हैं, जो साफ्टवेयर के निर्यात की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं।

(ड.) कृषि, पशुपालन, जल कृषि, पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगुरोत्पादन, मुर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न निर्यात अभिमुख यूनिटों को बाण्डेड क्षेत्र के बाहर प्रयोग के लिए केवल विशिष्ट माल को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(च) रत्न और आभूषण ई ओ यू यूनिटें नामित ऐजेंसियों से भी सोना/चांदी/ प्लेटिनम प्राप्त करके उनके प्राप्त कर सकती हैं। यूनिटें आभूषणों का निर्यात रिलीज की तारीख से 90 दिन के अन्दर कर देंगी। हालाँकि यह नामित एजेंसियों से कीमती गत्थरों के एकमुश्त खरीद पर लागू नहीं होगा।

(छ) सेवा यूनिटों के अतिरिक्त ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट भारतीय रिजर्व बैंक की क्लियरेंस, यदि कोई हो, के अधीन राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्करो रुपया लेखा के प्रति भारतीय रुपयों में रुस संघ को निर्यात कर सकती है।

(ज) यूनिटों द्वारा विनिर्मित माल के लिए आवश्यक स्पेयर्स और उपभोज्य की खरीद और आपूर्ति, निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5 प्रतिशत तक के माल के निर्यात की अनुमति होगी। तथापि यह रियायती दर डी टी ए बिक्री अथवा आयकर छूट के लिए एन एफ ई गणना में नहीं गिना जाएगा।

पुराना पूजीगत माल

6.3

पुराना पूजीगत माल का बिना किसी आयु सीमा के शुल्क मुक्त आयात भी किया जा सकता है।

- पूँजीगत माल के पट्टे 6.4 पार्टियों के बीच में हुई पक्की संविदा के आधार पर कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिट घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी से बिना सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क का भुगतान किए पूँजीगत माल उठा सकती है। ऐसे मामले में घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी तथा निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ बी टी पी यूनिट शुल्क मुक्त पूँजीगत माल, आयात करने/खरीदने के लिए संयुक्त रूप से आयात दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।
- सकल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) 6.5 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें एक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) उत्पादन प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संघटित रूप से गिना जाएगा।
- अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र और विधिक वचनबद्धता 6.6 (क) अनुमोदन हो जाने पर, विकास आयुक्त/नामित अधिकारी द्वारा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अनुमति पत्र (एल ओ पी)/आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करेगा। एल ओ पी/एल ओ आई का आरम्भ में वैधता अवधि तीन वर्ष होगी जब से यूनिट ने उत्पादन आरम्भ किया होगा। इसकी वैधता अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक वैधता की अवधि से आगे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, छः वर्ष से अधिक के विस्तार के प्रस्ताव पर विशेष परिस्थितियों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। एक बार यूनिट ने उत्पादन आरम्भ कर दिया, तो इसकी गतिविधियों के लिए जारी किए गए अनुमति पत्र/आशय पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा, एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
- (ख) सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई को सभी प्रयोजन के लिए लाइसेंस माना जाएगा।
- (ग) यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की शर्त को अथवा एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल/एल यू टी की शर्तों को न पूरा कर सकने पर वह विदेश व्यापार (विकास और विनियमन)

अधिनियम 1992 और किसी अन्य कानून के तहत नियम तथा आदेश जो बिना पूर्वाग्रह के बने हों, के अधीन दण्ड की भागी होगी और वह एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल रद्द अथवा मंसूख हो जाएगा ।

निवेश मानदण्ड

(घ) जिन परियोजनाओं में संयंत्र और मशीनरी पर 1 करोड़ रुपया न्यूनतम निवेश न हो उन पर ई.ओ.यू. स्कीम के अन्तर्गत स्थापना के लिए विचार किया जाएगा । यह, हालाँकि, मौजूदा यूनिटे और इ एच टी पी/एसटीपी/बीटीपी, हैण्डिक्राफ्ट/कृषि/पुष्पोत्पादन बागवानी/जल कृषि/ पुशपालन/सूचना तकनीकी, सेवाएं ब्रास हार्डवेयर, हस्तनिर्मित आभूषण और बीओए द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होगा ।

आवेदन और अनुमोदन 6.7

ई ओ यू योजना के तहत यूनिटों की स्थापना के लिए आवेदनों पर (क) सेवा क्षेत्र (आर एण्ड डी, साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंध सेवाओं अथवा बी ओ ए द्वारा प्रत्यायोजित अन्य सेवा गतिविधियों को छोड़कर) की यूनिटों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को छोड़कर, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 15 दिनों के भीतर मंजूरी/नामंजूरी दी जा सकती है जो प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करती हो ।

(ख) अन्य मामलों में इस उद्देश्य के लिए गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट के अनुसार मंजूरी दी जाएगी ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ईओयू की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन, अनुमोदन बोर्ड और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्ताव के निपटान के बाद 45 दिन के अन्दर विकास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है।



तैयार उत्पाद/अवशेष/  
स्कrap/शेष और उप-  
उत्पाद की घरेलू टैरिफ  
क्षेत्र (डी टी ए) में  
बिक्री

6.8

निर्यात अभिमुख यूनिटों/इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी  
पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिटों का सारा  
उत्पादन निम्नलिखित के अधीन निर्यात किया जाएगा:-

(क) रत्न और आभूषण यूनिटों को छोड़कर यूनिटों के पोत  
पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल का विक्रय कर  
सकता है बशर्ते कि रियायती शुल्क के भुगतान पर सकारात्मक  
निवल विदेशी मुद्रा के पूर्ति की गई है। डी टी ए बिक्री हकदारी  
के अन्दर इकाइयाँ अपने उत्पादों को डी टी ए में माल जैसे ही  
बेच सकती है। मोटर कार, अल्कोहल युक्त शराब, पुस्तकें और  
चाय (इन्सटैंट टी को छोड़कर) और पुस्तकें या पैकेजिंग/  
लेबलिंग/सैग्रीगेशन/रेफ्रीजरेशन/यूनिट कम्पैक्टिंग/माइक्रोनाइजेशन  
पल्वराइजेशन/ग्रेन्यूलेशन/मोनो-हाइड्रेट रूप के रसायन से  
एनहाइड्रस रूप में परिवर्तन अथवा विलोमत और ऐसी अन्य मदों  
जोकि समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी, के मामले में  
रियायती शुल्क पर कोई डी टी ए बिक्री की अनुमति नहीं दी  
जाएगी।

एस ई जेड में यूनिट को की गई बिक्री भी ई ओ यू द्वारा निर्यात  
के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान  
में रखी जाएगी। बशर्ते कि इन बिक्रियों हेतु किया गया भुगतान ई  
ई एफ सी एकाउण्ट से किया गया हो। डी टी ए को की गई  
बिक्री भी फर्मास्यूटिकल उत्पादों (थोक दवाइयों समेत) के  
पंजीकरण की अपरिहार्य आवश्यकता के मद्दे होगी।

(ख) सेवा के लिए, साफ्टवेयर यूनिटों सहित, डी टी ए में किसी  
भी रूप में बिक्री, आनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत  
पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत /अर्जित विदेशी मुद्रा के 50  
प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का  
भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

(ग) रत्न और आभूषण यूनिटों डी टी ए में पूर्व वर्ष के निर्यात के  
पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती है  
बशर्ते कि नीति निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया गया है।  
सादे आभूषण की बिक्री के संबंध में, प्राप्तकर्ता नामित एंजेंसियो  
से बिक्री पर यथा लागू शुल्क की रियायती दरों का भुगतान  
करेगा। रत्न जड़ित आभूषण के संबंध में, यथा लागू शुल्क का  
भुगतान करना होगा।

(घ) जब तक एल ओ पी में विशेष रूप से निषिद्ध न हुआ तो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से पैराग्राफ 6.8 (क) के तहत यथा लागू शुल्कों के भुगतान पर, डी टी ए में रिजेक्ट्स की कुल सीमा के 50 प्रतिशत तक बिक्री की जा सकती है। ऐसी बिक्री डी टी ए बिक्री हकदारी के मद्दे गिनी जाएगी। निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक रिजेक्ट्स की बिक्री पर एन एफ ई प्राप्त करने की शर्त नहीं होगी।

(ङ) उत्पादन प्रक्रिया या तत्सम्बन्धी प्रक्रिया से निकलने वाले स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का यथा लागू रियायती शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में बिक्री अथवा निर्यात शुल्क मुक्त स्कीम के तहत अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड के अनुसार किया जा सकता है जो निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा। लेकिन ऐसी बिक्री न्यूनतम निवल विदेशी मुद्रा अर्जन की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी। उन मर्दों के संबंध में जो मानदण्ड में शामिल नहीं हैं, विकास आयुक्त आंकड़ों के आधार पर छः माह की अवधि और छःमाह के भीतर की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है, उसे अनुमोदन बोर्ड द्वारा मानदण्ड निर्धारित करवाने होंगे। यूनिटों द्वारा जिन वेस्ट/स्क्रेप/अवशेष की बिक्री डी टी ए बिक्री की पात्रता या डी टी ए बिक्री पात्रता से बाहर बिक्री की अनुमति नहीं है उन पर शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा। स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का भी निर्यात किया जा सकता है।

(च) यदि ऐसे स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जाता है तो उन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा।

(छ) अनुमति पत्र में शामिल उपोत्पाद को डी टी ए में भी बेचा जा सकता है बशर्ते की नीति के पैरा 6.8 (क) की समग्र हकदारी के भीतर लागू शुल्कों के भुगतान और अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया हो। पैरा 6.8(क) की हकदारी के बाहर उपोत्पाद की बिक्री सम्पूर्ण शुल्कों के भुगतान पर भी अनुमत होगी।

(ज) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटों को तैयार उत्पादनों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है जिनका डी टी ए नीति के अधीन पूर्ण शुल्क की अदायगी पर मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है बशर्ते इन यूनिटों ने नीति के अनुसार सकारात्मक निर्धारित निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त किया हो।

(झ) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में, निवल विदेशी मुद्रा और डी टी ए बिक्री हकदारी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी ।

(ज) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री के मामले में जहाँ मूलशुल्क और सी वी डी शून्य है, ऐसी वस्तुओं को शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए उत्पाद कर रहित माना जाएगा ।

(ट) नये ई ओ यू के मामले में अग्रिम घरेलू प्रशुल्क बिक्री की अनुमति होगी जो भेषज यूनिटों के अलावा जहाँ यह प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमानित निर्यातों पर आधारित होगी के अतिरिक्त पहले वर्ष के लिए अनुमानित निर्यातों का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 6.9  
अन्य आपूर्तियां

अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पूरा करने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगी:-

(क) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस/शुल्क छूट के तहत डी एफ आर सी/विमुक्ति योजना/ई पी सी जी स्कीम के धारकों के संबंध में डी टी ए में की गई आपूर्तियां;

(ख) डीटीए में क्रेता के एक्सचेंज अर्नस फॉरेन करंसी (ई ई एफ सी) खाते से भुगतान के प्रति डी टी ए में और विदेशों से विदेशी मुद्रा प्रेषण के प्रति की गई आपूर्तियां।

(ग) अन्य निर्यातान्मुख इकाई/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बायोटेक्नोलोजी पार्क/एस ई जेड इकाई को आपूर्ति इन यूनिटों द्वारा ऐसे माल की खरीद के लिए अनुमति नीति के पैराग्राफ 6.2 के अन्तर्गत की जायेगी।

(घ) नीति के और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडेड गोदाम विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों में की गई आपूर्तियां, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है ।

(ड.) माल और सेवाओं की आपूर्ति ऐसे संगठनों जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं।

(च) निर्यात से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति (सेवा यूनिटों द्वारा) मुक्त विदेशी मुद्रा के लिए अथवा ऐसी सेवाओं के लिए जिनका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा के बदले भारतीय रुपये में किया गया हो।

(छ) सूचना तकनीकी समझौता (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकाम/इलेक्ट्रानिक मदों की आपूर्ति।

अन्यों के माध्यम से निर्यात 6.10

एक ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट, अपने द्वारा विकसित विनिर्मित माल/साफ्टवेयर का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-6.19 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दूसरे निर्यातक अथवा किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड यूनिट के माध्यम से कर सकती है।

डी.टी.ए. से आपूर्तियों हेतु हकदारी

6.11

(क) निर्यातोन्मुख/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी की यूनिटों को घरेलू हकदारी टैरिफ क्षेत्र से की गई आपूर्तियों को “मान्य निर्यात” समझा जाएगा और डी टी ए आपूर्तिकर्ता निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, के अलावा नीति के अध्याय 8 के अधीन संगत हकदारियों के लिए पात्र होगा। उपरोक्त के बावजूद, उपयुक्त डिसक्लेमर प्रस्तुत करने पर नीति के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट के अनुसार ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें हकदारी प्राप्त करने के योग्य होंगी। मान्य निर्यात शुल्क वापसी का दावा करने के लिए जहाँ भी वापसी की सभी उद्योग दरें उपलब्ध नहीं हैं, विकास आयुक्त द्वारा ब्राण्ड दरें निर्धारित करवाई जाएँगी।

(ख) बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर और प्रसंस्कृत मोतियों का डी टी ए से ई ओ यू को आपूर्ति करने वाले प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मदों के लिए और दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ग) इसके अलावा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड यूनिट निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे।

- (1) भारत में विनिर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति ;
- (2) भारत में विनिर्मित वस्तुओं पर, डी टी ए से खरीदी गई वस्तुओं पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट ।
- (3) हटा दिया गया है ।
- (4) घरेलू तेल कंपनियों से प्राप्त ईंधन पर अदा शुल्क को समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी की दर से लौटा दिया जाएगा ।
- (5) सेनवैट क्रेडिट पर सेवा शुल्क के भुगतान से छूट

अन्य हकदारियाँ

6.12 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों की अन्य हकदारियाँ निम्नलिखित हैं :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के उपबन्धों के अनुसार आयकर के भुगतान से छूट ।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट

(ग) हटा दिया गया है ।

(घ) निर्यात आय को 12 महीनों के भीतर प्राप्त करना होगा ।

(ङ.) ई ई एफ सी खाते में 100 प्रतिशत निर्यात अर्जन की अनुमति होगी ।

(च) यूनिटों को आयात करते समय या डी टी ए में जाब कार्य करते समय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन मामलों में यूनिट का (1) कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है (2) यूनिट कम से कम 3 वर्षों से मौजूद है और (3) यूनिट का साफ सुथरा ट्रैक रिकार्ड है ।

(छ) एस ई जेड यूनिटों की तरह हो आटोमैटिक रुट के जरिए 100 प्रतिशत एफ डी आई निवेश की अनुमति दी जाएगी ।

अन्तर यूनिट  
हस्तांतरण

6.13 (क) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जेड यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी।

(ख) संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी तथा विकास आयुक्त को पूर्व सूचना देकर पूंजीगत वस्तुओं को किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जेड यूनिटों को हस्तांतरित या ऋण पर दिया जा सकता है।

(ग) किसी एक यूनिट द्वारा किसी दूसरे ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को वस्तुओं की आपूर्ति, दूसरे यूनिट द्वारा डी टी ए बिक्री पर शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए दूसरे यूनिट के लिए आयातित वस्तुएँ मानी जाएंगी।

उप-ठेके

6.14 (क)(1) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट जिनमें रत्न और आभूषण यूनिटें शामिल हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की वार्षिक अनुमति के आधार पर डी टी ए में यूनिटों द्वारा फुटकर ठेके के आधार पर माल के रूप और किस्म में परिवर्तन करना भी शामिल है, का डी टी ए में उप ठेके पर उत्पादन प्रक्रिया कर सकती है।

(2) ये यूनिटें सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से डी टी ए में जॉब वर्क के उप ठेके के लिए मूल्य की शर्तों में पिछले वर्ष के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक भी उप ठेके पर दे सकते हैं।

(ख) (1) ई ओ यू यूनिटों को डीटीए निर्यातक के बदले में निर्यात हेतु जॉब वर्क की अनुमति दी जा सकती हैं बशर्ते माल को ई ओ यू यूनिटों से सीधे निर्यात किया जाए और निर्यात दस्तावेज डीटीए/ईओयू यूनिट के नाम में संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। ऐसे निर्यात हेतु शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए शुल्क को वापिस लेने के लिए डीटीए यूनिटें हकदार होंगी।

(2) जॉब वर्क के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा ई ओ यू को दिए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि कोई डी टी ए क्लीयरेंस न दी जाए।

(3) युनिट में रखे गये रिकार्ड के अनुसार अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जैड/बी टी पी एककों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उप ठेके की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना शुरू कर सकते हैं।

(4) विकास आयुक्त के अनुमोदन से विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में उप ठेके की अनुमति दी जाएगी।

(ग) जाब वर्कर के कार्य स्थल में पैदा हुए स्क्रेप/वेस्ट/टूकड़ों को या तो जाब वर्कर के कार्य स्थल से लागू शुल्क के भुगतान पर दिया जा सकता है या सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता यूनिट को वापिस किया जा सकता है। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों को नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) रत्न और आभूषण ई ओ यू इकाइयों द्वारा अन्य ई ओ यू/ एस ई जैड/ डीटीए इकाइयों में उपठेका/ विनिमय प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।

प्रयोग न किए गए  
माल की बिक्री

6.15 क) यदि कोई निर्यातानुमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी की यूनिट से आयातित या डी टी ए से प्राप्त किए गये माल और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है तो (1) यह अन्य ई ओ यू/एसईजैड/ इ एच टी पी / एस टी पी/बी टी पी इकाइयों को हस्तांतरित कर सकती है या (2) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से आयात लाइसेंस सौंपकर और लागू शुल्कों का भुगतान करके, यदि आवश्यक हो डी टी ए में उनका निपटान या (3) निर्यात कर सकती है। एक ई ओ यू/ई एचटीपी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ऐसे यूनिटों को किए गये मालों का हस्तांतरण प्राप्त कर्ता इकाई के लिए आयात माना जाएगा।

(ख) पूंजीगत वस्तुएं और पुराने/अतिरिक्त कल पूर्ण का निर्यात या अन्य ई ओ यू / ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी/एस ई जैड इकाइयों को हस्तांतरण या लागू शुल्क के भुगतान के बाद डी टी ए में निपटान किया जा सकता है। डी टी ए में निपटान की स्थिति में यथा लागू मूल्यहास का लाभ लागू होगा। यदि पूंजीगत माल कच्चा माल, उपभोज्य कलपूर्ण, वनिर्मित माल, प्रसंसाधित या पैकिंग किया गया और स्क्रेप/वेस्ट/रैमनेन्ट्स/रद्द माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करने के बाद यूनिट के भीतर नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से यूनिट के बाहर नष्ट करने

पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों पर उपर्युक्त विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।

(ग) वस्त्र क्षेत्र के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य या आयात की मात्रा, जो भी कम हो, के 2 प्रतिशत तक बचे हुए माल/कपड़े का निपटान सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमत होगा बशर्ते केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क अधिकारी यह प्रमाणित करें कि यह बचा हुआ माल है।

(घ) इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी।

रिक्विजिटिंग/मरम्मत और पुनः इंजिनियरिंग करना 6.16 निर्यातोनमुख/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी क्षेत्र की यूनिटों को रिक्विजिटिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजिनियरिंग जैसे कार्यों के लिए तथा विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए अनुमोदन बोर्ड की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। ऐसे यूनिट उपयुक्त कार्यों के लिए किसी भी किस्म के माल का आयात कर सकते हैं। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29 और नीति के पैराग्राफों 6.8, 6.9, 6.10, 6.13 व 6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।

आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत 6.17 (क) प्रतिस्थापन/मरम्मत वस्तुओं के निर्यात के संबंधित नीति के सामान्य प्रावधान ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों पर भी एक समान लागू होंगे यद्यपि प्रावधान के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) डी टी ए में बेची गई वस्तुएं और खराब पाई गई वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क/उत्पाद प्राधिकारियों की सूचना में मरम्मत/ बदलने के लिए लाया जा सकता है।

(ग) आयात करने पर/स्वदेशी रूप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके का हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं/लौटाए और प्रतिस्थापन प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामलों में वस्तुएं विदेशी संभरकों अथवा भारत में उनके अधिकृत संभरकों/स्वदेशी संभरकों से वापिस ली जा सकती है।



तथापि कीमती और अर्द्धकीमती धातुओं पर विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।

ईओयू योजना से  
बहिर्गमन

6.18 (क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से निर्यात अभिमुख यूनिट इस योजना को छोड़ सकती हैं। उस समय लागू सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान करने पर और बहिर्गमन से संबंधित निवर्तमान औद्योगिक नीति के तहत इस योजना को छोड़ा जा सकता है।

(ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व को प्राप्त नहीं किया है तो योजना से बहिर्गमन, के समय उसे जुर्माना देना होगा।

(ग) रत्न व जेवरात यूनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य धातु, मिश्रधातु, रत्न व अन्य सामग्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा नामित ऐजसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर हस्तांतरित करनी पड़ेगी।

(घ) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट के अनुसार मानक शर्तों और उस योजना के अधीन पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करने वाले निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को एक बार के विकल्प के रूप में मौजूद ई पी सी जी योजनाओं के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क को भुगतान करने पर विकास आयुक्त द्वारा योजना छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

(ङ.) ई ओ यू योजना को छोड़ने का प्रस्ताव करने वाले यूनिटों को विकास आयुक्त/सीमाशुल्क प्राधिकारी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को लिखित में सूचित करना होगा। यूनिट डिबांडिंग के कारण उत्पन्न शुल्क संबंधी दायित्व का मूल्यांकन करेगा और ऐसे मूल्यांकन के ब्यौरे सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों को भेजेगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी प्राथमिकता के आधार पर दायित्वों की पुष्टी करेंगे। शुल्क के भुगतान तथा सभी शुल्कों का भुगतान कर देने के पश्चात युनिट सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से “बेबाकी प्रमाण-पत्र” प्राप्त करेगा। सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा जारी “बेबाकी प्रमाण-पत्र” के आधार पर युनिट अन्तिम रूप से डिबांडिंग के लिए विकास आयुक्त को आवेदन करेगा। यदि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत कोई मामला लंबित न होने पर विकास आयुक्त 7 कार्य दिवसों के भीतर

अन्तिम डिवाइडिंग आदेश जारी कर देगा। सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए “बेबाकी प्रमाण-पत्र” और विकास आयुक्त द्वारा जारी किया गया अन्तिम डिवाइडिंग आदेश में बीच की अवधि के दौरान युनिट पूंजीगत माल अथवा निविष्टी को प्राप्त करने के लिए किसी छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

तथापि वे अग्रिम लाइसेंस/डी ई पी बी/डी एफ आर सी/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं।

(च) जिन मामलों में यूनिट ने लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात विदेश से या उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के पश्चात घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डी टी ए यूनिट स्थापित किया गया है, और जिसे बाद में ई ओ यू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में डीबान्डिंग के पश्चात डी टी ए में ऐसी पूंजीगत वस्तुएँ तो जाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार ई पी सी जी योजना के तहत यहाँ डी टी ए यूनिटों के रूप में पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है और ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात और स्वयं को ई ओ यू में परिवर्तित करवाने पर यूनिट से डी टी ए ऐसी पूंजीगत वस्तुओं को ले जाते समय पूंजीगत वस्तुओं से सीमाशुल्क नहीं लिया जाएगा।

#### परिवर्तन

6.19 (क) मौजूदा डी टी ए यूनिटें भी किसी निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती है और पहले से स्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के लिए योजना के अन्तर्गत आयकर अधिनियम की धारा 10(क) और 10(ख) के तहत लाभ उपलब्ध होंगे।

(ख) विद्यमान ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटें, ई ओ यू यूनिट में परिवर्तन/समाहित होने के लिए अथवा विलोमतः आवेदन कर सकती है। ऐसे मामलों में यूनिटें बांड के अधीन होंगी तथा संबद्ध योजनाओं के तहत लागू ड्यूटी एवं टैक्स छूट का लाभ उठा सकती है।

#### एन एफ ई की निगरानी

6.20 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी एकक अनुमोदन समिति के द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार निगरानी की जाएगी।

- प्रदर्शनी के माध्यम से निर्यात/निर्यात प्रोत्साहन यात्रा/विदेशी शो रूम के जरिए निर्यात/शुल्क मुक्त दुकानें
- 6.21 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें निम्नलिखित के हकदार होंगे:
- (1) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शन करने/शामिल होने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना ।
  - (2) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनियम जेबरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, माणिक व अन्य व्यक्तिगत सामान।
  - (3) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों में प्रदर्शन/विक्रय के लिए मालों का निर्यात।
  - (4) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों या उनके वितरकों/एजेन्टों के शो रूम में प्रदर्शन/बिक्री हेतु निर्यात।
  - (5) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शो रूम/खुदरा दुकानों की स्थापना।
- वैयक्तिक सामानों का आयात/विदेशी बांड पैसेन्जर सहित निर्यात पार्सल
- 6.22 रत्न और आभूषणों का आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अधीन किया जा सकता है। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनलों के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। रत्न और आभूषण ईकाई के अलावा अन्य यूनिटों के लिए आयात निर्यात व्यक्तिगत रूप से करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में हो,
- डाक/कोरियर द्वारा निर्यात/आयात
- 6.23 निःशुल्क नमूनों सहित अन्य मालों को सीमा शुल्क नियमों के अधीन हवाई जहाज या विदेश डाक खाना या कोरियर द्वारा निर्यात/आयात किया जा सकता है।
- ई ओ यू यूनिटों का प्रशासन/विकास आयुक्त को प्रदत्त शक्तियाँ
- 6.24 ई ओ यू यूनिटों के प्रशासन और विकास आयुक्त को प्रदत्त शक्तियाँ का ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।
- रुग्ण यूनिटों का पुनरुत्थान
- 6.25 उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित करने पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के पुनरुत्थान या अधिग्रहण के लिए विचार किया जा सकता है।
- ई एच टी पी/एस टी पी के लिए अनुमोदन
- 6.26 ई एच टी पी/एस टी पी योजनाओं के अधीन यूनिटों के मामलों में इस अध्याय के संबंधित पैरा के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति के विकास आयुक्त के बजाए सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा और अनुमोदन बोर्ड के बजाए अंतर्मंत्रालय स्थायी समिति (आई एम एस सी) द्वारा दी जाएगी।

बी टी पी का  
अनुमोदन

6.27 जैव प्रौद्योगिकी पार्कों (बी टी पी) को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जाए। बी टी पी में यूनिटों के मामले में इस अध्याय के संबद्ध उपबन्धों के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रौद्योगिकी विभाग के नामजद अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

### अध्याय - 7

#### विशेष आर्थिक क्षेत्र

टिप्पणी: विशेष आर्थिक ज़ोन एस ई जेड विकास के वे स्त्रोत है जो विनिर्माण कार्यकलापों को बढ़ावा दे सकते हैं, निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं और रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। निजी क्षेत्र को एसईजेड के विकास के साथ सक्रिय रूप से संबद्ध किया गया है। एसईजेड के लिए विशेष राजकोषीय और विनियन्त्रक तन्त्र की आवश्यकता है ताकि स्टेट आफ द आर्ट बुनियादी सुविधाओं और सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मुक्त संचालक तन्त्र विकसित किया जा सकता है। एसईजेड के संबंध में प्रस्तावित विधेयक निकट भविष्य में पारित किया जाने वाला है जो विकासकर्ता और सह विकासकर्ता की अवधारणा, वास्तविक एसईजेड के प्रावधान, आयकर अधिनियम और सीमाशुल्क अधिनियम के तहत वित्तीय रियायतें, ऑफसोर बैंकिंग यूनिटों के लिए प्रावधान शामिल किये जाएंगे। एसईजेड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में एक संक्षिप्त नोट नीचे दिया गया है :-

पात्रता

7.1 (क) विशेष आर्थिक क्षेत्र एक खास तौर से शुल्क मुक्त क्षेत्र है और यह व्यापार कार्यकलापों तथा शुल्क और प्रशुल्क के प्रयोजनों के लिए एक विदेशी क्षेत्र माना जाएगा।

(ख) डी टी ए से एस ई जेड में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को मान्य निर्यात माना जाएगा और एस ई जेड से डी टी ए में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को आयात की गई वस्तुएं माना जाएगा।

(ग) एस. ई. जेड. एककों की स्थापना वस्तुओं के विनिर्माण और सेवाएं प्रदान करने हेतु की जा सकती है।

वस्तुओं का निर्यात और  
आयात

7.2 (क) एस ई जेड एकक, आई टी सी (एच एस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित सामान के अलावा कृषि उत्पादों, आंशिक रूप से प्रसंस्कृत सामग्री, सब-एसेम्बलीज और संघटकों सहित वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकते हैं। यह उपोत्पादों, अस्वीकृत माल, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वेस्ट स्क्रेप का भी निर्यात कर सकते हैं। विशेष रसायन, जैविकों, सामग्रियों, उपकरणों और टैक्नालाजी (एस.सी.ओ.एम.ई.टी) का निर्यात, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

व्यापार/सेवा यूनिट को छोड़कर एस ई जेड यूनिट, रूस संघ को भी राज्य क्रेडिट/स्क्रो रुपया लेखा के भुगतान के प्रति भारतीय

रुपयों में निर्यात कर सकता है बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक की निकासी, यदि कोई हो, प्राप्त हो ।

(ख) एस. ई. जेड एकक अपने कार्यकलापों या इससे संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक तथा नीति में यथा-परिभाषित पूंजीगत वस्तुओं सहित, चाहे नई हों या पुरानी, सभी प्रकार की वस्तुओं के शुल्क के भुगतान के बिना आयात कर सकते हैं और डीटीए से खरीद सकते हैं बशर्ते ये आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मदें न हों । तथापि, किसी अन्य नियम के तहत आयात हेतु अपेक्षित अनुमति लागू होगी । वस्तुओं में उपयोग के लिए पूंजीगत माल के विनिर्माण हेतु कच्चा माल शामिल है । इन एककों को बिना लागत के या ग्राहकों से ऋण के रूप में पूंजीगत वस्तुओं सहित स्वीकृत कार्यकलापों के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात करने की भी अनुमति होगी।

(ग) एस. ई. जेड. एकक नीति के तहत नीति के अनुसार/अथवा सीमा शुल्क अधिनियम के धारा 65 के अधीन तथा भारत में अयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों डी टी ए में स्थापित बांडेड गोदामों से शुल्क का भुगतान किए बिना आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकती हैं।

(घ) एस. ई. जेड एकक, एस ई जेड एकको द्वारा उपयोग के लिए केन्द्रीय सुविधाएँ स्थापित करने हेतु भुगतान के बिना सभी किस्मों की वस्तुओं का आयात/डी टी ए से खरीद कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर विकास के लिए केन्द्रीय सुविधा सॉफ्टवेयर के निर्यात हेतु डीटीए में एककों द्वारा बढ़ोतरी भी की जा सकती है।

(ङ.) रत्न और आभूषण एकक नामजद अभिकरणों के जरिए स्वर्ण/चांदी/ प्लैटिनम भी प्राप्त कर सकते हैं।

(च) एस. ई. जेड. एकक, जोन में यूनिटों की स्थापना/संचालन/रख-रखाव करने के लिए डी. टी. ए. से माल का शुल्क भुगतान किए बिना आयात/खरीद भी कर सकते हैं।

पूंजीगत वस्तुओं को  
पट्टे पर देना

7.3

एस. ई. जेड एकक पार्टियों के बीच पक्के ठेके के आधार पर घरेलू/विदेशी पट्टा कम्पनी से पूंजीगत वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में एस ई जेड यूनिट और घरेलू/विदेशी पट्टा कम्पनी, संयुक्त रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करेगी ताकि शुल्क के भुगतान के बिना पूंजीगत वस्तुओं का आयात/प्राप्ति संभव हो सके।

- निबल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) 7.4 एस ई जेड एकक सकारात्मक निबल विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला एकक होगा। निबल विदेशी मुद्रा अर्जन परिकलन, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अध्याय-7 में दिए गए फार्मूले के अनुसार वार्षिक उत्पादन शुरू होने से पाँच वर्षों की अवधि के लिए संचित रूप से किया जाएगा।
- कार्य निष्पादन की मानिट्रिंग 7.5 (क) एस ई जेड एककों के कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग एकक अनुमोदन समिति द्वारा की जाएगी।  
(ख) एस. ई. जेड एककों के कार्य निष्पादन की मानिट्रिंग प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14-I छ में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार की जाएगी।
- विधिक वचन-बद्धता 7.6 एकक संबंधित विकास आयुक्त के साथ एक विधिक वचनबद्धता निष्पादित करेगा और सकारात्मक विदेशी मुद्रा अर्जन न कर पाने की स्थिति में विधिक बचनबद्धता या उस समय लागू अन्य किसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है।
- अनुमोदन और आवेदन 7.7 (क) सेवा क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के अतिरिक्त एस ई जेड में इकाई स्थापित करने के लिए (सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित बिक्री एवं अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अन्य सेवाओं को छोड़कर) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट -14-I-ख में यथा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 15 दिन के भीतर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अथवा निरस्त कर दिया जाएगा। अन्य सभी मामलों में अनुमोदन की स्वीकृति अनुमोदन बोर्ड द्वारा दी जाएगी।  
(ख) औद्योगिक लाइसेंस हेतु एस ई जेड में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव पर एस ई जेड बोर्ड की स्वीकृति के बाद विकास आयुक्त अनुमोदन कर सकते हैं। इसके लिए औद्योगिक नीति एवं उन्नयन की सहमति के 45 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा।
- डी टी ए बिक्री और आपूर्तियाँ 7.8 (क) एस.ई.जेड एकक, उस समय लागू आयात नीति के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करके डी.टी.ए. में उपोत्पादों और सेवाओं सहित वस्तुओं की बिक्री कर सकता है।  
(ख) सेवा/व्यापार एककों द्वारा डी.टी.ए. बिक्री संचित रूप से सकारात्मक निबल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के अधीन होगी।

इस प्रकार जो इकाइयाँ एकल एल ओ पी के मध्य विनिर्माण और सेवा/व्यापार कार्य-कलाप करती हैं उनकी डी टी ए बिक्री, संचित शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की प्राप्ति के अधीन होगी।

(ग) एस ई जेड एककों द्वारा डी टी ए में की गई निम्नलिखित आपूर्तियाँ सकारात्मक निबल विदेशी मुद्रा अर्जन को पूरा करने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

(1) नीति के अध्याय 8 के अनुसार डी टी ए में की गई आपूर्तियाँ।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडिड गोदामों को की गई आपूर्तियाँ।

(3) अन्य ई ओ यू/एस ई जेड/ई एच टी पी/एस टी पी एककों को की गई आपूर्तियाँ बशर्ते कि ऐसे माल यूनिटों द्वारा प्राप्ति के लिए अनुमत हैं।

(4) वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की विशेष हकदारी के तहत आपूर्तियाँ।

(5) संगठनों को माल और सेवाओं की आपूर्ति जिनकी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना की शर्तों पर ऐसी मदों का मुक्त आयात करने की पात्रता है।

(6) मुक्त विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपयों में की गई ऐसी सेवाओं के लिए प्रदत्त निर्यात से संबंधित सेवाओं (सेवा यूनिटों द्वारा) की आपूर्ति जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान माना गया है।

(7) सूचना और तकनीकी समझौता (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलीकाम/इलेक्ट्रानिक मदों की आपूर्तियाँ। प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-14Iग में उल्लिखित है।

डी टी ए से आपूर्ति  
हेतु हकदारी

7.9 डी टी ए से एस ई जेड को आपूर्ति वाली यूनिटें निम्नलिखित के लिए पात्र होंगी :-

(क) डी टी ए आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित के हकदार होंगे-

- (1) शुल्क वापसी/डी इ पी वी/डी एफ आर सी/अग्रिम लाइसेंस ।
- (2) आपूर्ति कर्ता द्वारा निर्यात निष्पादन, यदि कोई हो पूरा करना ।

(ख) एस. ई. जेड यूनिटें निम्नलिखित की पात्र होगी,

- (1) केन्द्रीय बिक्री कर से छूट,
- (2) यूनिटों द्वारा प्राप्ति के लिए योग्य सभी वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर छूट,
- (3) हटा दिया गया है ।
- (4) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित ऐसी अधिसूचना की तारीख से शुल्क वापसी की दर पर डी टी ए से खरीदे गए ईंधन या किसी अन्य वस्तुओं पर भुगतान किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(ग) घरेलू टैरिफ क्षेत्र से एस ई जेड में स्थित एककों को बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित दरों और मर्दों के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस पाने के पात्र होंगे।

(घ) उपर्युक्त पैराग्राफ (क) तथा (ख) (ii) के अधीन पात्रता उस आपूर्ति के लिए उपलब्ध होगी जो माल देश में विनिर्मित हो।

स्तर धारकों के माध्यम  
से निर्यात

7.10 एस ई जेड एकक, उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं/विकसित सॉफ्टवेयर इस नीति के तहत मान्यता प्राप्त व्यापारिक निर्यातक/स्तरधारक या किसी अन्य ई ओ यू/ एस ई जेड/ई एच टी पी/एस टी पी एकक के माध्यम से निर्यात भी कर सकता है।



अन्तर यूनिट हस्तांतरण 7.11 (क) एस ई जेड यूनिट, एक एस ई जेड यूनिट से अन्य एस ई जेड/ ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट को आंशिक प्रसंसाधित/अर्ध-संसाधित माल या सेवाओं सहित विनिर्मित माल का हस्तांतरण कर सकता है।

(ख) किसी एस ई जेड यूनिट, उसी एस ई जेड के भीतर किसी अन्य यूनिट को उस आयातित प्राप्त माल का हस्तांतरण कर सकता है या उधार दे सकता है जिसे बाकायदा गिना जाएगा लेकिन निर्यात निष्पादन की पूर्ति हेतु नहीं गिना जाएगा।

(ग) आयातित/खरीदे गए पूंजीगत माल का विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से अन्य एस ई जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट को हस्तांतरण कर सकता है या उधार दे सकता है।

(घ) सब पैरा (क) और (ख) के अनुसार उसी एस ई जेड में माल के हस्तान्तरण के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी परन्तु यूनिट कार्य का पूरा लेखा-जोखा रखेगी।

अन्य हकदारी

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अध्याय-7 में एस ई जेड की अन्य हकदारी का उल्लेख किया गया है।

उप-ठेका

7.12 (क) एस ई जेड एकक सीमाशुल्क प्राधिकारी की वार्षिक अनुमति से डी टी ए में एककों या अन्य एस ई जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी के माध्यम से अपने उत्पादन के हिस्से या उत्पादन प्रक्रिया का ठेका दे सकता है। उत्पादन प्रक्रिया के भाग के उप-ठेके की विदेश में अनुमति विकास आयुक्त की मंजूरी से दी जा सकती है

(ख) अन्य एस ई जेड/ई ओ यू अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में यूनिटों के माध्यम से एस ई जेड रत्न और आभूषण एककों द्वारा उप ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(1) जड़ित आभूषणों सहित तैयार या अर्द्ध-तैयार वस्तुओं जिन्हें उप ठेकेदारी के लिए क्षेत्र से बाहर ले जाया गया है को 90 दिन के भीतर जोन में वापिस लाया जाएगा। इसके अलावा किसी कटे और पालिश किए हुए हीरे, बहुमूल्य या अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों (शून्य शुल्क वाले बहुमूल्य या अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों को छोड़कर) को उप ठेके के लिए जोन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(2) बराबर मात्रा और शुद्धता के स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के बदले में डी टी ए से सादा स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम जैसा भी मामला हो, के आभूषण प्राप्त करना।

(3) उप ठेके हेतु और अदला-बदली के प्रति यथा लागू एस ई जेड यूनिटें वेस्टेज हेतु पात्र होंगी ।

(4) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के बदले जोब वर्क या आभूषण की आपूर्ति का कार्य हाथ में लेने वाला डी टी ए एकक मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र नहीं होगा।

(ग) रत्न और आभूषण एकक सहित सभी एकक सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति के बिना उसी एस ई जेड में अन्य एककों के माध्यम से उत्पादन के हिस्से या उत्पादन प्रक्रिया को उप-ठेके पर दे सकते हैं जो कि आपूर्ति करने वाले और वस्तुओं को प्राप्त करने वाले एककों दोनों द्वारा रिकार्ड रखने की शर्तों के अधीन होगा ।

(घ) रत्न और आभूषण एककों के अलावा, एस ई जेड एककों को डी टी ए निर्यातक की ओर से निर्यात के लिए जॉब वर्क लेने की अनुमति होगी बशर्ते तैयार वस्तुएं एस ई जेड एककों से सीधे ही निर्यात की जाएं । ऐसे निर्यात के लिए डी टी ए एकक शुल्क वापसी की ब्रान्ड दर की वापसी के पात्र होंगे।

(ङ.) जाब वर्क से उत्पन्न स्क्रेप/वेस्ट/रेमेनेन्ट्स को लागू शुल्क का भुगतान करके जाब वर्कर के परिसर से निकास किया जाएगा या एकक को वापिस किया जाएगा।

(च) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अध्याय-7 में उल्लिखित प्रक्रिया की शर्तों के अधीन सीमा शुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर कृषि/बागवानी उत्पादों के उत्पादन/प्रसंसाधन में लगी हुई एस ई जेड यूनिटें, निविष्टि तथा उपकरण को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र कृषि क्षेत्र को सौंप सकती है।

एस ई जेड योजनाओं  
से बहिर्गमन

7.13 (क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से एस ई जेड एकक स्कीम से बाहर रह सकते हैं। स्कीम से ऐसा बहिर्गमन आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं, कच्चा माल आदि और स्टॉक में तैयार वस्तुओं पर लागू सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान की शर्तों के अधीन होगी। यदि एकक ने सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं की है तो यह बहिर्गमन दण्ड के अधीन होगा जिसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत न्याय निर्णय प्राधिकारी द्वारा लगाया जाएगा।

(ख) एक बार के विकल्प के रूप में एस ई जेड एक को विकास आयुक्त द्वारा मौजूदा ई पी सी जी किसी योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने पर एस ई जेड स्कीम से बहिर्गमन की अनुमति दी जाएगी बशर्ते एकक इस योजना के पात्रता संबंधी मानदण्डों और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट - 14-18 के अनुसार बहिर्गमन की मानक शर्तों को पूरा करे।

समारोह/निर्यात संवर्धन  
दौरों/विदेशों में शो-रूम  
के माध्यम से  
निर्यात/शुल्क मुक्त  
दुकानों के माध्यम से  
निर्यात

7.14 विशेष आर्थिक क्षेत्र एकक:-

- (1) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में आयोजित समारोह में होल्डींग/विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यात कर सकते हैं।
- (2) सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों, बहुमूल्य, अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों, बीड्स एवं वस्तुओं की व्यक्तिगत ढुलाई।
- (3) विदेश में स्थापित अनुमति प्राप्त दुकानों पर प्रदर्शन/बिक्री के लिए आभूषणों के निर्यात की भी अनुमति है।
- (4) विदेश में स्थापित अनुमति प्राप्त दुकानों या इनमें वितरकों/एजेंटों के शोरूम में प्रदर्शन/बिक्री।
- (5) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शोरूम/खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना।

निर्यात/आयात पार्सल  
का व्यक्तिगत असबाब

7.15 रत्नों एवं आभूषणों के आयात/निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत असबाब के तौर पर ले जाने की अनुमति सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी। रत्न और आभूषण यूनिटों के अलावा यूनिटों के लिए व्यक्तिगत असबाब द्वारा आयात निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि माल व्यावसायिक मात्रा में नहीं हो।

- डाक/कुरियर द्वारा  
निर्यात/ आयात 7.16 मुफ्त नमूने सहित वस्तुओं का एयरकुरियर या विदेशी डाकघर या कुरियर के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि इसकी प्रक्रिया सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी हो।
- खराब माल/  
स्क्रेप/वेस्ट/ अपशिष्ट  
का निपटारा 7.17 उत्पादन प्रक्रिया या इससे संबंधित कार्यकलापों से बने खराब माल/स्क्रेप/वेस्ट/अपशिष्ट को लागू शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में बेचा जा सकता है। सीमाशुल्क प्राधिकारी को सूचित करके जोन के भीतर स्क्रेप/वेस्ट/अपशिष्ट/खराब माल को नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति से एस ई जेड के बाहर नष्ट करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। उपरोक्त के अनुसार, नष्ट करना स्वर्ण, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती तथा अर्द्ध कीमती पत्थरों पर यह लागू नहीं होगा।
- वस्तुओं की प्रतिस्थापन/  
मरम्मत 7.18 (क) प्रतिस्थापित/मरम्मत की गई वस्तुओं के निर्यात संबंधित नीति के प्रावधान एस ई जेड एककों पर भी समान रूप से लागू होंगे, इसके अलावा, जो मामले इन प्रावधानों के तहत नहीं आते उन पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।
- (ख) डी टी ए में बेची गई वस्तुओं जिन्हें खराब पाया गया है उन्हें विकास आयुक्त को सूचित करते हुए मरम्मत/बदलने के लिए वापिस लाया जाएगा।
- (ग) आभूषण निर्माण हेतु रत्नों और कीमती धातुओं के संघटकों सहित वस्तुओं या इसके हिस्सों को आयातित/स्वदेशी रूप से प्राप्त किए जाने और खराब पाया जाने या प्रयोग के लिए अन्यथा ठीक ना पाया जाना या जो वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं या आयात/प्राप्त के पश्चात् खराब हो गई हैं उन्हें वापिस किया जा सकता है और बदला जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। वस्तुओं को बदले जाने की स्थिति में वस्तुओं को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं या भारत में इनके प्राधिकृत एजेंटों या स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं से वापिस लाया जा सकता है। तथापि, यह नष्ट करना रत्न, पत्थरों और कीमती धातुओं पर लागू नहीं होगा।
- (घ) सीमाशुल्क प्राधिकारी को सूचित करके और रिकार्डों के रख रखाव के प्रति वस्तुओं को मरम्मत करने/बदलने, परीक्षण अंशांकन, गुणवत्ता, परीक्षण और अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए डी टी ए को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

- विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रबन्धन 7.19 (क) एस ई जेड विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।  
(ख) विशेष आर्थिक जोन यूनिटों में एस ई जेड यूनिटों की सभी कार्यवाही अन्य विनिर्दिष्ट माध्यम को छोड़कर निर्यात और पुनः आयात सहित सभी गतिविधियाँ स्वतः प्रमाणित प्रक्रिया द्वारा की जाएगी।
- निजी/संयुक्त/ राज्य क्षेत्र में एस ई जेड की स्थापना 7.20 प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14-IIण में उल्लिखित ब्यौरों के अनुसार एस ई जेड सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
- नमूने 7.21 एस ई जेड एकक उनके द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर और सीमाशुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना के बाद :-  
(1) लागू शुल्क के भुगतान पर, प्रदर्शन/बाजार संवर्धन के लिए डी टी ए में नमूनों की आपूर्ति या बिक्री कर सकते हैं।  
(2) सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यह उपयुक्त वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर कि निर्धारित अवधि के भीतर वस्तुओं को वापिस लाया जाएगा शुल्क के भुगतान के बिना नमूनों को हटा सकता है।  
(3) वैक्स मोल्ड्स, चाँदी मोल्ड्स और खर मोल्ड्स में निर्मित मुफ्त नमूनों समेत मुफ्त नमूने बिना सीमा के कुरियर एजेंसियों/डाक सहित निर्यात के सभी अनुमत साधनों द्वारा निर्यात कर सकता है।
- अप्रयुक्त सामग्री/ अप्रचलित माल की बिक्री 7.22 (क) पूँजीगत माल और स्पेयर्स सहित सेवाओं का प्रयोग करने में, वैध कारणों से, यदि एस ई जेड यूनिट असमर्थ है तो उन्हें डी टी ए यूनिट में प्रभावी नीति के अनुसार तथा लागू शुल्कों का भुगतान करके बेचा अथवा निर्यात किया जा सकता है।  
(ख) जो पूँजीगत वस्तुएँ और हिस्से पूर्ण अप्रचलित/फालतू हो गए हैं उन्हें या तो निर्यात किया जा सकता है या लागू शुल्क का भुगतान करके डी टी ए में बेचा जा सकता है। यथा लागू मूल्यहास को लाभ, डी टी ए में बिक्री के मामले में उपलब्ध होंगे।  
(ग) किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, यदि पूँजीगत माल, कच्चा माल, उपभोग्यों, स्पेयर्स, विनिर्मित वस्तुएँ, संसाधित अथवा पैकेज्ड वस्तुएँ तथा स्कैप/वेस्ट/उपशिष्ट को जोन के

भीतर सीमाशुल्क प्राधिकारियों की सूचना में नष्ट किया जाता है अथवा जोन के बाहर सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जा सकता है। तथापि, कीमती और अर्द्ध कीमती धातुओं के लिए यह विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।

(घ) संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा एस ई जेड एकक को आयातित/स्वदेशी रूप से प्राप्त किए गए कम्प्यूटर और पेरिफैरलस का एकक द्वारा आयात करने/प्राप्त करने और प्रयोग के 2 वर्ष के पश्चात शुल्क का भुगतान किए बिना प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14-11 में उल्लिखित व्यौरों के अनुसार मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शैक्षिक संस्थाओं, पंजीकृत धर्मार्थ अस्पतालों इत्यादि को दान कर सकते हैं।

एस ई जेड विकासकर्ता 7.23  
हेतु हकदारी

(क) एस ई जेड में आधार भूत सुविधाओं के विकास, कार्यान्वयन और रख-रखाव हेतु विकासकर्ता निम्न हकदारी हेतु पात्र होगा :-

- (i) आयकर अधिनियम की धारा 80-1क के अनुसार आयकर में छूट।
- (ii) सीमाशुल्क/उत्पाद कर के भुगतान के बिना माल का आयात/खरीद।
- (iii) सेवा कर से छूट।
- (iv) केन्द्रीय बिक्री कर से छूट।

**अध्याय-7क****मुक्त व्यापार और गोदाम क्षेत्र**

- उद्देश्य** 7क.1 इसका उद्देश्य है मुक्त मुद्रा में मुक्त रूप से व्यापारिक लेन-देन करने और माल तथा सेवाओं के आयात व निर्यात को सुगम बनाने हेतु व्यापार संबंधित ढाँचा बनाना । स्कीम में विभिन्न उत्पादों को गोदाम में रखने हेतु विश्व स्तर का ढाँचा बनाने, अत्याधुनिक (स्टेट आफ द आर्ट) उपकरण, परिवहन और प्रबंधन सुविधाएँ, व्यावसायिक कार्यालय-स्थल, जल, विद्युत, संचार और सम्पर्क, के साथ एक स्थान पर आयात और निर्यात की निकासी हेतु औपचारिकता की परिकल्पना की गयी है ताकि समेकित जोनों को “अन्तरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्रों” के तौर पर सुविधाएँ प्रदान की जाएँ । इन जोनों को समुद्री पत्तनों, वायुपत्तनों अथवा शुष्क पत्तनों के नजदीकी क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा ताकि रेल और सड़क से आसानी से पहुंचा जा सके ।
- स्तर** 7क.2 मुक्त व्यापार और गोदाम जोन (एफटीडब्ल्यूजैड) व्यापार और गोदाम पर ध्यान देते हुए विशेष आर्थिक जोनों की विशेष श्रेणी होगी ।
- जोन की स्थापना** 7क.3 (1) एफ टी डब्ल्यू जैडों की स्थापना हेतु प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेड कम्पनियों अथवा अनुभवी ढांचागत डेवेलपर्स के साथ तकनीकी सहयोग प्राप्त संयुक्त उद्यमों द्वारा किए जा सकते हैं । इन प्रस्तावों पर वाणिज्य विभाग के अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा । अनुमोदन प्राप्त होने पर, डेवेलपर को ऐसे एफटीडब्ल्यूजैड के विकास, संचालन और रख रखाव हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा ।
- (2) जोनों के विकास और स्थापना तथा उनकी ढांचागत सुविधाओं हेतु 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी ।
- (3) प्रस्ताव पर ढांचागत सुविधाओं के निर्माण और विकास हेतु अनिवार्यतः 100 करोड़ रूपए का न्यूनतम परिव्यय आना

चाहिए और उसका न्यूनतम निर्मित क्षेत्र पांच लाख वर्ग मीटर होना चाहिए ।

(4) डेवलपर को शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति होगी जैसे कि जोन के विकास और ढांचे हेतु आवश्यक निर्माण सामग्री और उपकरण । यह उपकरण और सामग्री जिसे डी टी ए से प्राप्त किया जाएगा को डी टी ए आपूर्तिकर्ताओं से वास्तविक निर्यात के तौर पर ध्यान में रखा जाएगा ।

(5) एक बार एफटीडब्ल्यूजैड विकसित हो जाने पर, डेवलपर को एफ टी डब्लू यू जैड में गोदाम/वर्कशाप/कार्यालय-क्षेत्र व अन्य सुविधाओं को व्यापारियों/निर्यातकों को बिक्री/लीज/किराए पर देने की भी अनुमति होगी ।

जोन का रखरखाव

7क.4 डेवलपर स्वयं या उपयुक्त विशेष प्रयोजन प्रबन्ध के जरिये एफ टी डब्ल्यू जेड की सामान्य सुविधाओं और सुरक्षा के उचित रख-रखाव के लिए भरोसे योग्य तंत्र सुनिश्चित करेगा ।

कार्यकलाप

7क.5(1) इस योजना में गोदाम के लिए सभी वस्तुओं (निषिद्ध मदों, हथियार और गोला-बारूद, खतरनाक अपशिष्टों और स्कोमेट मदों के अलावा) का शुल्क मुक्त आयात करने की परिकल्पना की गई है । जहां तक आयात पर सीमा शुल्क के बारे में बांड का संबंध है, ये एकक एस ई जेड में एककों के लिए लागू उपबन्धों के अधीन होंगे ।

(2) ऐसी वस्तुओं के पुनः बेचने/पुनः बीजक में दर्ज करने या पुनः निर्यात करने की अनुमति होगी । पुनः निर्यात की अनुमति बिना किसी प्रतिबन्ध के दी जायेगी । तथापि, स्कोमेट मदों के आयात की अनुमति अन्तर मंत्रालयीय समिति की इज़ाज़त के बिना नहीं दी जायेगी ।

(3) इन वस्तुओं को ऐसी बिक्री की तारीख पर यथा लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर डी टी ए में बिक्री की भी अनुमति दी जायेगी । शुल्क का भुगतान केवल तभी देय होगा जब डी टी ए में वस्तुओं को बेचा/सुपुर्द किया जायेगा और बाँण्डेड गोदामों के मामले में कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ।



(4) संसाधन के बिना पैकिंग या पुनः पैकिंग और ग्राहक या विपणन आवश्यकताओं के अनुसार लेबलिंग एफ टी डब्ल्यू जेड के भीतर की जा सकती है ।

(5) एफ टी डब्ल्यू जेड के भीतर वस्तुओं को गोदाम में रखने की अधिकतम अवधि दो वर्ष होगी, इस अवधि के बाद इनका अनिवार्य रूप से पुनः निर्यात करना होगा या इन्हें डीटीए में बेचना होगा । दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, यथा लागू सीमा शुल्क स्वतः देय हो जायेगा जब तक कि यथा अनुमत छूट की अवधि, जो तीन माह से ज्यादा नहीं होगी, के भीतर इन वस्तुओं का पुनः निर्यात नहीं किया जाता ।

ईकाईओं की हकदारी

7क.6 (1) आय कर अधिनियम की धारा 80 आईए के अनुसार आय कर से छूट ।

(2) सेवा कर से छूट ।

(3) मुक्त विदेशी मुद्रा के लेन-देन की अनुमति दी जायेगी ।

(4) एस ई जेड के एककों को यथा लागू आवश्यक परिवर्तनों सहित अन्य लाभ ।

निवल विदेशी मुद्रा  
संबंधी मापदण्ड

7क.7 एफ टी डब्ल्यू जेड में एकक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगे । एसईजेड यूनिटों पर लागू फार्मूले के अनुसार गोदाम और/अथवा व्यापारिक कार्यकलापों की शुरुआत से प्रत्येक पांच वर्षों की अवधि हेतु सकल विदेशी मुद्रा को संचयी तौर पर परिकलित किया जाएगा ।

## अध्याय - आठ

मान्य निर्यात

- मान्य निर्यात 8.1 “मान्य निर्यात” का अर्थ उस लेन-देन से है जिसमें आपूर्ति किया गया माल देश से बाहर नहीं जाता और इन आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है ।
- संभरण की श्रेणियाँ 8.2 इस नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के माल का मुख्य/उप ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति को मान्य निर्यात " के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि माल भारत में विनिर्मित हुआ हो :-
- (क) शुल्क मुक्त/शुल्क वापसी स्कीम के तहत अग्रिम लाइसेंस/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस डी एफ आर सी के प्रति माल का संभरण:
  - (ख) निर्यातोन्मुख यूनितों या साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क्स ( एटीपी) या इलेक्ट्रॉनिक हार्ड वेयर टेक्नालोजी पार्क (ई एच टी पी) वायोटेक्नालोजी पार्क (बी टी पी) में स्थित यूनितों को माल की आपूर्ति ।
  - (ग) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों को पूंजीगत माल की आपूर्ति ।
  - (घ) वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/निधियों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं को उन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार माल का संभरण, जहां विधिक करारों में सीमाशुल्क को शामिल किए बिना टेंडर मूल्यांकन की व्यवस्था हो ।
  - (ङ.) पूंजीगत माल की आपूर्ति जिसमें उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु इस पूंजीगत माल के लिए आवश्यक अनअसैम्बल्ड/डिसअसैम्बल्ड हालत में तथा कच्चा माल अर्न्तवर्ती, संघटक, कलपुर्जे शामिल हैं और एफ ओ आर मूल्य के 10 प्रतिशत तक हिस्से पुर्जों एवं वाणिज्यिक उत्पाद की आपूर्ति ।
  - (च) इस अध्याय के अन्तर्गत घरेलू संभरण के लिए शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति देते हुए किसी परियोजना या प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत घरेलू संभरण के लिए माल की आपूर्ति ।

- (छ) ऊपर (च) में शामिल न किए गए पावर और रिफाइनरी को माल की आपूर्ति ।
- (ज) शिपिंग कारपोरेशन को 100 प्रतिशत ई ओ यू (घरेलू भाड़ा कन्टेनरों के विनिर्माताओं) द्वारा समुद्री फ्रेट कन्टेनरों की आपूर्ति, बशर्ते उक्त कन्टेनरों का भारत से 6 महीनों या सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमत अवधि के भीतर निर्यात किया गया हो ।
- (झ) संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों द्वारा वित्त पोषित संगठनों को की गई आपूर्ति ।
- (ञ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के विपरीत प्रतियोगी बोली के आधार पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टों को माल की आपूर्ति ।

पैराग्राफ (घ), (ड.), (च) और (छ) के तहत मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे यदि आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई है।

मान्य निर्यातों के लिए लाभ

8.3 मान्य निर्यात के रूप में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे बशर्ते कि यह प्रक्रिया पुस्तक खण्ड (1) में दी गयी शर्तों के अनुसार होगा -

- (क) अन्तर्वर्ती आपूर्ति/मान्य निर्यात/डी एफ आर सी अन्तर्वर्तीय आपूर्तियों के लिए डी एफ आर सी हेतु अग्रिम लाइसेंस
- (ख) मान्य निर्यात शुल्क वापसी।
- (ग) जहाँ आपूर्तियाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के मद्दे की गई है वहाँ अन्तिम उत्पाद शुल्क से छूट होगी । अन्य मामलों में अन्तिम उत्पाद शुल्क वापिस किया जाएगा ।

आपूर्तिकर्ता को लाभ

8.4.1 (1) नीति के पैरा 8.2(क) के संबंध में अग्रिम लाइसेंस के मद्दे की गई आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ता, अन्तर्वर्तीय आपूर्ति हेतु अग्रिम लाइसेंस का हकदार होगा ।

(2) यदि आपूर्तिकर्ता ने नीति के पैरा 4.1.11 और 4.1.12 की शर्तों के अनुसार अग्रिम रिलीज आदेश (ए आर ओ) या बैंक टू बैंक साख-पत्र के अनुसार आपूर्ति की है तो वह नीति के पैरा 8.3 ख और ग जो कोई भी लागू हो में दिए गए लाभों का हकदार होगा ।

(3) उन मामलों में जहाँ डी एफ आर सी के मदे अग्रिम रिलीज आदेश या बैक-ट्र-बैक ऋण पत्र के अनुसार आपूर्ति की गई है, आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3ख में उल्लिखित लाभ का हकदार होगा।

8.4.2 नीति के पैरा 8.2 (ख) के अनुसार ईओयू/ईएच टीपी/एस टी पी/बीटीपी को माल की आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) जो भी लागू हो में उल्लिखित लाभों का हकदार होगा।

8.4.3 नीति के पैरा 8.2 ग के अधीन आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3 क) (ख) और (ग) जो भी लागू हो में निर्दिष्ट लाभों के पात्र होंगे।

8.4.4 (1) नीति के अन्तर्गत पैरा 8.2 (घ), (च) और (छ) के तहत आपूर्तियों के मामले में, आपूर्तिकर्ता पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हों, का पात्र होगा।

(2) पैरा 8.2घ में बताये अनुसार केवल ऐसे अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की आपूर्ति, जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित हो, मान्य निर्यात लाभों के पात्र होंगी। ऐसे अभिकरणों/निधियों की सूची परिशिष्ट 33 में दी गई है।

(3) नीति के पैरा 8.2(च) के तहत मान्य निर्यात के लाभ उन मदों पर लागू होंगे, जिनका आयात शून्य सीमाशुल्क पर राजस्व विभाग द्वारा अनुमत होगा बशर्ते कि वह समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 21/2002, दिनांक 1.3.2002 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हों।

(4) पैरा-8.2छ के अनुसार विद्युत परियोजनाओं को की गई पूंजीगत माल और पूंजीगत माल के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक पुर्जों की आपूर्ति मान्य निर्यात लाभों के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि वह स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आई पी पी)/इंजीनियरिंग एण्ड, प्रोक्योरमेंट कान्ट्रैक्ट (ई पी सी) स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद की गई हो। मान्य निर्यात के लाभ पावर संयंत्रों के नवीकरण/आधुनिकीकरण हेतु भी उपलब्ध होंगे। (आपूर्तिकर्ता

नीति के पैरा 8.3क, ख में दिए गए जो भी लागू हों लाभों के लिए पात्र होंगे।) तथापि समय-समय पर यथासंशोधित राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क दिनांक 1.3.2002 की क्रम सं० 400 में निर्दिष्ट कोई बड़ी पावर परियोजना स्थापित करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 8.3 क, ख और ग में यथा उल्लिखित मान्य निर्यात के लाभ पाने की पात्र होगी, यदि ऐसी बड़ी योजना

(क) अर्न्तराज्य थर्मल पावर संयंत्र जिसकी क्षमता 1000 मैगावॉट या इससे अधिक है।

(ख). 500 मैगावाट या उससे अधिक की क्षमता वाले एक अर्न्तराज्य हाइड्रिल पावर प्लान्ट।

(5) नीति के पैराग्राफ 8.2छ के अन्तर्गत उन नई रिफाइनरियों को जो नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगी है और दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक चलेंगी को आपूर्ति अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क दिनांक 1.3.2002 समय-समय पर यथासंशोधित, की क्रम संख्या 228 में सूची संख्या 17 में विनिर्दिष्ट माल के लिए मान्य निर्यात के लाभ की हकदार होगी।

8.4.5 नीति के पैरा 8.2(ड.) के तहत की गई आपूर्तियों के मामले में आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3(क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हो, के लिए पात्र होगा। मान्य निर्यातों के लाभ उर्वरक संयंत्रों के पूँजीगत माल और पुर्जों लिए भी उपलब्ध होंगे जिन्हें नौवीं योजना के दौरान स्थापना/दुरुस्त/ विस्तार/ आधुनीकीकरण किया गया है। मान्य निर्यातों के लाभ उर्वरक संयंत्रों को की जाने वाली उन आपूर्तियों के लिए भी उपलब्ध होंगे जो आठवीं/नौवीं योजना में शुरू हुई है और दसवीं योजना तक चलेंगी।

8.4.6 नीति के पैरा 8.2(झ) के अन्तर्गत आने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वित्तपोषित परियोजना को माल की आपूर्ति नीति के पैरा 8.3(क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हो, के लिए पात्र होंगी।

न्यूक्लियर पावर  
प्रोजेक्टों को आपूर्ति

8.4.7 दिनांक 1.3.2002 के अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क यथासंशोधित सूची संख्या 43 के क्रम संख्या 401 के अनुसार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जिनकी क्षमता 440 एम डब्ल्यू या अधिक हो जिसे आणविक उर्जा विभाग, भारत सरकार में

संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे का अधिकारी न हो ने प्रमाणित किया हो को की गई आपूर्ति मान्य निर्यात लाभ के हकदार होंगी बशर्ते की ऐसी आपूर्तियाँ प्रतिस्पर्धात्मक बोली (न कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली) प्रक्रिया के अधीन हुई हो। नीति के पैरा 8.2(य) के अन्तर्गत न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स को की गई आपूर्ति के आपूर्तिकर्ता नीति के पैराग्राफ 8.3क, ख व ग जो भी लागू हो में विनिर्दिष्ट लाभों के हकदार होंगे।

- |   |       |  |
|---|-------|--|
| टर्मिनल उत्पाद शुल्क वापसी/शुल्क वापसी के भुगतान से छूट | 8.5   | माल की आपूर्ति नीति के पैरा 8.3(ग) के संबंध में टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी बशर्ते कि माल के प्राप्तकर्ता ने ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट/छूट प्राप्त न किया हो। इसी प्रकार आपूर्तियाँ निविष्टि/संघटकों पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद पर नीति के पैरा 8.3(ख) के संबंध में मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि आवेदक द्वारा सेनवेट क्रेडिट सुविधा/छूट प्राप्त न की गई हो। तथापि ऐसी आपूर्तियाँ निविष्टि/संघटकों पर अदा किए गए सीमाशुल्क पर मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी। |
| मुख्य/उप ठेकेदार द्वारा की जाने वाली आपूर्तियाँ         | 8.6.1 | मान्य निर्यात के सभी मामलों में आपूर्तियाँ प्रत्यक्षतः नामित प्रोजेक्ट्स/एजेंसियाँ/यूनिटें/अग्रिम लाइसेंस/ई पी सी जी लाइसेंसधारक को की जाएंगी। तथापि, उप ठेकेदार पैरा 8.4 के अनुसार नामित एजेंसियों/प्रोजेक्ट्स के बजाय मुख्य ठेकेदार को आपूर्तियाँ कर सकता है।  |
| उप ठेकेदारों का लाभ                                     | 8.6.2 | भारतीय या विदेशी मुख्य ठेकेदारों के भारतीय उप ठेकेदार द्वारा की गयी आपूर्तिया भी मान्य निर्यात के लिए पात्र होगी बशर्ते कि करार में मूल रूप में या बाद में उप ठेकेदार का नाम भी दर्शाया गया हो तथा परिशिष्ट-22ग में निर्धारित प्रपत्र में उपठेकेदार के नाम में परियोजना अधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाणपत्र जारी किया हो।   |

## अध्याय - नौ

### परिभाषाएं

- 9.1 इस नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:-
- 9.2 “उपांग” या “संलग्नी” का अर्थ है एक भाग, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है।
- 9.3 “अधिनियम” का अर्थ है-विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, (1992 की संख्या 22)।
- 9.4 “वास्तविक उपयोक्ता” का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक हो सकता है।
- 9.5 “वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी निजी यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा फुटकर सहित किसी अन्य यूनिट में अपने निजी प्रयोग के लिए करता है।
- 9.6 “वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्नलिखित में इस्तेमाल करता हो:-
1. कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो, या
  2. कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल, या
  3. कोई सेवा उद्योग।
- 9.7 “ए ई जैड” का अर्थ है प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 8 में महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र।

- 9.8 “ए एल सी” अर्थात् “अग्रिम लाइसेंसिंग समिति” का अर्थ है शुल्क से मुक्त स्कीम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए सिफारिश करने और महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निवेश उत्पादन मूल्य संवर्धन मानदण्डों की सिफारिश करने वाली विदेश व्यापार महानिदेशालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति ।
- 9.9 “आवेदक” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहाँ संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है ।
- 9.10 “बी ओ ए” का अर्थ है अनुमोदन बोर्ड जैसा कि वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित है ।
- 9.11 “बीटीपी” से अभिप्राय उन बायोटेक्नालोजी पार्कों से है जिन्हें बायोटेक्नोलोजी विभाग की सिफारिश पर विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किया गया है ।
- 9.12 “पूँजीगत माल” का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल हैं। पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, प्रारंभिक लाइनिंग हेतु रिफ्रेक्टरीज, प्रशीतन उपकरण, उर्जा अर्जित करने वाले सेट, मशीन टूल्स, इनीशियल चार्ज के लिए कैटालिस्ट और परीक्षण अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल हैं। पूँजीगत माल के निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है ।
- 9.13 “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ है-वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हों ।



- 9.14 “संघटक” का अर्थ उप संयोजन या संयोजन का वह पुर्जा जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए । संघटक में उसके सहायक या उपषंगी भी शामिल हैं ।
- 9.15 “उपभोज्य” माल का अर्थ है कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिसकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो । मर्दे जिनका वास्तविक रूप में पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मर्दे माना जाएगा ।
- 9.16 “उपभोक्ता माल” का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए टिकाऊ उपभोज्य माल और उसके अनुषंगी भी शामिल होंगे ।
- 9.17 “प्रतिसंतुलन व्यापार” (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत भारत से/को किया जाना वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौते या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता हों । प्रतिसंतुलन व्यापार (काउंटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमित एस्करो एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। ऐसा प्रतिसंतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है ।
- 9.18 “विकासकर्ता” का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसे ही अन्य निजी या सरकारी उद्यम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं को और बुनियादी सुविधाओं के एक भाग या सम्पूर्ण सुविधाओं का विकास, निर्माण करता है, डिजाइन तैयार करता है, स्थापना, संवर्धन करता है, प्रचार, वित्तीय सहायता प्रचालन, रख-रखाव या प्रबन्ध करता है ।
- 9.19 “विकास आयुक्त” का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त ।
- 9.20 “डी एफ आर सी” का अर्थ है जारी शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र

- 9.21 “घरेलू टैरिफ क्षेत्र” का अर्थ है भारत के भीतर का क्षेत्र जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी से बाहर है।
- 9.22 “शुल्क वापसी” का अर्थ है भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती। भारत में विनिर्मित पूंजीगत माल सहित आयातित कल-पुर्जे, यदि आपूर्ति की गई है, माल में शामिल है।
- 9.23 “ई. एच. टी. पी.” का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नॉलाजी पार्क।
- 9.24 “ई.ओ.यू.” का अर्थ है निर्यात उन्मुख एकक जिसके लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति-पत्र जारी किया गया हो।
- 9.25 “उत्पाद शुल्क देय माल” का अर्थ है -कोई माल जिसका भारत में निर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1994 (1994 का 1) के अधीन हो।
- 9.26 “निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, निर्यात करना चाहता है और जो निर्यातक-आयातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
- 9.27 “निर्यात दायित्व” का अर्थ है:- लाइसेंस अथवा अनुज्ञा में शामिल उत्पाद अथवा उत्पादों का लाइसेंसिंग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में निर्यात करने का दायित्व।
- 9.28 “कम्पनी समूह” से अभिप्राय दो या अधिक इन्टरप्राइजेज जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ऐसी स्थिति में हों-
- (i) अन्य इन्टरप्राइजेज में मताधिकार का 26 प्रतिशत या अधिक भागीदारी होगा, या
  - (ii) अन्य इन्टरप्राइजेज में निदेशक मण्डल के सदस्यों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो, या

- 9.29 “प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)” का अर्थ प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) से है और “प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड -2)” का नीति के पैरा 2.4 के पैरा के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-2) से है ।
- 9.30 “आयातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारी हो जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो ।
- 9.31 “संरचनात्मक सुविधाओं” का अर्थ है औद्योगिक, व्यावसायिक और सामाजिक संरचना या कोई अन्य सुविधा जो कि यथाअधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए हो ।
- 9.32 “आई टी सी (एच एस)” का अर्थ निर्यात और आयात मर्चों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण से है ।
- 9.33 “जाबिंग” का अर्थ है-जाब वर्कर को आपूर्तित कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्रवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरूरी हो ।
- 9.34 “लाइसेंसिंग प्राधिकारी” का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो अधिनियम/आदेश के अधीन लाइसेंस देने के लिए सक्षम हो।
- 9.35 “लाइसेंसिंग वर्ष” का अर्थ उस वर्ष से है जो 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो ।
- 9.36 “होटल प्रबंधन” से अभिप्राय तीन स्टार या ऊपर के होटल/होटल श्रृंखला द्वारा होटल चलाना/होटल श्रृंखला तथा होटल प्रबंधन चलाने के मध्य कम से कम तीन वर्ष के दौरान एक प्रबंधन चलाने के करार के अधीन प्रबंधन से है। प्रबंधन करार होटल चलाने के प्रबंधन/कार्यकलापों के क्षेत्र आवश्यक रूप शामिल किया जायेगा ।
- 9.37 “विनिर्माण” का अर्थ है-विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया गया, उत्पन्न किया गया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया

अथवा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजेशन, पुनः पैकिंग, पॉलिशिंग, लेबलिंग, रि-कन्डीशनिंग, मरम्मत, रि-मेकिंग, रि-फर्बिशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन रि-इन्जीनिरिंग। विनिर्माण में, इस नीति के उद्देश्य के लिए कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्पोदपादन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम-उत्पादन, अंगूरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं।

- 9.38 “विनिर्माता निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है।
- 9.39 “एम. ए. आई.” का अर्थ बाज़ार पहुंच पहल स्कीम है जिसे वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 9.40 “व्यापारी निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो।
- 9.41 “एन एफ ई” का अर्थ निवल विदेशी मुद्रा अर्जन से है।
- 9.42 “अधिसूचना” का अर्थ उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए।
- 9.43 “आदेश” का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश।
- 9.44 “पुर्ज” का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के योग्य न हो। “पुर्जा” एक संघटक स्पेयर अथवा उपसाधन हो सकता है।
- 9.45 “व्यक्ति” का अर्थ है कोई व्यक्ति विशेष, फर्म, सोसायटी, कम्पनी, कार्पोरेशन अथवा अन्य कोई वैध व्यक्ति।
- 9.46 “नीति” का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2004-2009।

- 9.47 “निर्धारित” का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम अथवा आदेश या नीति के तहत निर्धारित से है।
- 9.48 “सार्वजनिक सूचना” का अर्थ नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सूचना से है।
- 9.49 “कच्ची सामग्री” का अर्थ है:
1. मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है, परन्तु वह अभी कच्ची, प्राकृतिक, अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित अवस्था में हो, और
  2. किसी विनिर्माण के लिए वह सामग्री या माल जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती हो, चाहे वह सामग्री या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या संसाधित किया जाए या वह अब भी कच्ची या प्राकृतिक अवस्था में हो।
- 9.50 “पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र” (आर.सी.एम.सी) का तात्पर्य नीति या प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिषद/वस्तु बोर्ड/विकास प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है।
- 9.51 “नियमों” का अर्थ है अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम।
- 9.52 “सेवाओं” में, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य करार के अन्तर्गत आने वाली सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है।
- 9.53 “सेवा प्रदान करने वाला” का अर्थ है वह व्यक्ति जो:-
1. भारत से किसी और देश के लिए “सेवा” प्रदान करता है,
  2. भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई सेवा की आपूर्ति करता है, और
  3. भारत से किसी अन्य देश की धरती पर व्यापारिक या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से सेवा की आपूर्ति करता है।
  4. भारत में निर्यातों से सम्बन्धित सेवा की आपूर्ति जिसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो या भारतीय मुद्रा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा माना हो।

- 9.54 “एस ई जेड” का तात्पर्य विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है ।
- 9.55 “जहाज” का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्रतट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है इसमें पुराने पोत भी शामिल हैं ।
- 9.56 “एस आई ओ एन” का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) 2002-2007 में अधिसूचित/ अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित, मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों से है ।
- 9.57 “स्पेयर्स” का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी पुर्जे या उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है । में संघटक या सहायक उपकरण शामिल होते हैं ।
- 9.58 “विनिर्दिष्ट” का तात्पर्य इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है ।
- 9.59 “स्तर धारक” का आशय उस निर्यातक से है जिसे विदेश व्यापार महानिदेशक या विकास आयुक्त ने पाँच सितारा व्यापार सदन के रूप में मान्यता दी हो ।
- 9.60 “एस टी पी” का अर्थ साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क से है ।
- 9.61 “सहायक विनिर्माण” का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी उत्पाद या उसके हिस्सों/ उपांगों/संघटकों का विनिर्माण करता है । सहायक विनिर्माता के साथ-साथ निर्यातक का नाम निर्यात दस्तावेजों पर अवश्य निर्दिष्ट करना चाहिए।
- 9.62 “तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात” का आशय है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा दूसरे निर्यातक की ओर से किए गए निर्यात। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे शिपिंग बिल आदि में विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नामों का उल्लेख होगा । बी आर सी जी आर घोषणा, निर्यात आदेश और बीजक तीसरी पार्टी निर्यातक के नाम से होना चाहिए ।

- 9.63 “विनिमय मूल्य” से अभिप्राय है जो कि राजस्व विभाग के सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम में बताई गई है ।
- 9.64 “यूनिट अनुमोदन समिति” का अर्थ है इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई से सम्बन्धित विषयों पर प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अधिसूचित समिति ।
- 9.65 “वन्य प्राणी” का अर्थ है कोई वन्य प्राणी जो वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के खण्ड- 2(36) में परिभाषित है ।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

( Department of Commerce )  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2005

No. 1 (RE-2005)/2004—2009

**S. O. 530 (E).**—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.2 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby notifies the Foreign Trade Policy, 2004—2009 incorporating the Annual Supplement as updated on 8th April, 2005 and contained in Annexure to this notification. The policy shall come into force w.e.f. 1st April, 2005.

This issues in Public interest.

[F. No. 01/94/180/Foreign Trade Policy/AM06/PC-I]

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

**ANNEXURE**  
**FOREIGN TRADE POLICY**  
(1st September, 2004—31st March, 2009)  
(Updated w. e. f. 1st April, 2005)  
**PREAMBLE**

**CONTEXT**

For India to become a major player in world trade, an all encompassing, comprehensive view needs to be taken for the overall development of the country's foreign trade. While increase in exports is of vital importance, we have also to facilitate those imports which are required to stimulate our economy. Coherence and consistency among trade and other economic policies is important for maximizing the contribution of such policies to development. Thus, while incorporating the existing practice of enunciating an annual Exim Policy, it is necessary to go much beyond and take an integrated approach to the developmental requirements of India's foreign trade. This is the context of the new Foreign Trade Policy.

**OBJECTIVES**

Trade is not an end in itself, but a means to economic growth and national development. The primary purpose is not the mere earning of foreign exchange, but the stimulation of greater economic activity. The Foreign Trade Policy is rooted in this belief and built around two major objectives. These are:

- (i) To double our percentage share of global merchandise trade within the next five years; and
- (ii) To act as an effective instrument of economic growth by giving a thrust to employment generation.

**STRATEGY**

These objectives are proposed to be achieved by adopting, among others, the following strategies:

- (i) Unshackling of controls and creating an atmosphere of trust and transparency to unleash the innate entrepreneurship of our businessmen, industrialists and traders
- (ii) Simplifying procedures and bringing down transaction costs
- (iii) Neutralizing incidence of all levies and duties on inputs used in export products, based on the fundamental principle that duties and levies should not be exported
- (iv) Facilitating development of India as a global hub for manufacturing, trading and services
- (v) Identifying and nurturing special focus areas which would generate additional employ-



ment opportunities, particularly in semi-urban and rural areas, and developing a series of 'Initiatives' for each of these

- (vi) Facilitating technological and infrastructural upgradation of all the sectors of the Indian economy, especially through import of capital goods and equipment, thereby increasing value addition and productivity, while attaining internationally accepted standards of quality
- (vii) Avoiding inverted duty structures and ensuring that our domestic sectors are not disadvantaged in the Free Trade Agreements/Regional Trade Agreements/Preferential Trade Agreements that we enter into in order to enhance our exports
- (viii) Upgrading our infrastructural network, both physical and virtual, related to the entire Foreign Trade chain, to international standards
- (ix) Revitalising the Board of Trade by redefining its role, giving it due recognition and inducting experts on Trade Policy
- (x) Activating our Embassies as key players in our export strategy and linking our Commercial Wings abroad through an electronic platform for real time trade intelligence and enquiry dissemination

#### **PARTNERSHIP:**

The new Policy envisages merchant exporters and manufacturer exporters, business and industry as partners of Government in the achievement of its stated objectives and goals. Prolonged and unnecessary litigation vitiates the premise of partnership. In order to obviate the need for litigation and nurture a constructive and conducive atmosphere, a suitable Grievance Redressal Mechanism will be established which, it is hoped, would substantially reduce litigation and further a relationship of partnership.

The dynamics of a liberalized trading system sometimes results in injury caused to domestic industry on account of dumping. When this happens, effective measures to redress such injury will be taken.

#### **ROADMAP:**

This Policy is essentially a roadmap for the development of India's foreign trade. It contains the basic principles and points the direction in which we propose to go. By virtue of its very dynamics, a trade policy cannot be fully comprehensive in all its details. It would naturally require modification from time to time. We propose to do this through continuous updation, based on the inevitable changing dynamics of international trade. It is in partnership with business and industry that we propose to erect milestones on this roadmap.

(KAMAL NATH)  
MINISTER FOR COMMERCE & INDUSTRY  
GOVERNMENT OF INDIA

NEW DELHI  
31<sup>ST</sup> AUGUST, 2004

## CHAPTER 1A

### LEGAL FRAMEWORK

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| <b><i>Preamble</i></b>                  | 1.1 | The Preamble spells out the broad framework and is an integral part of the Foreign Trade Policy.   |
| <b><i>Duration</i></b>                  | 1.2 | In exercise of the powers conferred under Section 5 of The Foreign Trade (Development and Regulation Act), 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby notifies the Foreign Trade Policy for the period 2004-2009 incorporating the Export and Import Policy for the period 2002-2007, as modified. This Policy shall come into force with effect from 1 <sup>st</sup> September 2004 and shall remain in force upto 31 <sup>st</sup> March, 2009 unless as otherwise specified.  |
| <b><i>Amendments</i></b>                | 1.3 | The Central Government reserves the right in public interest to make any amendments to this Policy in exercise of the powers conferred by Section-5 of the Act. Such amendment shall be made by means of a Notification published in the Gazette of India.   |
| <b><i>Transitional Arrangements</i></b> | 1.4 | Any Notifications made or Public Notices issued or anything done under the previous Export/ Import policies, and in force immediately before the commencement of this Policy shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Policy, continue to be in force and shall be deemed to have been made, issued or done under this Policy.<br><br>Licences, certificates and permissions issued before the commencement of this Policy shall continue to be valid for the purpose and duration for which such licence, certificate or permission was issued, unless otherwise stipulated. |
|   | 1.5 | In case an export or import that is permitted freely under this Policy is subsequently subjected to any restriction or regulation, such export or import will ordinarily be permitted notwithstanding such restriction or regulation, unless otherwise stipulated, provided that the shipment of the export or import is made within the original validity of an irrevocable letter of credit established before the date of imposition of such restriction.   |

## CHAPTER 1B

## SPECIAL FOCUS INITIATIVES

***Special Focus Initiatives***

- 1B.1 With a view to doubling our percentage share of global trade within 5 years and expanding employment opportunities, especially in semi urban and rural areas, certain special focus initiatives have been identified for the agriculture, handlooms, handicraft, gems & jewellery, leather and marine sectors.

Government of India shall make concerted efforts to promote exports in these sectors by specific sectoral strategies that shall be notified from time to time.

***New Sectoral Initiatives to be announced***

Further Sectoral Initiatives in other sectors will also be announced from time to time.

For the present, the thrust sectors indicated below shall be extended the following facilities:

## (i) Agriculture

- (a) A new scheme called the Vishesh Krishi Upaj Yojana (Special Agricultural Produce Scheme) for promoting the export of fruits, vegetables, flowers, minor forest produce, dairy, poultry and their value added products has been introduced (Para 3.8).
- (b) Funds shall be earmarked under ASIDE for development of Agri Export Zones (AEZ)
- (c) Deleted.
- (d) Deleted.
- (e) Capital goods -imported under EPCG shall be permitted to be installed anywhere in the AEZ.
- (f) Import of restricted items, such as panels, shall be allowed under the various export promotion schemes.
- (g) Import of inputs such as pesticides shall be permitted under the Advance Licence for agro exports.
- (h) New towns of export excellence with a threshold limit of Rs 250 crore shall be notified.

## (ii) Handlooms :

- (a) Specific funds would be earmarked under MAI/MDA Scheme for promoting handloom exports.

- (b) Duty free import entitlement of specified trimmings and embellishments shall be 5% of FOB value of exports during the previous financial year.
- (c) Duty free import entitlement of hand knotted carpet samples shall be 1% of FOB value of exports during the previous financial year.
- (d) Duty free import of old pieces of hand knotted carpets on consignment basis for re-export after repair shall be permitted.
- (e) New towns of export excellence with a threshold limit of Rs 250 crore shall be notified.
- (f) Government has decided to develop a trade mark for Handloom on lines similar to 'Woolmark' and 'Silkmark'. This will enable handloom products to develop a niche market with a distinct identity.

(iii) Handicrafts:

- (a) New Handicraft SEZs shall be established which would procure products from the cottage sector and do the finishing for exports.
- (b) Duty free import entitlement of trimmings and embellishments shall be 5% of the FOB value of exports during the previous financial year. The entitlement is broad banded, and shall extend also to merchant exporters tied up with supporting manufacturers.
- (c) The Handicraft Export Promotion Council shall be authorized to import trimmings, embellishments and consumables on behalf of those exporters for whom directly importing may not be viable.
- (d) Specific funds would be earmarked under MAI & MDA Schemes for promoting Handicraft exports.
- (e) CVD is exempted on duty free import of trimmings, embellishments and consumables.
- (f) New towns of export excellence with a reduced threshold limit of Rs 250 crore shall be notified.

(iv) Gems & Jewellery

- (a) Import of gold of 8k and above shall be allowed under the replenishment scheme subject to the import being accompanied by an Assay Certificate specifying the purity, weight and alloy content.

- (b) Duty free import entitlement of consumables for metals other than Gold, Platinum shall be 2% of FOB value of exports during the previous financial year.
  - (c) Duty free import entitlement of commercial samples shall be Rs 300,000.
  - (d) Duty free re-import entitlement for rejected jewellery shall be 2% of the FOB value of exports.
  - (e) Cutting and polishing of gems and jewellery, shall be treated as manufacturing for the purposes of exemption under Section 10A of the Income Tax Act.
- (v) Leather and Footwear
- (a) Duty free import entitlement of specified items shall be 5% of FOB value of exports during the preceding financial year.
  - (b) The duty free entitlement for the import of trimmings, embellishments and footwear components for footwear (leather as well as synthetic), gloves, travel bags and handbags shall be 3% of FOB value of exports of the previous financial year. The entitlement shall also cover packing material, such as printed and non printed shoeboxes, small cartons made of wood, tin or plastic materials for packing footwear.
  - (c) Machinery and equipment for Effluent Treatment Plants shall be exempt from basic customs duty.
  - (d) Re-export of unsuitable imported materials such as raw hides & skins and wet blue leathers is permitted.
  - (e) CVD is exempted on lining and interlining material notified at S.No 168 of Customs Notification No 21/2002 dated 01.03.2002.
  - (f) CVD is exempted on raw, tanned and dressed fur skins falling under Chapter 43 of ITC (HS).
- (vi) (a) Duty free import of specified specialised inputs / chemicals and flavouring oils etc. to be allowed to the extent of 1% of FOB value of preceding financial years export.

***Package for Marine Sector***

- (b) To allow import of monofilament long line system for tuna fishing at a concessional rate of duty.
- (c) A self removal procedure for clearance of seafood waste to be applicable subject to prescribed wastage norms.

***Optimum  
Development  
programme for  
Pragati Maidan***

1B.2

In order to showcase our industrial and trade prowess to its best advantage and leverage existing facilities to enhance the quantity of space and service, Pragati Maidan will be transformed into a world-class complex with visitor friendliness ingress and egress system. The complex utilisation will be improved, increased and diversified. There shall be brand new, state-of-the-art, environmentally-controlled, air-conditioned exhibition areas, and Permanent Exhibition Marts. In addition, a large Convention Centre to accommodate ten thousand delegates will be developed, with multiple and flexible hall spaces, auditoria and meeting rooms with hi-tech equipment. A year-round Food and Beverage destination will be developed, with a large number of outlets covering all cuisines and pricing levels. There will be a multi-level park to accommodate over nine thousand vehicles within the envelope of Pragati Maidan.

## CHAPTER-1C

## BOARD OF TRADE

**Board of Trade**

- 1C.1 The Board of Trade has been revamped and given a clear and dynamic role in advising government on relevant issues connected with Foreign Trade Policy. There would be a process of continuous interaction between the Board of Trade and Government in order to achieve the desired objective of boosting India's exports.

**Terms of Reference**

- 1C.2 The Board of Trade would have the following terms of reference:
- I To advise the Government on Policy measures for preparation and implementation of both short and long term plans for increasing exports in the light of emerging national and international economic scenarios;
  - II To review export performance of various sectors, identify constraints and suggest industry specific measures to optimize export earnings;
  - III To examine the existing institutional framework for imports & exports and suggest practical measures for further streamlining to achieve the desired objectives;
  - IV To review the policy instruments and procedures for imports & exports and suggest steps to rationalize and channelise such schemes for optimum use;
  - V To examine issues which are considered relevant for promotion of India's foreign trade, and to strengthen the international competitiveness of Indian goods and services; and
  - VI To commission studies for furtherance of the above objectives.

**Composition**

- 1C.3 Government shall nominate an eminent person or expert on trade policy to be President of the Board of Trade. Government shall also nominate 25 persons, of whom at least 10 will be experts in trade policy. In addition, Chairmen of recognized Export Promotion Councils and President or Secretary-Generals of National Chambers of Commerce will be ex-officio members.

**Meetings**

- 1C.4 The Board will meet at least once every quarter and make recommendations to Government on issues pertaining to its terms of reference.

**Sub-committee**

- 1C.5 The Board of Trade will have the power to set up sub-committees and to co-opt experts to these, to make recommendations on specific sectors and objectives.

**Secretariat and Budget Head**

- 1C.6 The Board of Trade will have a Secretariat and Budget Head and shall be serviced by the Department of Commerce.

## CHAPTER-2

### GENERAL PROVISIONS REGARDING IMPORTS AND EXPORTS

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| <b><i>Exports and Imports free unless regulated</i></b> | 2.1 | Exports and Imports shall be free, except in cases where they are regulated by the provisions of this Policy or any other law for the time being in force. The item wise export and import policy shall be, as specified in ITC(HS) published and notified by Director General of Foreign Trade, as amended from time to time.   |
| <b><i>Compliance with Laws</i></b>                      | 2.2 | Every exporter or importer shall comply with the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders made thereunder, the provisions of this Policy and the terms and conditions of any licence/certificate/permission granted to him, as well as provisions of any other law for the time being in force. All imported goods shall also be subject to domestic Laws, Rules, Orders, Regulations, technical specifications, environmental and safety norms as applicable to domestically produced goods. No import or export of rough diamonds shall be permitted unless the shipment parcel is accompanied by Kimberley Process (KP) Certificate required under the procedure specified by the Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC). |
| <b><i>Interpretation of Policy</i></b>                  | 2.3 | <p>If any question or doubt arises in respect of the interpretation of any provision contained in this Policy, or regarding the classification of any item in the ITC(HS) or Handbook (Vol.1) or Handbook (Vol.2), or Schedule Of DEPB Rate the said question or doubt shall be referred to the Director General of Foreign Trade whose decision thereon shall be final and binding.</p> <p>If any question or doubt arises whether a licence/certificate/permission has been issued in accordance with this Policy or if any question or doubt arises touching upon the scope and content of such documents, the same shall be referred to the Director General of Foreign Trade whose decision thereon shall be final and binding.</p>   |
| <b><i>Procedure</i></b>                                 | 2.4 | The Director General of Foreign Trade may, in any case or class of cases, specify the procedure to be followed by an exporter or importer or by any licensing or any other competent authority for the purpose of implementing the provisions of the Act, the Rules and the Orders made thereunder and this Policy. Such procedures shall be included in the Handbook (Vol.1), Handbook (Vol.2), Schedule of DEPB Rate and in ITC(HS) and published by   |



means of a Public Notice. Such procedures may, in like manner, be amended from time to time.

The Handbook (Vol.1) is a supplement to the Foreign Trade Policy and contains relevant procedures and other details. The procedure of availing benefits under various schemes of the Policy are given in the Handbook (Vol.1).

***Exemption from  
Policy/ Procedure***

2.5

Any request for relaxation of the provisions of this Policy or of any procedure, on the ground that there is genuine hardship to the applicant or that a strict application of the Policy or the procedure is likely to have an adverse impact on trade, may be made to the Director General of Foreign Trade for such relief as may be necessary. The Director General of Foreign Trade may pass such orders or grant such relaxation or relief, as he may deem fit and proper.

The Director General of Foreign Trade may, in public interest, exempt any person or class or category of persons from any provision of this Policy or any procedure and may, while granting such exemption, impose such conditions as he may deem fit. Such request may be considered only after consulting Advance Licensing Committee (ALC) if the request is in respect of a provision of Chapter-4 (excluding any provision relating to Gem & Jewellery sector) and EPCG Committee if the request is in respect of a provision of Chapter-5 of the Policy/ Procedure. However, any such request in respect of a provision other than Chapter-4, Chapter-5 and Gem & Jewellery sector as given above may be considered only after consulting Policy Relaxation Committee.

***Principles of  
Restriction***

2.6

DGFT may, through a notification, adopt and enforce any measure necessary for:-

- i Protection of public morals.
- ii Protection of human, animal or plant life or health.
- iii Protection of patents, trademarks and copyrights and the prevention of deceptive practices.
- iv Prevention of use of prison labour.
- v Protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value.
- vi Conservation of exhaustible natural resources.
- vii Protection of trade of fissionable material or material from which they are derived; and

viii Prevention of traffic in arms, ammunition and implements of war.

<b><i>Restricted Goods</i></b>	2.7	Any goods, the export or import of which is restricted under ITC(HS) may be exported or imported only in accordance with a licence/ certificate/ permission or a public notice issued in this behalf.
<b><i>Terms and Conditions of a Licence/ Certificate/ Permission</i></b>	2.8	<p>Every licence/certificate/permission shall be valid for the period of validity specified in the licence/ certificate/ permission and shall contain such terms and conditions as may be specified by the licensing authority which may include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The quantity, description and value of the goods;</li> <li>(b) Actual User condition;</li> <li>(c) Export obligation;</li> <li>(d) The value addition to be achieved; and</li> <li>(e) The minimum export price.</li> </ul>
<b><i>Licence/ Certificate/ Permission not a Right</i></b>	2.9	No person may claim a licence/certificate/ permission as a right and the Director General of Foreign Trade or the licensing authority shall have the power to refuse to grant or renew a licence/certificate/permission in accordance with the provisions of the Act and the Rules made there under.
<b><i>Penalty</i></b>	2.10	If a licence/certificate/permission holder violates any condition of the licence/certificate/ permission or fails to fulfill the export obligation, he shall be liable for action in accordance with the Act, the Rules and Orders made there under, the Policy and any other law for the time being in force.
<b><i>State Trading</i></b>	2.11	<p>Any goods, the import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to State Trading Enterprise(s), may be imported or exported by the State Trading Enterprise(s) as specified in the ITC(HS) Book subject to the conditions specified therein. The Director General of Foreign Trade may, however, grant a licence/certificate/permission to any other person to import or export any of these goods.</p> <p>In respect of goods the import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to State Trading Enterprise(s), the State Trading Enterprise(s) shall make any such purchases or sales involving imports or exports solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of</p>

purchase or sale. These enterprises shall act in a non discriminatory manner and shall afford the enterprises of other countries adequate opportunity, in accordance with customary business practices, to compete for participation in such purchases or sales.

- |   |      |  |
|---|------|--|
| <b>Importer-Exporter Code Number</b>                    | 2.12 | No export or import shall be made by any person without an Importer-Exporter Code (IEC) number unless specifically exempted. An Importer-Exporter Code (IEC) number shall be granted on application by the competent authority in accordance with the procedure specified in the Handbook (Vol.1).   |
| <b>Trade with Neighbouring Countries</b>                | 2.13 | The Director General of Foreign Trade may issue, from time to time, such instructions or frame such schemes as may be required to promote trade and strengthen economic ties with neighbouring countries.  |
| <b>Transit Facility</b>                                 | 2.14 | Transit of goods through India from or to countries adjacent to India shall be regulated in accordance with the bilateral treaties between India and those countries and will be subject to such restrictions as may be specified by DGFT in accordance with International Conventions.  |
| <b>Trade with Russia under Debt-Repayment Agreement</b> | 2.15 | In the case of trade with Russia under the Debt Repayment Agreement, the Director General of Foreign Trade may issue, from time to time, such instructions or frame such schemes as may be required, and anything contained in this Policy, in so far as it is inconsistent with such instructions or schemes, shall not apply.  |
| <b>Actual User Condition</b>                            | 2.16 | <p>Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods, which are importable without any restriction, may be imported by any person.</p> <p>However, if such imports require a licence/certificate/permission, the actual user alone may import such goods unless the actual user condition is specifically dispensed with by the licensing authority.</p> |
| <b>Second Hand Goods</b>                                | 2.17 | <p>All second hand goods, excepting second hand capital goods, shall be restricted for imports and may be imported only in accordance with the provisions of this Policy, ITC(HS), Handbook (Vol.1), Public Notice or a licence/certificate/permission issued in this behalf.</p> <p>Import of second hand capital goods, including refurbished/reconditioned spares, shall be allowed freely.</p>                                   |

<b>Import of samples</b>	2.18	Import of samples shall be governed by the provisions given in Handbook (Vol.1).
<b>Import of Gifts</b>	2.19	Import of gifts shall be permitted where such goods are otherwise freely importable under this Policy. In other cases, a Customs Clearance Permit (CCP) shall be required from the DGFT.
<b>Passenger Baggage</b>	2.20	<p>Bonafide household goods and personal effects may be imported as part of passenger baggage as per the limits, terms and conditions thereof in the Baggage Rules notified by the Ministry of Finance.</p> <p>Samples of such items that are otherwise freely importable under this Policy may also be imported as part of passenger baggage without a licence/certificate/permission.</p> <p>Exporters coming from abroad are also allowed to import drawings, patterns, labels, price tags, buttons, belts, trimming and embellishments required for export, as part of their passenger baggage without a licence / certificate/permission.</p>
<b>Import on Export basis</b>	2.21	New or second hand capital goods, equipments, components, parts and accessories, containers meant for packing of goods for exports, jigs, fixtures, dies and moulds may be imported for export without a licence/certificate/permission on execution of Legal Undertaking/Bank Guarantee with the Customs Authorities provided that the item is freely exportable without any conditionality/requirement of licence/ permission as may be required under ITC(HS) Schedule II.
<b>Re-import of goods repaired abroad</b>	2.22	Capital goods, equipments, components, parts and accessories, whether imported or indigenous, except those restricted under ITC (HS) may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or upgradation or standardization of technology and re-imported without a licence/certificate/permission.
<b>Import of goods used in projects abroad</b>	2.23	After completion of the projects abroad, project contractors may import, without a licence/ certificate/ permission, used goods including capital goods provided they have been used for at least one year.
<b>Sale on High Seas</b>	2.24	Sale of goods on high seas for import into India may be made subject to this Policy or any other law for the time being in force.
<b>Import under Lease Financing</b>	2.25	Permission of licensing authority is not required for import of new capital goods under lease financing.

<b><i>Clearance of Goods from Customs</i></b>	2.26	The goods already imported/shipped/arrived, in advance, but not cleared from Customs may also be cleared against the licence/ certificate/ permission issued subsequently.
<b><i>Execution of BG/ LUT</i></b>	2.27	Wherever any duty free import is allowed or where otherwise specifically stated, the importer shall execute a Legal Undertaking (LUT)/Bank Guarantee (BG)/ Bond with the Customs Authority before clearance of goods through the Customs, in the manner as may be prescribed. In case of indigenous sourcing, the licence/ certificate/ permission holder shall furnish LUT / BG / Bond to the licensing authority before sourcing the material from the indigenous supplier/nominated agency.
<b><i>Exemption from Bank Guarantee</i></b>	2.27.1	All the exporters who have an export turnover of at least Rupees 5 crore in the current or preceding licencing year and have a good track record of three years of exports will be exempted from furnishing a BG for any of the schemes under this Policy and may furnish a LUT in lieu of BG.
<b><i>Private/ Public Bonded Warehouses for Imports</i></b>	2.28	<p>Private/Public bonded warehouses may be set up in the Domestic Tariff Area as per the terms and conditions of notification issued by Department of Revenue.</p> <p>Any person may import goods except prohibited items, arms and ammunition, hazardous waste and chemicals and warehouse them in such private/public bonded warehouses.</p> <p>Such goods may be cleared for home consumption in accordance with the provisions of this Policy and against Licence/certificate/ permission, wherever required. Customs duty as applicable shall be paid at the time of clearance of such goods.</p> <p>If such goods are not cleared for home consumption within a period of one year or such extended period as the custom authorities may permit, the importer of such goods shall re-export the goods.</p>
<b><i>Free Exports</i></b>	2.29	<p>All goods may be exported without any restriction except to the extent such exports are regulated by ITC(HS) or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force.</p> <p>The Director General of Foreign Trade may, however, specify through a public notice such terms and conditions according to which any goods, not included in the ITC(HS), may be exported without a licence/ certificate/ permission.</p>

- |   |      |  |
|---|------|--|
| <b><i>Export of Samples</i></b>           | 2.30 | Export of samples and Free of charge goods shall be governed by the provisions given in Handbook (Vol.1).  |
| <b><i>Export of Passenger Baggage</i></b> | 2.31 | Bonafide personal baggage may be exported either along with the passenger or, if unaccompanied, within one year before or after the passenger's departure from India. However, items mentioned as Restricted in ITC(HS) shall require a licence/certificate/permission.  |
| <b><i>Export of Gifts</i></b>             | 2.32 | <p>Goods, including edible items, of value not exceeding Rs.5,00,000/- in a licensing year, may be exported as a gift.</p> <p>However, items mentioned as restricted for exports in ITC(HS) shall not be exported as a gift, without a licence/certificate/permission.</p>   |
| <b><i>Export of Spares</i></b>            | 2.33 | Warranty spares, whether indigenous or imported, of plant, equipment, machinery, automobiles or any other goods, except those restricted under ITC (HS), may be exported along with the main equipment or subsequently but within the contracted warranty period of such goods subject to approval of RBI.   |
| <b><i>Third Party Exports</i></b>         | 2.34 | Third party exports, as defined in Chapter 9 shall be allowed under the Policy.  |
| <b><i>Export of Imported Goods</i></b>    | 2.35 | <p>Goods imported, in accordance with this Policy, may be exported in the same or substantially the same form without a licence/certificate/permission provided that the item to be imported or exported is not mentioned as restricted for import or export in the ITC(HS).</p> <p>Exports of such goods imported against payment in freely convertible currency would be permitted against payment in freely convertible currency.</p> |
|   | 2.36 | Goods, including those mentioned as restricted item for import (except prohibited items) may be imported under Customs Bond for export in freely convertible currency without a licence/ certificate/ permission provided that the item is freely exportable without any conditionality/ requirement of licence/permission as may be required under ITC (HS) Schedule II.  |
| <b><i>Export of Replacement Goods</i></b> | 2.37 | Goods or parts thereof on being exported and found defective/damaged or otherwise unfit for use may be replaced free of charge by the exporter and such goods shall be allowed clearance by the customs authorities provided that the replacement goods are not mentioned as restricted items for exports in ITC(HS).  |

**Export of Repaired Goods**

2.38

Goods or parts, except restricted under ITC (HS), thereof on being exported and found defective, damaged or otherwise unfit for use may be imported for repair and subsequent re-export.

Such goods shall be allowed clearance without a licence/certificate/permission and in accordance with customs notification issued in this behalf.

**Private Bonded Warehouses for Exports**

2.39

Private bonded warehouses exclusively for exports may be set up in DTA as per the terms and conditions of the notifications issued by Department of Revenue.

Such warehouses shall be entitled to procure the goods from domestic manufacturers without payment of duty. The supplies made by a domestic supplier to the notified warehouses shall be treated as physical exports provided the payments for the same are made in free foreign exchange.

**Denomination of Export Contracts**

2.40

All export contracts and invoices shall be denominated either in freely convertible currency or Indian rupees but the export proceeds shall be realised in freely convertible currency.

However export proceeds against specific exports may also be realized in rupees provided it is through a freely convertible Vostro account of a non resident bank situated in any country other than a member country of ACU or Nepal or Bhutan. Additionally, the rupee payment through the Vostro account must be against payment in free foreign currency by the buyer in his non resident bank account. The free foreign exchange remitted by the buyer to his non resident bank (after deducting the bank service charges) on account of this transaction would be taken as the export realization under the export promotion schemes of this Policy.

Contracts for which payments are received through the Asian Clearing Union (ACU) shall be denominated in ACU Dollar. The Central Government may relax the provisions of this paragraph in appropriate cases. Export contracts and Invoices can be denominated in Indian rupees against EXIM Bank/ Government of India line of credit.

**Realisation of Export Proceeds**

2.41

If an exporter fails to realise the export proceeds within the time specified by the Reserve Bank of India, he shall, without prejudice to any liability or penalty under any law for the time being in force, be liable to action in accordance

with the provisions of the Act, the Rules and Orders made there under and the provisions of this Policy.

<b>Free movement of export goods</b>	2.42	Consignments of items meant for exports shall not be withheld /delayed for any reason by any agency of the Central/State Government. In case of any doubt, the authorities concerned may ask for an undertaking from the exporter.
<b>No seizure of Stock</b>	2.42.1	No seizure of stock shall be made by any agency so as to disrupt the manufacturing activity and delivery schedule of export goods. In exceptional cases, the concerned agency may seize the stock on the basis of prima facie evidence. However, such seizure should be lifted within 7 days.
<b>Export Promotion Councils</b>	2.43	The basic objective of Export Promotion Councils is to promote and develop the exports of the country. Each Council is responsible for the promotion of a particular group of products, projects and services. The list of the councils, and their main functions are given in Handbook (Vol.1).
<b>Registration -cum- Membership Certificate</b>	2.44	Any person, applying for (i) a licence/ certificate/ permission to import/ export, [except items listed as restricted items in ITC(HS)] or (ii) any other benefit or concession under this policy shall be required to furnish Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) granted by the competent authority in accordance with the procedure specified in the Handbook (Vol.1) unless specifically exempted under the Policy.
	2.45	Deleted
<b>Trade Facilitation through EDI Initiatives</b>	2.45.1	It is endeavor of the Government to work towards greater simplification, standardization and harmonization of trade documents using international best practices. As a step in this direction DGFT shall move towards an automated environment for electronic filing, retrieval and authentication of documents based on agreed protocols and message exchange with other community partners including Customs and Banks.
<b>DGCI&amp;S Commercial Trade Data</b>	2.45.2	To enable the users to make commercial decisions in a more professional manner, DGCI&S trade data shall be made available with a minimum time lag in a query based structured format on a commercial criteria.



***Fiscal Incentives to promote EDI Initiatives adoption*** 2.45.3 With a view to promote the use of Information Technology, DGFT will provide fiscal incentives to the user community. The details are enumerated in the Handbook (Vol. I).

***Regularization of EO default and settlement of customs duty and interest through Settlement Commission*** 2.46 With a view to providing assistance to firms who have defaulted under the Foreign Trade Policy for reasons beyond their control as also facilitating the merger, acquisition and rehabilitation of sick units, it has been decided to empower the Settlement Commission in the Central Board of Excise and Customs to decide such cases also with effect from 01.04.2005.

2.47 Deleted.

***Remission of Service Tax in DTA*** 2.48.1 For all goods and services which are exported from units in Domestic Tariff Area (DTA) and units in EOU/EHTP/STP/BTP remission of service tax levied shall be allowed.

***Exemption from Service Tax in SEZ*** 2.48.2 Units in SEZ shall be exempted from service tax.

#### GRIEVANCE REDRESSAL

***DGFT as a facilitator of exports/ imports*** 2.49 DGFT has a commitment to function as a facilitator of exports and imports. Our focus is on good governance, which depends on clean, transparent and accountable delivery systems.

***Citizen's Charter*** 2.49.1 DGFT has in place a Citizen's Charter which lays down its commitment to serve importers and exporters. It also gives time schedules for providing services to clients, and details of grievance committees at different levels.

***Grievance Redressal Mechanism*** 2.49.2 In order to facilitate speedy redressal of grievances of trade and industry, a new grievance redressal mechanism has been put in place by a Government Resolution.

The Government is committed to resolving all outstanding problems and disputes pertaining to the past policy periods through the Grievance Redressal Committee set up on 27.10.2004 for condoning delays, regularizing breaches by exporters in bonafide cases, resolving disputes over entitlements, granting extensions for utilization of licences etc.

2.49.3 Deleted

## CHAPTER-3

### PROMOTIONAL MEASURES

***Assistance to States  
for Infrastructure  
Development of  
Exports (ASIDE)***

3.1

The State Governments shall be encouraged to participate in promoting exports from their respective States. For this purpose, Department of Commerce has formulated a scheme called ASIDE.

Suitable provision has been made in the Annual Plan of the Department of Commerce for allocation of funds to the States on the twin criteria of gross exports and the rate of growth of exports.

The States shall utilise this amount for developing infrastructure such as roads connecting production centres with the ports, setting up of Inland Container Depots and Container Freight Stations, creation of new State level export promotion industrial parks/zones, augmenting common facilities in the existing zones, equity participation in infrastructure projects, development of minor ports and jetties, assistance in setting up of common effluent treatment facilities, stabilizing power supply and any other activity as may be notified by Department of Commerce from time to time.

***Market Access  
Initiative (MAI)***

3.2

The Market Access Initiative (MAI) scheme is intended to provide financial assistance for medium term export promotion efforts with a sharp focus on a country and product.

The financial assistance is available for Export Promotion Councils, Industry and Trade Associations, Agencies of State Governments, Indian Commercial Missions abroad and other eligible entities as may be notified from time to time.

A whole range of activities can be funded under the MAI scheme. These include market studies, setting up of showroom/ warehouse, sales promotion campaigns, international departmental stores, publicity campaigns, participation in international trade fairs, brand promotion, registration charges for pharmaceuticals and testing charges for engineering products etc. Each of these export promotion activities can receive financial assistance from the Government ranging from 25% to 100% of the total cost depending upon the activity and the implementing agency, as indicated in the detailed guidelines. The full text of the guidelines can be seen at <http://commerce.nic.in>.

**Marketing  
Development  
Assistance (MDA)**

3.2.1

The Marketing Development Assistance (MDA) Scheme is intended to provide financial assistance for a range of export promotion activities implemented by export promotion councils, industry and trade associations on a regular basis every year.

As per the revised MDA guidelines with effect from 1<sup>st</sup> April, 2004 assistance under MDA is available for exporters with annual export turnover upto Rs 5 crores.

These include participation in Trade Fairs and Buyer Seller meets abroad or in India, export promotion seminars, etc.

Further, assistance for participation in Trade Fairs abroad and travel grant is available to such exporters if they travel to countries in one of the four Focus Areas, such as, Latin America, Africa, CIS Region, ASEAN countries, Australia and New Zealand.

For participation in trade fairs, etc. in other areas financial assistance without travel grant is available.

**Meeting Legal  
expenses for Trade  
related matters**

3.2.1.1

Financial assistance would be provided to deserving exporters on the recommendation of Export Promotion Councils for meeting the cost of legal expenses relating to trade related matters.

**Towns of Export  
Excellence**

3.3

A number of towns in specific geographical locations have emerged as dynamic industrial clusters contributing handsomely to India's exports. It is necessary to grant recognition to these industrial clusters with a view to maximizing their potential and enabling them to move higher in the value chain and tap new markets.

Selected towns producing goods of Rs. 1000 crore or more will be notified as Towns of Exports Excellence on the basis of potential for growth in exports. However for the Towns of Export Excellence in the Handloom, Handicraft, Agriculture and Fisheries sector, the threshold limit would be Rs 250 crores.

Common service providers in these areas shall be entitled for the facility of the EPCG scheme.

The recognized associations of units will be able to access the funds under the Market Access Initiative scheme for creating focused technological services.

Further such areas will receive priority for assistance for rectifying identified critical infrastructure gaps from the ASIDE scheme.

The notified towns of export excellence are listed in Appendix 7.

***Brand Promotion  
and Quality***

- 3.4.1 The Central Government aims to encourage manufacturers and exporters to attain internationally accepted standards of quality for their products. The Central Government will extend support and assistance to Trade and Industry to launch a nationwide programme on quality awareness and to promote the concept of total quality management.

***Test Houses***

- 3.4.2 The Central Government will assist in the modernisation and upgradation of test houses and laboratories in order to bring them at par with international standards.

***Quality Complaints/  
Disputes***

- 3.4.3 The Regional Sub-Committee on Quality Complaints (RSCQC) set up at the Regional Offices of the Directorate General of Foreign Trade shall investigate quality complaints received from foreign buyers. The guidelines for settlement of quality complaints, in particular, and such other complaints, in general, are given in Appendix-16 of Handbook (Vol.1).

***Trade disputes  
affecting trade  
relations***

- 3.4.4 If it comes to the notice of the Director General of Foreign Trade or he has reason to believe that an export or import has been made in a manner that
- (i) is gravely prejudicial to the trade relations of India with any foreign country; or
  - (ii) Is gravely prejudicial to the interest of other persons engaged in exports or imports;
  - (iii) has brought disrepute to the country;

The Director General Foreign Trade may take action against the exporter or importer concerned in accordance with the provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder and this Policy.

### 3.5 STAR EXPORT HOUSES

**Star Export House** 3.5.1 Merchant as well as Manufacturer Exporters, Service Providers, Export Oriented Units (EOUs) and Units located in Special Economic Zones (SEZs), Agri Export Zone (AEZ's), Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio Technology Parks (BTPs) shall be eligible for applying for status as Star Export Houses.

**Status Category** 3.5.2 The applicant shall be categorized depending on his total FOB/FOR export performance during the current plus the previous three years:

Category	Performance (Rupees in Crores)
One Star Export House	15
Two Star Export House	100
Three Star Export House	500
Four Star Export House	1500
Five Star Export House	5000

Note

1. Manufacturer exporters in the Small Scale Industry/Tiny Sector/Cottage Sector, Units registered with KVICs/KVIBs, Units located in North Eastern States, Sikkim and J&K, Units exporting handloom/ handicrafts/hand knotted or silk carpets, exporters exporting to countries in Latin America/CIS/sub-Saharan Africa as listed in Appendix-9, units having ISO 9000 (series)/ ISO 14000 (series) /WHOGMP/HACCP/SEI CMM level-II and above status granted by agencies listed in Appendix-6, exports of services and exports of agro products shall be entitled for double weightage of exports made for grant of Star Export House status.
2. Exports made on re-export basis shall not be counted for the purpose of recognition.
3. Exports made by a subsidiary of a limited company shall be counted towards export performance of the limited company for the purpose of recognition only if the limited company has a majority share holding in the subsidiary company.

4. In case the recognition is claimed based upon the current year's export performance, same shall be considered only in case the exporter has export performance during any one of the preceding three years as well.

### ***Privileges***

3.5.2.1 A Star Export House shall be eligible for the following facilities:

- i) Licence/certificate/permissions and Customs clearances for both imports and exports on self-declaration basis;
- ii) Fixation of Input-Output norms on priority within 60 days;
- iii) Exemption from compulsory negotiation of documents through banks. The remittance, however, would continue to be received through banking channels;
- iv) 100% retention of foreign exchange in EEFC account;
- v) Enhancement in normal repatriation period from 180 days to 360 days;
- vi) Entitlement for consideration under the Target Plus Scheme; and
- vii) Exemption from furnishing of Bank Guarantee in Schemes under this Policy.

### ***Validity Period***

3.5.3 All status certificates issued or renewed on or after 01.09.2004 shall be valid from 1st April of the licensing year during which the application for the grant of such recognition is made upto 31st March, 2009, unless otherwise specified.

On the expiry of such certificate, application for renewal of status certificate shall be required to be made within a period as prescribed in the Handbook (Vol.1). During the said period, the star export house shall be eligible to claim the usual facilities and benefits.

## **3.6 SERVICES EXPORTS**

### ***Services exports***

3.6.1 Services include all the 161 tradable services covered under the General Agreement on Trade in Services where payment for such services is received in free foreign exchange. A list of services is given in Appendix-10 of

Handbook (Vol.1). All provisions of this Policy shall apply mutatis mutandis to export of services as they apply to goods, unless otherwise specified.

**Export Promotion  
Council for Services**

3.6.2

Service exporters are required to register themselves with the Federation of Indian Exporters Organisation. However, software exporters shall register themselves with Electronic and Software Export Promotion Council.

In order to give proper direction, guidance and encouragement to the Services Sector, an exclusive Export Promotion Council for Services shall be set up.

The Services Export Promotion Council shall:

- (i) Map opportunities for key services in key markets and develop strategic market access programmes for each component of the matrix.
- (ii) Co-ordinate with sectoral players in undertaking intensive brand building and marketing programmes in target markets.
- (iii) Make necessary interventions with regard to policies, procedures and bilateral/ multilateral issues, in co-ordination with recognised nodal bodies of the services industry.

**Common Facility  
Centres**

3.6.3

Government shall promote the establishment of Common Facility Centres for use by home-based service providers, particularly in areas like Engineering & Architectural design, Multi-media operations, Software developers etc., in State and District-level towns, to draw in a vast multitude of home-based professionals into the services export arena.

3.6.4

**SERVED FROM INDIA SCHEME**

**Objective**

3.6.4.1

The objective is to accelerate the growth in export of services so as to create a powerful and unique 'Served From India' brand, instantly recognized and respected world over.

**Eligibility**

3.6.4.2

All Service providers who have a total foreign exchange earning of at least Rs.10 lakhs in the preceding or current financial year shall be eligible to qualify for a duty credit entitlement.

For individuals who are service providers, the total foreign exchange earned criteria would be Rs.5 lakhs in the preceding financial year.

Payments received from Export Earners Foreign Currency (EEFC) Account shall not be counted for benefits under the scheme.

***Entitlement***

3.6.4.3 All Service providers (other than hotels and restaurants) shall be entitled to duty credit equivalent to 10% of the foreign exchange earned by them in the preceding financial year.

***Hotels &  
Restaurants***

3.6.4.4 Hotels of one-star and above (including managed hotels and heritage hotels) approved by the Department of Tourism and other Service providers in the tourism sector registered with the Department of Tourism shall be entitled to duty credit equivalent to 5% of the foreign exchange earned by them in the preceding financial year.

Stand-alone restaurants will be entitled to duty credit equivalent to 20% of the foreign exchange earned by them in the preceding financial year.

Note: In the case of one and two star hotels and stand-alone restaurants, the foreign exchange earned through International Credit Cards and sources as may be notified only shall be taken into account for the purposes of computation of duty credit entitlement under the scheme.

***Imports allowed***

3.6.4.5 Duty credit entitlement may be used for import of any capital goods including spares, office equipment and professional equipment, office furniture and consumables, related to the main line of business of the applicant.

In the case of hotels and stand-alone restaurants, the duty credit entitlement may also be used for the import of food items and alcoholic beverages.

***Non  
Transferability***

3.6.4.6 The entitlement and the goods imported shall be non-transferable. However, transfer of goods imported under the scheme shall be allowed within the Group Company as defined in chapter 9 and managed hotels with actual user condition.

***Healthcare &  
Education***

3.6.4.7 In order to enable Healthcare and Educational Institutions to have world-class state-of-the-art infrastructure, service providers in these sectors shall, as for other service sectors, be entitled to duty credit equivalent to 10% of the foreign exchange earned by them in the previous financial year.



- (i) The foreign exchange turnover for Healthcare Institutions would include amounts earned through medical treatment, surgery, testing, consultancy and health care provided by the institution.
- (ii) The foreign exchange turnover for Educational Institutions would include amounts earned through the courses and consultancy provided by the institution.
- (iii) In either case, it will not include foreign exchange remittances through any other source including equity participation, donations etc.
- (iv) The capital goods and the consumer goods imported under the duty free entitlement shall have a nexus with the activities of the healthcare or educational institutions concerned.

**Special provisions**

3.6.4.8 Government reserves the right in public interest to specify from time to time the category or type of service exports which shall not be eligible for calculation of either eligibility or of entitlement.

Similarly, Government may from time to time also notify the goods which shall not be allowed for import under the duty free entitlement certificate issued under the scheme.

3.6.4.8.1 The scheme shall not be available for 100% EOUs and units operating under SEZ, STPI and EHTP Schemes. The clubbing of turnover of services rendered by these units with the turn over of the DTA units shall also not be allowed.

### 3.7 TARGET PLUS SCHEME

**Objective**

3.7.1 The objective of the scheme is to accelerate growth in exports by rewarding Star Export Houses who have achieved a quantum growth in exports. High performing Star Export Houses shall be entitled for a duty credit based on incremental exports, substantially higher than the general annual export target fixed (Since the target fixed for 2005-06 is 17%, the lower limit of performance for qualifying for rewards is pegged at 20% for the current year).

**Eligibility Criteria**

3.7.2 All Star Export Houses (including Status Holders as defined in Para 3.7.2.1 of Exim Policy 2002-07) which have achieved a minimum export turnover in free foreign exchange of Rs.10 crores in the previous licensing year

are eligible for consideration under the Target Plus Scheme.

### **Entitlement**

3.7.3

The entitlement under this scheme would be contingent on the percentage incremental growth in FOB value of exports in the current licensing year over the previous licensing year, as under:

Percentage incremental growth	Duty Credit Entitlement (as a % of the incremental growth)
20% and above but below 25%	5%
25% or above but below 100%	10%
100% and above	15% (of 100%)

Note:

- (1) Incremental growth beyond 100% will not qualify for computation of duty credit entitlement.
- (2) For the purpose of this scheme, the export performance shall not be transferred to or transferred from any other exporter. In the case of third party exports, the name of the supporting manufacturer/ manufacturer exporter shall be declared.
- (3) Exporters shall have the option to apply for benefit either under the Target Plus Scheme or under the Vishesh Krishi Upaj Yojana, but not both in respect of the same exported product/s. Provided that in calculating the entitlement under Para 3.7.3 the total eligible exports shall be taken into account for computing the percentage incremental growth but the duty credit entitlement shall be arrived at on the eligible exports reduced by the amount on which the benefit is claimed under para 3.8.2.
- (4) All exports including exports under free shipping bill verified and authenticated by Customs and Gems & Jewellery shipping bills but excluding exports specified under para 3.7.5, shall be eligible for benefits under the Target Plus Scheme.
- (5) In respect of export of Cut & Polished diamonds only those shipments would be taken into account for computation of eligible exports under the scheme where a minimum of 10% value addition has been achieved.

***Applicant  
Companies***

3.7.4

Companies which are Star Export Houses as well as part of a Group company shall have an option to either apply as an individual company or as a Group based on the growth in the Group's turnover as a whole. (For the purpose of this scheme the definition of Group Company as given in Chapter 9 will be applicable. Furthermore, only such companies of the Group as are Star Export Houses will be considered).

If a Group company chooses to apply based on the export of one or more of its individual Star Export House companies, the entitlement would be calculated considering the export performance of the applicant company during the previous licencing year and current licencing year. It shall be necessary that the adjusted export performance of all the Star Export House companies of the Group during the current licencing year does not fall below the combined performance of all Star Export House companies of the Group in the previous licencing year.

In case the Group chooses to apply based on the overall growth in Group's turnover (i.e. the turnover of all the Star Export House companies), any one of the Star Export House companies of the Group may file an application on behalf of all the Star Export House companies of the Group.

3.7.5

The following exports shall not be taken into account for calculation of export performance or for computation of entitlement under the scheme:

- (a) Export of imported goods covered under Para 2.35 of the Foreign Trade Policy or exports made through transshipment.
- (b) Export turnover of units operating under SEZ/EOU/EHTP/STPI/ BTP Schemes or products manufactured by them and exported through DTA units.
- (c) Deemed exports (even when payments are received in Free Foreign Exchange and payment is made from EEFC account).
- (d) Service exports .
- (e) Rough, uncut and semi polished diamonds and other precious stones.

- (f) Gold, silver, platinum and other precious metals in any form, including plain and studded Jewellery.
- (g) Export performance made by one exporter on behalf of another exporter.

**Imports allowed**

3.7.6

The Duty Credit may be used for import of any inputs, capital goods including spares, office equipment, professional equipment and office furniture provided the same is freely importable under ITC (HS) Classification of Export and Import items, for their own use or that of supporting manufacturers as declared in 'Aayaat Niryaat Form'.

Import of agricultural Products listed in Chapter 1 to 24 of ITC (HS) Classification of Export and Import items except the following shall be allowed:

- (i) Garlic, Peas and all other Vegetables with a Duty of more than 30% under Chapter 7 of ITC (HS) Classification of Export and Import items.
- (ii) Coconut, Areca Nut, Oranges, Lemon, Fresh Grapes, Apple and Pears and all other fruits with a Duty of more than 30% under Chapter 8 of ITC (HS) Classification of Export and Import items.
- (iii) All spices with a Duty of more than 30% under Chapter 9 of ITC (HS) Classification of Export and Import items (except Cloves).
- (iv) Tea, Coffee and Pepper as per Chapter 9 of ITC (HS) Classification of Export and Import items.
- (v) All Oil Seeds under Chapter 12 of ITC (HS) Classification of Export and Import items.

Further, Natural Rubber as per Chapter 40 of ITC (HS) Classification of Export and Import items shall also not be allowed for import under the Scheme.

Import of all edible oils classified under Chapter 15, shall be allowed under the scheme only through STC and MMTC.

**Cenvat/ Drawback**

3.7.7

Additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under Target Plus shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue.

**Special Provision**

3.7.8

Government reserves the right in public interest, to specify from time to time the category of exports and export

products, which shall not be eligible for calculation of incremental growth/ entitlement.

Further the Government shall have the right to change the eligibility criteria and rate of entitlement under the scheme effective from the date of notification of this policy.

Similarly, Government may from time to time also notify the list of goods, which shall not be allowed for import under the duty credit entitlement certificate issued under the scheme.

### 3.8 VISHESH KRISHI UPAJ YOJANA

#### (SPECIAL AGRICULTURAL PRODUCE SCHEME)

#### **Objective**

- 3.8.1 The objective of the scheme is to promote export of fruits, vegetables, flowers, minor forest produce, dairy, poultry and their value added products, by incentivising exporters of such products.

#### **Entitlement**

- 3.8.2 Exporters of such products shall be entitled for duty credit scrip equivalent to 5% of the FOB value of exports for each licencing year commencing from 1<sup>st</sup> April, 2004. However, dairy, poultry and their value added products shall qualify for benefits in respect of the exports made on or after 1<sup>st</sup> April 2005. The scrip and the items imported against it would be freely transferable.

- 3.8.2.1 Under the Scheme, export of all items as given in Appendix-37A of Handbook (Vol.1) shall qualify for export benefits as per Para 3.8.2 above. Items which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of the Export Policy in the ITC (HS) Classification of Export and Import items shall not be eligible for any benefits under Para 3.8.2.

- 3.8.2.2 Following exports shall not be taken into account for duty credit entitlement under the scheme :

- (a) Export of imported goods covered under Para 2.35 of the Foreign Trade Policy or exports made through transshipment.
- (b) Deemed exports (even when payments are received in Free Foreign Exchange and payment is made from EEFC account).

**Imports allowed**

3.8.3

The Duty Credit may be used for import of inputs or goods including capital goods, as may be notified, provided the same is freely importable under ITC(HS).

Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue.

3.8.3.1

Items listed in Appendix-37B of Handbook of Procedures Vol.I shall not be allowed to be imported under the scheme.

**Cenvat/ Drawback**

3.8.4

Additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under Vishesh Krishi Upaj Yojana shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue.

**Special Provision**

3.8.5

Government reserves the right in public interest, to specify from time to time the export products which shall not be eligible for calculation of entitlement.

## CHAPTER-4

## DUTY EXEMPTION &amp; REMISSION SCHEMES

***Duty Exemption and Remission Schemes***

- 4.1 Duty exemption schemes enable duty free import of inputs required for export production. An Advance Licence is issued as a duty exemption scheme. A Duty Remission Scheme enables post export replenishment/ remission of duty on inputs used in the export product. Duty remission schemes consist of (a) DFRC (Duty Free Replenishment Certificate) and (b) DEPB (Duty Entitlement Passbook Scheme).

DFRC permits duty free replenishment of inputs used in the export product. DEPB allows drawback of import charges on inputs used in the export product.

***Re-import of exported goods under Duty Exemption/ Remission Scheme***

- 4.1.1 Goods exported under Advance Licence/ DFRC/ DEPB may be re-imported in the same or substantially the same form subject to such conditions as may be specified by the Department of Revenue from time to time.

***Value Addition***

- 4.1.2 The value addition for the purposes of this chapter (Except for the Gems and Jewellery) shall be:-

$$V.A = \frac{(A - B)}{B} \times 100, \quad \text{where}$$

V.A.: Value Addition

A: FOB value of the export realised /FOR value of supply received.

B: CIF value of the imported inputs covered by the licence, plus any other imported materials used on which the benefit of duty drawback is being claimed.

***ADVANCE LICENCE******Advance Licence***

- 4.1.3 An Advance Licence is issued to allow duty free import of inputs, which are physically incorporated in the export product (making normal allowance for wastage). In addition, fuel, oil, energy, catalysts etc., which are consumed/utilised in the course of their use to obtain the export product, may also be allowed under the scheme.

Duty free import of mandatory spares upto 10% of the CIF value of the licence which are required to be exported/ supplied with the resultant product may also be allowed under Advance Licence.

Advance Licences are issued on the basis of the inputs and export items given under SION. However, they can also be issued on the basis of Adhoc norms or self declared norms as per para 4.7 of Handbook (Vol. I). Advance Licence can be issued either to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer(s):

- i) for Physical exports (including exports to SEZ); and/ or
- ii) for Intermediate supplies; and /or
- iii) to the main contractor for supply of goods to the categories mentioned in paragraph 8.2 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) and (j) of the Policy;

for import of inputs required in the manufacture of goods.

In addition, in respect of supply of goods to specified projects mentioned in paragraph 8.2 (d), (e), (f), (g) and (j) of the Policy, an Advance Licence can also be availed by the sub-contractor of the main contractor to such project provided the name of the sub contractor(s) appears in the main contract.

Such licence can also be issued for supplies made to United Nations Organisations or under the Aid Programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in free foreign exchange.

4.1.4 Advance Licence is issued for duty free import of inputs, as defined in paragraph 4.1.3 subject to actual user condition. Such licences are exempted from payment of basic customs duty, additional customs duty, education cess, anti dumping duty and safeguard duty, if any. However, the imports for supplies covered under paragraph 8.2 (h) & (i) will not be exempted from the payment of applicable anti-dumping and safeguard duty, if any.

4.1.5 Advance Licence and/or materials imported thereunder shall not be transferable even after completion of export obligation. However, the licensee will have the option to dispose off the product manufactured out of the duty free inputs once the export obligation is completed.



- 4.1.6 Advance Licences shall be issued with a positive value addition.

However, for physical exports for which payments are not received in freely convertible currency, the same shall be subject to value addition as specified in Appendix-11 of Handbook (Vol.1).

In case of Tea, the minimum value addition under advance licence shall be 100%.

- 4.1.7 Advance Licence shall be issued in accordance with the Policy and procedure in force on the date of issue of licence.

The validity period of advance licence for import shall be as prescribed in the Handbook (Vol.1).

- 4.1.8 The facility of Advance Licence shall also be available where some or all of the inputs are supplied free of cost to the exporter.

In such cases, for calculation of value addition, the notional value of free of cost inputs along with value of other duty-free inputs shall be taken into consideration. However, if all the inputs are supplied free of cost, it shall be covered under paragraph 4.2.7 of the Policy.

### ***Export Obligation***

- 4.1.9 The period for fulfilment of the export obligation under Advance Licence shall be as prescribed in the Handbook (Vol.1).

### ***Provision for BIFR units***

- 4.1.9 A Any firm/company registered with BIFR or any firm/company acquiring a unit, which is under BIFR shall be allowed EOP extension as per the rehabilitation package prepared by the operating agency subject to subsequent approval of BIFR.

However, in cases where the rehabilitation package does not specify the EOP extension period, a time period upto 5 years reckoned from the date of issue of licence would be permitted on merits of the case for fulfillment of export obligation.

Similarly, SSI units shall also be entitled for similar facility as per the rehabilitation scheme of the concerned State government. However, in cases where the State

rehabilitation scheme does not specify the export obligation extension period, a time period upto 5 years reckoned from the date of issue of licence would be permitted on merits of the case for fulfillment of export obligation.

***Advance Licence  
for Annual  
Requirement***

4.1.10

Advance Licence can also be issued on the basis of annual requirement for physical exports, intermediate supplies and / or deemed exports.

One to Five Star Export House shall be entitled for the Advance licence for annual requirement. All other categories of exporters having past export performance (in the preceding two years) shall also be entitled for the Advance Licence for annual requirement.

In addition, a merchant exporter shall also be issued the Advance Licence for Annual Requirement provided they agree to the endorsement of the name(s) of the supporting manufacturer(s) on the relevant licence.

The entitlement in terms of CIF value of imports under this scheme shall be upto 300% of the FOB value of physical export and / or FOR value of deemed export in the preceding licensing year or Rs 1 crore, whichever is higher. Such licence shall have value addition as specified in para 4.1.6 of the Foreign Trade Policy.

***Advance Release  
Orders***

4.1.11

An Advance Licence holder, holder of advance licence for annual requirement, holder of Diamond Imprest Licence and holder of DFRC intending to source the inputs from indigenous sources/State Trading Enterprises/ EOU/SEZ/ EHTP/STP/BTP units in lieu of direct import has the option to source them against Advance Release Orders denominated in free foreign exchange/ Indian rupees.

The transferee of a DFRC shall also be eligible for ARO facility. However, supplies may be obtained against the licence from EOU/EHTP/BTP/STP/ units, without conversion into ARO.

The validity period of ARO shall be as prescribed in the Handbook (Vol.1).

***Back-to-Back  
Inland Letter of  
Credit***

4.1.12

An Advance Licence holder, holder of advance licence for annual requirement, holder of Diamond Imprest Licence and holder of DFRC may, instead of applying for an Advance Release Order, avail of the facility of Back-to-

Back Inland Letter of Credit in accordance with the procedure specified in Handbook (Vol.1).

***Prohibited Items***

- 4.1.13 Prohibited items of imports mentioned in ITC(HS) shall not be imported under the licence issued under the scheme.

Further the items reserved for imports by State Trading Enterprises cannot be imported against advance licence. However those items can be procured from State Trading Enterprises against ARO issued to advance licence holder.

Similarly prohibited items of exports mentioned in the ITC(HS) shall not be exported under the licence issued under the scheme. Further, export of restricted items shall be subject to all conditionalities or requirement of export licence or permission, as may be required, under Schedule II of ITC (HS).

***Admissibility of Drawback***

- 4.1.14 In the case of an Advance Licence, the drawback shall be available in respect of any of the duty paid materials, whether imported or indigenous, used in the goods exported, as per the drawback rate fixed by Ministry of Finance (Directorate of Drawback). The Drawback shall however be restricted to the duty paid materials as mentioned in the licence.

***DUTY FREE REPLENISHMENT CERTIFICATE***

***Duty Free Replenishment Certificate (DFRC)***

- 4.2 DFRC is issued to a merchant exporter or manufacturer exporter for the import of inputs used in the manufacture of goods without payment of basic customs duty.

However, such inputs shall be subject to the payment of additional customs duty equal to the excise duty at the time of import.

- 4.2.1 DFRC shall be issued on minimum value addition of 25% except for items in gems and jewellery sector for which value addition as given in paragraph 4A.2.1 of the Handbook (Vol.1) shall be applicable.

- 4.2.2 DFRC may be issued for physical exports against freely convertible currency / supplies effected under paragraph 8.2 of the Policy (except for supplies made to DFRC holder). DFRC may also be issued in respect of exports (including supplies to SEZ) for which payments are received in non-

convertible currency. Such exports shall, however, be subject to value addition and conditions as specified in Appendix-11 of Handbook (Vol.1)

- 4.2.3 DFRC shall be issued only in respect of products covered under the Standard Input Output Norms as notified by DGFT.

However, in respect of Standard Input Output Norms which are subject to "actual user" condition or where the export proceeds have not been realised at the time of filing application or for import of fuel under the general norms, DFRC shall be issued with actual user condition for these inputs.

However, for fuel, the import entitlement may be transferred only to the companies which have been granted authorization to market fuel by the Ministry of Petroleum & Natural Gas.

In cases where Standard Input Output Norms allow import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo Ephedrine, DFRC shall be issued provided these items are specifically deleted from the list of import items.

DFRC will not be issued against SION which prescribe a prior import condition for inputs.

- 4.2.4 DFRC shall be issued for import of inputs as per SION as indicated in the shipping bills. The validity of such licences will be governed by the provision stipulated in the handbook (Vol. I). DFRC and or the material(s) imported against it shall be freely transferable. However, DFRC with actual user condition or the material(s) imported against it shall not be transferable.

- 4.2.5 The export products, which are eligible for modified VAT, shall be eligible for CENVAT credit/ service tax credit.

However, non excisable, non dutiable or non CENVAT products, shall be eligible for drawback at the time of exports in lieu of additional customs duty to be paid at the time of imports under the scheme.

- 4.2.6 The exporter shall be entitled for drawback benefits in respect of any of the duty paid materials, whether imported or indigenous, used in the export product as per the

drawback rate fixed by Directorate of Drawback (Ministry of Finance).

The drawback shall however be restricted to the duty paid materials not covered under SION.

***Jobbing, repairing  
etc. for re-export***

- 4.2.7 Import of goods, including those mentioned as restricted in ITC(HS) but excluding prohibited items, supplied free of cost, may be permitted for the purpose of jobbing without a licence/certificate/ permission as per the terms of notification issued by Department of Revenue from time to time.

Similarly, import of goods for carrying out repairs, re-conditioning, re-engineering, testing etc. shall be allowed as per the terms and conditions of the Customs notification even though the goods may be restricted for imports under the Foreign Trade Policy/ITC(HS) Classification of Imports and Exports Book.

The above provisions shall, however, be subject to all conditionality or requirement of licence or permission, as may be required, under Schedule II of ITC (HS).

***DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK SCHEME***

***Duty Entitlement  
Passbook Scheme  
(DEPB)***

- 4.3 The objective of DEPB is to neutralise the incidence of Customs duty on the import content of the export product. The neutralisation shall be provided by way of grant of duty credit against the export product.

The DEPB scheme will continue to be operative until it is replaced by a new scheme which will be drawn up in consultation with exporters .

- 4.3.1 Under the DEPB scheme, an exporter may apply for credit, as a specified percentage of FOB value of exports, made in freely convertible currency.

The credit shall be available against such export products and at such rates as may be specified by the Director General of Foreign Trade by way of public notice issued in this behalf, for import of raw materials, intermediates, components, parts, packaging material etc.

- 4.3.2 The holder of DEPB shall have the option to pay additional customs duty, if any, in cash as well.
- Validity** 4.3.3 The validity period of DEPB for import shall be as prescribed in the Handbook (Vol.1).
- Transferability** 4.3.4 The DEPB and/or the items imported against it are freely transferable. The transfer of DEPB shall however be for import at the port specified in the DEPB, which shall be the port from where exports have been made.
- Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue.
- Applicability of Drawback** 4.3.5 Normally, the exports made under the DEPB Scheme shall not be entitled for drawback. However, the additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under DEPB shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue.

### **GEMS AND JEWELLERY**

- Scheme for Gems and Jewellery** 4A Exporters of gems and Jewellery can import/procure duty free inputs required for manufacture of gems and jewellery items.
- Replenishment Licence** 4A.1 Exporters of gems and jewellery are eligible to import their inputs duty free by obtaining Replenishment (REP) Licences from the licensing authorities in accordance with the procedure specified in this regard in the Handbook of Procedure (Vol.1).
- 4A.1.1 The exporters of gems and jewellery products listed in Appendix-12A of the Handbook (Vol.1) shall be eligible for grant of Replenishment Licences at the rate and for the items mentioned in the said Appendix to import and replenish their inputs.
- Replenishment licence may also be issued for import of consumables as per the details given in paragraph 4A.28 of Handbook (Vol.1).

***Export of Cut &  
Polished Diamonds  
for Certification/  
Grading***

4A.2 Gem and Jewellery exporters may be permitted to send cut & polished diamonds each weighing 0.25 of a carat and above for certification/grading to Indian Diamond Institute, Surat, Gujarat. In addition, Gem and Jewellery exporters with a track record of at least three years and having an annual average turnover of Rs.5 crores and above during the preceding three licensing years or the authorized offices /agencies in India of Gemological Institute of America (GIA), The Robert Mouawad Campus, International Gemological Institute (IGI) and European Gemological Laboratory (EGL) in USA, Hoge Road Voor Diamond, Antwerp, (HRD), World Diamond Centre of Diamonds High Council, Antwerp, Belgium, Central Gem Laboratory, Miyagi Building, 5-15-14 Ueno Taito-Ku, Tokyo, Japan may also be permitted to export cut & polished diamonds each weighing 0.25 of a carat and above to the said laboratories/agencies for the purpose of certification/grading reports by them with a condition that the same should be re-imported with the certificate/grading reports issued by them without any import duty at the time of re-import.

4A.2.1 At the time of export of cut and polished diamonds for certification/grading, exporter should give an undertaking to the customs that the cut and polished diamonds will be re-imported within three months of exports for certification/grading.

The export invoice should clearly indicate the estimated value, height, circumference, weight of each diamond to be exported for certification/ grading so that at the time of their import, the above specification could be compared with the original ones to establish their identity. Subsequently these cut and polished diamonds would be exported as per the provisions of the Policy.

***Schemes for Gold/  
Silver/ Platinum  
Jewellery***

4A.3 Exporters of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof may import their essential inputs such as gold, silver, platinum, mountings, findings, rough gems; precious and semi-precious stones, synthetic stones and unprocessed pearls etc. in accordance with the procedure specified in this behalf.

***Nominated Agencies***

4A.4 Exporters (excepting units operating under EOU/SEZ schemes) availing the schemes of gold/ silver/platinum jewellery and articles thereof may obtain gold/silver/platinum from the nominated agencies. The nominated agencies are MMTC Ltd, Handicraft and Handloom Export Corporation (HHEC), State Trading Corporation (STC), the Project and Equipment Corporation

of India Ltd (PEC) , Five Star Export House under Paragraph 3.5.2 of the Policy and any other agency authorised by Reserve Bank of India (RBI).

A bank authorised by RBI is allowed export of gold scrap for refining and import in the form of standard gold bars. The detailed procedure for the import of gold will be as per the guidelines notified by RBI separately.

### ***Items of Export***

4A.5

The following items, if exported, would be eligible for the facilities under the schemes stipulated in paragraph 4A of the Foreign Trade Policy:

- (a) Gold jewellery, including partly processed jewellery and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above;
- (b) Silver jewellery including partly processed jewellery, silverware, silver strips and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight;
- (c) Platinum jewellery including partly processed jewellery and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight.

### ***Value Addition***

4A.6

The value addition for the purpose of gems and jewellery sector shall be as per paragraph 4A.2.1 of Handbook (Vol.1).

$$V.A. = \frac{(A - B)}{B} \times 100, \quad \text{where}$$

V.A. : Value Addition,

A : FOB value of the export realised /FOR value of supply received.

B : The Value of inputs such as gold / silver / platinum content in the export product plus the admissible wastage along with the value of the other items such as gemstone etc. 'Value' for this purpose includes both imported as well as domestically procured inputs. Wherever gold has been



obtained on loan basis, the value shall also include interest paid in free foreign exchange to the foreign supplier.

**Wastage Norms**

- 4A.7 Under the schemes for gold/silver/platinum jewellery, the wastage or manufacturing loss shall be admissible as per paragraph 4A.2 of the Handbook (Vol.1).

**Export against Supply by Foreign Buyer**

- 4A.8 Where export orders are placed on the nominated agencies/status holder/ exporters of three years standing having an annual average turnover of Rs. Five Crore during the preceding three licensing years, the foreign buyer may supply to the nominated agencies/status holder/exporter, in advance and free of charge, gold/ silver/ platinum, alloys, findings and mountings of gold/ silver/ platinum for manufacture and export.

The exports may be made by the nominated agencies directly or through their associates or by the status holder/exporter as the case may be. The import and export of findings shall be on net to net basis. The foreign buyer may also supply to the nominated agencies/status holder/exporter in advance and free of charge plain, semi finished gold/silver/platinum jewellery including findings/ mountings/ components for repairs/re-make and export subject to minimum value addition of 10%. However, if the so imported semi finished gold/silver /platinum jewellery is exported as studded jewellery, value addition of 15% shall be achieved. In such cases of export, wastage of 2% may be permitted.

The procedures in this regard shall be as prescribed in the Handbook (Vol.1).

**Export Against Supply by Nominated Agencies**

- 4A.9 The exporter may obtain the gold/silver/platinum as an input for export products from nominated agencies in advance or as replenishment after exports in accordance with the procedure specified in this behalf.

**Export Against Advance Licence**

- 4A.10 An Advance Licence may be granted for the duty free import of:
- (a) Gold of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings of 8 carats and above;
  - (b) Silver of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% silver by weight;

- (c) Platinum of fineness not less than 0.900 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% platinum by weight.

- 4A.11 Such licences shall carry an export obligation which will be required to be fulfilled in accordance with the procedure specified in paragraph 4A of the handbook (Vol. I).

The Advance Licence holder may obtain gold/silver/platinum from the nominated agencies in lieu of direct import in accordance with the procedure specified in this behalf.

***Gem Replenishment  
Licence***

- 4A.12 Gem Replenishment (Gem & Jewellery REP) Licence may be issued under the schemes for export of gold/ silver/ platinum jewellery and articles thereof as given in paragraph 4A.8, 4A.9 and 4A.10 of the Policy. In the case of plain gold/ silver/platinum jewellery and articles, the value of such licences shall be determined with reference to the realisation in excess of the prescribed minimum value addition.

In the case of studded gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the value of Gem Replenishment Licence shall be determined by taking into account the value of studdings used in items exported, after accounting for the value addition on gold/ silver/ platinum including admissible wastage.

Such Gem REP licences shall be freely transferable.

***Gem REP Rate and  
Item***

- 4A.13 The scale of replenishment and the item of import will be as prescribed in Appendix 12B of Handbook (Vol. I).

***Diamond Imprest  
Licence***

- 4A.14 Diamond Imprest Licence for import of cut & polished diamonds including semi processed diamonds, half cut diamonds, broken in any form, for mixing with cut & polished diamonds or for export as it is, may be issued for export of cut & polished diamonds.

Such licences shall carry an export obligation, which has to be discharged in accordance with the procedure specified in this behalf.

***Eligibility***

- 4A.14.1 An exporter of cut & polished diamonds who is status holder may be issued a licence for import of cut & polished

diamonds upto 5% of the export performance of the preceding year of cut & polished diamonds.

- |   |         |  |
|---|---------|--|
| <b><i>Export Obligation</i></b>   | 4A.14.2 | The export obligation under the scheme will be governed by the provisions of paragraph 4A of chapter 4 of the handbook (Vol. 1).   |
| <b><i>Export Promotion<br/>Tours/ Export of<br/>Branded Jewellery</i></b> | 4A.15   | <p>The nominated agencies and their associates, with the approval of Department of Commerce, and others, with the approval of Gem &amp; Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), may export gold/ silver/platinum jewellery and articles thereof for holding/participating in exhibitions abroad.</p> <p>Personal carriage of gold/ silver/platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles and export of branded jewellery is also permitted. These exports shall be subject to the conditions as given in the Handbook (Vol.1).</p> |
| <b><i>Personal Carriage<br/>of Export/ Import<br/>Parcels</i></b>         | 4A.16   | Personal carriage of gems and jewellery export parcels by foreign bound passengers and personal carriage of gems & jewellery import parcels by an Indian importer/foreign national may be permitted as per the conditions given in Handbook (Vol.1).   |
| <b><i>Export by Post</i></b>  | 4A.17   | In case of exports through Foreign Post Office which may include export via Speed Post through Foreign Post Office, the value of the jewellery parcels shall not exceed US\$50000 and 20 kg. by weight. The detailed procedure is laid down in chapter 4 of the handbook (vol.1).  |
| <b><i>Private/ Public<br/>Bonded Warehouse</i></b>                        | 4A.18   | Private/Public Bonded Warehouses may be set up in SEZ/ DTA for import and re-export of cut & Polished diamonds, cut & polished coloured gemstones, uncut & unset precious & semi-precious stones. Import & re-export of cut & polished diamonds & cut & polished coloured gemstones will be subject to achievement of minimum value addition of 5%.  |
| <b><i>Diamond &amp;<br/>Jewellery Dollar<br/>Accounts</i></b>             | 4A.19   | Firms and companies dealing in the purchase/sale of rough or cut and polished diamonds/ precious metal jewellery plain, minakari and/or studded with/without diamond and/or other stones with a track record of at least 3 years in import or export of diamonds/ coloured gemstones/ diamond and coloured gemstones studded jewellery/ plain gold jewellery and having an average annual turnover of Rs. 5 crore or above during preceding three licensing years  |

may also carry out their business through designated Diamond Dollar Accounts.

The Diamond Dollar Account Scheme shall operate under the current licensing scheme of this chapter. This scheme shall be optional and those importers/exporters who wish to continue to use Rupee Accounts shall be allowed to do so under the existing policies.

Dollars in such accounts available from bank finance and/or export proceeds shall be used only for

- (i) Import/purchase of rough diamonds from overseas/local sources,
- (ii) Purchase of cut and polished diamonds, coloured gemstones and plain gold jewellery from local sources,
- (iii) Import/purchase of gold from overseas/ nominated agencies and repayment of dollar loans from the bank; and
- (iv) Transfer to the Rupee Account of the exporter. Details of this Diamond Dollar Accounts Scheme (DDAS) are given in the Handbook (Vol.1). The procedure outlined in the Handbook (Vol.1) shall also apply to diamond studded jewellery.

A non DDA holder is also permitted to supply cut and polished diamonds to DDA holder, receive payment in dollars and convert same into rupees within the period of 7 days and cut and polished diamonds and coloured gemstones so supplied by non-DDA holder will also be counted towards the discharge of his export obligation and/or entitle him to replenishment licence as the case may be.

## CHAPTER-5

### EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME

#### ***EPCG Scheme***

5.1

The scheme allows import of capital goods for pre production, production and post production (including CKD/SKD thereof as well as computer software systems) at 5% Customs duty subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved on capital goods imported under EPCG scheme to be fulfilled over a period of 8 years reckoned from the date of issuance of licence.

In the case of agro units, import of capital goods at 5% Customs duty shall be allowed subject to a fulfillment of an export obligation equivalent to 6 times the duty saved (on capital goods imported under the Scheme) over a period of 12 years from the date of issue of licence.

However for SSI units, import of capital goods at 5% Customs duty shall be allowed subject to a fulfillment of an export obligation equivalent to 6 times the duty saved (on capital goods imported under the Scheme) over a period of 8 years from the date of issue of licence provided the landed CIF value of such imported Capital Goods under the Scheme does not exceed Rs Twenty Five Lakhs and the total investment in plant and machinery after such imports does not exceed the SSI limit.

However, in respect of EPCG licences with a duty saved of Rs.100 crore or more, the same export obligation, as the case may be shall be required to be fulfilled over a period of 12 years.

In case CVD is paid in cash on imports under EPCG, the incidence of CVD would not be taken for computation of net duty saved provided the same is not Cenvated.

The capital goods shall include spares (including refurbished/ reconditioned spares), tools, jigs, fixtures, dies and moulds. EPCG licence may also be issued for import of components of such capital goods required for assembly or manufacturer of capital goods by the licence holder.

Second hand capital goods without any restriction on age may also be imported under the EPCG scheme.

However, import of motor cars, sports utility vehicles/ all purpose vehicles shall be allowed only to hotels, travel agents, tour operators or tour transport operators and

companies owning/operating golf resorts whose total foreign exchange earning in current and preceding three licencing years is Rs 1.5 crores. However, the parts of motor cars, sports utility vehicles/ all purpose vehicles such as chassis etc. cannot be imported under the EPCG Scheme.

Import of Restricted items of imports mentioned under ITC(HS) shall only be allowed to be imported under the Scheme after approval from the Import Licensing Committee.

- |  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 5.1A  | Spares (including refurbished/ reconditioned spares), tools, spare refractories, catalyst & consumable for the existing plant and machinery imported/to be imported under the Scheme shall also be allowed subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved to be fulfilled over a period of 8 years reckoned from the date of issuance of licence. |
| <b><i>EPCG for Projects</i></b>                      | 5.1B  | An EPCG licence can also be issued for import of capital goods under the Scheme for Project Imports notified by the Central Board of Excise and Customs under S.No 441 of Customs Exemption Notification No 21/2002 dated 01.03.2002 wherein the basic customs duty on imports is 10% with a CVD of 16%.   |
|  |       | The export obligation for such EPCG licences would be eight times the duty saved. The duty saved would be the difference between the effective duty under the aforesaid Customs Notification and the concessional duty under the EPCG Scheme.  |
| <b><i>EPCG for Retail Sector</i></b>                 | 5.1 C | To create modern infrastructure in the retail sector, concessional duty benefits under EPCG scheme shall be extended for import of capital goods required by retailers having minimum area of 1000 sq meters. The retailer shall fulfil the export obligation i.e. 8 times the duty saved in 8 years.  |
| <b><i>Eligibility</i></b>                            | 5.2   | The scheme covers manufacturer exporters with or without supporting manufacturer(s)/ vendor(s), merchant exporters tied to supporting manufacturer(s) and service providers.   |
| <b><i>Conditions for import of Capital Goods</i></b> | 5.3   | Import of capital goods shall be subject to Actual User condition till the export obligation is completed.   |

**Export obligation**

5.4

The following conditions shall apply to the fulfillment of the export obligation:-

- (i) The export obligation shall be fulfilled by the export of goods capable of being manufactured or produced by the use of the capital goods imported under the scheme.

The export obligation may also be fulfilled by the export of same goods, for which EPCG licence has been obtained, manufactured or produced in different manufacturing units of the licence holder/specified supporting manufacturer (s).

When Capital Goods are imported for pre/ post-production or license is taken for import of spares, the license holder shall fulfill the export obligation by export of products manufactured from the plant / project to which the pre/ post- production capital goods/ spares are related.

The import of capital goods for creating storage and distribution facilities for products manufactured or services rendered for export by the EPCG licence holder would be permitted under the EPCG Scheme.

The export obligation under the scheme shall be, over and above, the average level of exports achieved by him in the preceding three licensing years for same and similar products within the overall export obligation period including extended period, if any except for categories mentioned in Handbook (Vol.1).

Alternatively, export obligation may also be fulfilled by exports of other good(s) manufactured or service(s) provided by the same firm/company or group company/ managed hotel which has the EPCG licence.

However, in such cases, the additional export obligation imposed under EPCG scheme shall be over and above the average exports achieved by the unit/company/group company/ managed hotel in preceding three years for both the original and the substitute product(s) /service (s) even in cases where the average is exempt for the substitute product (s)/ service (s) as given in para 5.7.6 of the Handbook (Vol 1).

The incremental exports to be fulfilled by the licence holder for fulfilling the remaining export obligation can include any combination of exports of the original product/ service and the substitute product (s)/ service (s). The exporter of goods can opt to get the export obligation refixed for the export of services and vice versa.

The licensee can also opt for the re-fixation of the balance export obligation based on 8 times of the duty saved amount for the CIF value in proportion to the balance Export obligation under the scheme. The guidelines for the re-fixation of export obligation is given in para 5.19 of the Handbook (Vol 1).

The aforesaid facilities shall only be available to manufacturer exporters/ service provider on all the licences where export obligation period including extended export obligation period is valid on the date of application. In this regard, exports made only on or after submission of application for alternate item and/ or re-fixation of the export obligation based on duty saved amount will be taken into account for fulfillment of export obligation.

- (ii) The export obligation under the scheme shall be, in addition to any other export obligation undertaken by the importer, except the export obligation for the same product under Advance Licence, DFRC, DEPB or Drawback scheme.
- (iii) The export obligation can also be fulfilled by the supply of ITA-1 items to the DTA provided the realization is in free foreign exchange.
- (iv) Exports shall be physical exports. However, deemed exports as specified in paragraph 8.2 (a), (b), (d), (f), (g) & (j) of Policy shall also be counted towards fulfilment of export obligation alongwith the usual benefits available under paragraph 8.3 of the Policy.

Royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for R& D services shall also be counted for discharge under the EPCG scheme. Payment received in rupee terms for the port handling services, in terms of Chapter 9



of the Foreign Trade Policy shall also be counted for export obligation discharge under the Scheme.

Payments received against 'Counter Sales' in free foreign exchange through banking channels as per the RBI guidelines shall be counted for fulfillment of export obligation under Para 5.1 C.

**Provision for BIFR units** 5.5.1

Any firm/company registered with BIFR or any firm/company acquiring a unit, which is under BIFR shall be allowed EO extension as per the rehabilitation package prepared by the operating agency subject to subsequent approval of BIFR.

However, in cases where the rehabilitation package does not specify the EO extension period, a time period upto 12 years reckoned from the date of issue of licence would be permitted on merits of the case for fulfillment of export obligation.

Similarly, small-scale SSI units shall also be entitled for similar facility as per the rehabilitation scheme of the concerned State government. However, in cases where the State rehabilitation scheme does not specify the export obligation extension period, a time period upto 12 years reckoned from the date of issue of licence would be permitted on merits of the case for fulfillment of export obligation.

**EPCG for agro units** 5.5.2

In the case of EPCG licences issued to agro units in the agri export zones, a period of 12 years reckoned from the date of issue of the licence would be permitted for the fulfillment of export obligation.

The agro units in the agri export zones would also have the facility of moving the capital good (s) imported under the EPCG within the agri export zone.

An LUT/ Bond or a 15% BG (as the case may be) may be given for EPCG licence granted to units in the Agri Export Zones provided the EPCG licence is taken for export of the primary agricultural product (s) notified in Appendix 8 or their value added variants.

**Indigenous Sourcing of Capital Goods and benefits to Domestic Supplier** 5.6

A person holding an EPCG licence may source the capital goods from a domestic manufacturer instead of importing them. The domestic manufacturer supplying capital goods to EPCG licence holders shall be eligible for deemed export benefit under paragraph 8.3 of the Policy.

***Benefits to Domestic Supplier*** 5.7

In the event of a firm contract between the EPCG licence holder and domestic manufacturer for such sourcing, the domestic manufacturer may apply for the issuance of Advance Licence for the import of inputs including components required for the manufacturer of said capital goods.

The domestic manufacturer may also replenish the inputs including components after supply of capital goods to the EPCG licence holders.

***Fixation of Export Obligation*** 5.7A

In case of direct imports, the export obligation relating to the EPCG licence shall be reckoned with reference to the duty saved value on the CIF value of capital goods (including spares, jigs, fixtures, dies and moulds) actually imported. In case of domestic sourcing, the export obligation relating to EPCG shall be reckoned with reference to the notional Customs duties saved-on the FOR of capital goods (including spares, jigs, fixtures, dies and moulds).

5.8 Service provider in Agri export zone shall have the facility to move or shift the capital goods within the zone provided he maintains accurate record of such movements. However, such equipments shall not be sold or leased by the licence holder.

***Maintenance of Average exports under EPCG*** 5.9

As per the provisions of para 5.4(i), the EPCG licence holder would have to maintain the average level of exports equivalent to the average of the exports in the preceding three licencing years for the same and similar products except for exempted categories given in Handbook (Vol. 1) during the entire period of export obligation.

Notwithstanding the above, the licence holder shall maintain the average exports in any particular year (s) provided the same is offset by excess exports to fulfil the average in other year (s).

***Technological Upgradation of existing EPCG machinery*** 5.10

EPCG licence holders can opt for Technological Upgradation of the existing capital goods imported under the EPCG licence.

The conditions governing the Technological Upgradation of the existing capital goods are as under:

- (i) The minimum time period for applying for Technological Upgradation of the existing capital

goods imported under EPCG is 5 years from the date of issuance of the licence.

- (ii) The minimum exports made under the old capital goods must be 40% of the total export obligation imposed on the first EPCG licence.
- (iii) The export obligation would be refixed such that the total export obligation mandated for both the capital goods would be the sum total of 6 times the duty saved on both the capital goods.
- (iv) The procedure governing the replacement of capital good is given in para 5.20 of the Handbook (Vol. 1).
- (v) The facility for technological upgradation shall be available only once and the minimum imports to be made shall be at least 10% of the existing investment in plant and machinery by the applicant firm.

***Incentives for  
Fast Track  
Companies***

5.11

To incentivise fast track companies with a view to accelerate exports under the Scheme, in cases where the licence holder has fulfilled 75% or more of the export obligation under the Scheme (including average level of exports) in half or less than half the original export obligation period specified in the Licence, the remaining export obligation shall be condoned and the Licence redeemed by the licensing authority concerned.

However no benefits under Para 5.12 of Handbook (Vol. 1) shall be available in such cases.

## CHAPTER- 6

## EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPs) AND BIO-TECHNOLOGY PARKS (BTPs)

**Eligibility**

- 6.1 Units undertaking to export their entire production of goods and services (except permissible sales in the DTA), may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme, Electronic Hardware Technology Park (EHTP) Scheme, Software Technology Park (STP) Scheme or Bio-Technology Park (BTP) scheme for manufacture of goods, including repair, re-making, reconditioning, re-engineering and rendering of services. Trading units, however, are not covered under these schemes.

**Export and Import of Goods**

- 6.2
- (a) An EOU/EHTP/STP/BTP unit may export all kinds of goods and services except items that are prohibited in the ITC (HS). Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in the ITC (HS).
  - (b) An EOU/EHTP/STP/BTP unit may import and/or procure from DTA or bonded warehouses in DTA / international exhibition held in India without payment of duty all types of goods, including capital goods, required for its activities, provided they are not prohibited items of import in the ITC (HS). Any permission required for import under any other law shall be applicable. The units shall also be permitted to import goods including capital goods required for the approved activity, free of cost or on loan/lease from clients. The import of capital goods will be on a self certification basis.
  - (c) State Trading regime shall not apply to EOU manufacturing units.
  - (d) EOU/EHTP/STP/BTP units may import/procure from DTA without payment of duty certain specified goods for creating a central facility which will be used by software units. These software units can be EOU/ DTA units who will use the facility for export of software.
  - (e) An EOU engaged in agriculture, animal husbandry, aquaculture, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry or sericulture may be permitted to remove specified goods in connection with its activities for use outside the bonded area.

- (f) Gems and jewellery EOUs may source gold/silver/platinum through the nominated agencies also. Units obtaining gold/silver/platinum from the nominated agencies shall export gold/silver/platinum jewellery within 90 days from the date of release. This shall not, however, apply to outright purchase of precious metal from the nominated agencies.
- (g) EOU/EHTP/STP/BTP units, other than service units, may export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit/Escrow Rupee Account of the buyer subject to RBI clearance, if any.
- (h) Procurement and supply of spares and consumables required for the goods manufactured by the units may be allowed to be exported along with goods upto 1.5% of FOB value of exports. This shall, however, not count towards NFE calculation, for concessional rate DTA sales or for Income Tax exemption.
- Second Hand Capital Goods** 6.3 Second hand capital goods, without any age limit, may also be imported duty free.
- Leasing of Capital Goods** 6.4 An EOU/EHTP/STP/BTP unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic/foreign leasing company without payment of customs/excise duty. In such a case, the EOU/ EHTP/ STP/BTP unit and the domestic/foreign leasing company shall jointly file the documents to enable import/procurement of the capital goods without payment of duty.
- Net Foreign Exchange Earnings (NFE)** 6.5 EOU/EHTP/STP/BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner. Net Foreign Exchange Earnings (NFE) shall be calculated cumulatively in blocks of five years, starting from the commencement of production.
- Letter of Permission/ Letter of Intent and Legal Undertaking** 6.6 (a) On approval, a Letter of Permission (LOP) /Letter of Intent (LOI) shall be issued by the Development Commissioner/designated officer to EOU/EHTP/STP/BTP unit. The LOP/LOI shall have an initial validity of 3 years by which time the unit should have commenced production. Its validity may be extended further up to 3 years by the competent authority. However, proposals for extension beyond six years shall be considered in exceptional circumstances, on a case-to-case basis by the BOA. Once the unit commences production, LOP/LOI issued shall be valid for a period of 5 years for its activities. This period may be extended further by the Development Commissioner for a period of 5 years at a time.

- (b) LOP/LOI issued to EOU/EHTP/STP/BTP units by the concerned authority would be construed as a licence for all purposes.
- (c) The unit shall execute a legal undertaking with the Development Commissioner concerned. Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of the LOP/LOI/IL/LUT shall render the unit liable to penal action under the provisions of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and the Rules and Orders made thereunder without prejudice to action under any other law/rules and cancellation or revocation of LOP/LOI/IL.

### ***Investment Criteria***

- (d) Only projects having a minimum investment of Rs.1 crore in plant and machinery shall be considered for establishment as EOUs under the scheme. This shall, however, not apply to existing units and units in EHTP / STP / BTP, Handicrafts / Agriculture / Floriculture / Aquaculture / Animal Husbandry / Information Technology, Services, Brass hardware, Handmade Jewellery and such other sectors as may be decided by the BOA.

### ***Application & Approvals***

6.7

- (a) Applications for setting up of units under EOU scheme other than proposals for setting up of units in the services sector (except R&D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by the BOA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per the criteria indicated in Handbook (Vol. 1).
- (b) In other cases, approval may be granted by the Board of Approval (BOA) set up for this purpose as indicated in the Handbook (Vol. 1).
- (c) Proposals for setting up EOU requiring industrial licence may be granted approval by the Development Commissioner after clearance of the proposal by the Board of Approval and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days.

### ***DTA Sale of Finished Products/Rejects/Waste/Scrap/ Remnants and By-products***

6.8

The entire production of EOU/EHTP/STP/BTP units shall be exported subject to the following:

- (a) Units, other than gems and jewellery units, may sell goods upto 50% of FOB value of exports subject to fulfilment of positive NFE on payment of concessional duties. Within the entitlement of DTA sale, the unit may sell in DTA its products similar to the goods, which are exported or expected to be

exported from the units. No DTA sale at concessional duty shall be permissible in respect of motor cars, alcoholic liquors, books and tea (except instant tea) or by a packaging / labeling / segregation / refrigeration unit / compacting / micronisation / pulverization / granulation / conversion of monohydrate form of chemical to anhydrous form or vice-versa and such other items as may be notified from time to time.

Sales made to a unit in SEZ shall also be taken into account for the purpose of arriving at FOB value of export by EOU provided payment for such sales are made from EEFC Account. Sale to DTA would also be subject to mandatory requirement of registration of pharmaceutical products (including bulk drugs).

- (b) For services, including software units, sale in the DTA in any mode, including on line data communication shall also be permissible up to 50% of FOB value of exports and /or 50% of foreign exchange earned, where payment of such services is received in foreign exchange.
- (c) Gems and jewellery units may sell upto 10% of FOB value of exports of the preceding year in DTA subject to fulfillment of positive NFE. In respect of sale of plain jewellery, the recipient shall pay concessional rate of duty as applicable to sale from nominated agencies. In respect of studded jewellery, duty shall be payable as applicable.
- (d) Unless specifically prohibited in the LOP, rejects within a overall limit of 50% may be sold in the Domestic Tariff Area (DTA) on payment of duties as applicable to sale under paragraph 6.8(a) on prior intimation to the Customs authorities. Such sales shall be counted against DTA sale entitlement. Sale of rejects upto 5% of FOB value of exports shall not be subject to achievement of NFE.
- (e) Scrap/ waste/ remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in the DTA as per the Standard Input-Output norms notified under the Duty Exemption Scheme on payment of concessional duties as applicable within the overall ceiling of 50% of FOB value of exports. Such sales shall not, however, be subject to achievement of positive NFE. In respect of items not covered by the

norms, the Development Commissioner may fix ad-hoc norms on the basis of data for a period of six months and within this period, he shall get the norms fixed by the BOA. Sale of waste/scrap/remnants by units not entitled to DTA sale or sales beyond the DTA sale entitlement, shall be on payment of full duties. The scrap/waste/remnants may also be exported.

- (f) There shall be no duties/taxes on scrap/waste/remnants in case the same are destroyed with the permission of Customs authorities.
- (g) By-products included in the LOP may also be sold in the DTA subject to achievement of positive NFE on payment of applicable duties within the overall entitlement of paragraph 6.8(a). Sale of by-products by units not entitled to DTA sales or beyond the entitlements of paragraph 6.8 (a) shall also be permissible on payment of full duties.
- (h) EOU/ EHTP/ STP/BTP units may sell finished products, which are freely importable under the Policy in the DTA under intimation to the Development Commissioner against payment of full duties provided they have achieved the positive NFE.
- (i) In the case of units manufacturing electronics hardware and software, the NFE and DTA sale entitlement shall be reckoned separately for hardware and software.
- (j) In case of DTA sale of goods manufactured by EOU/EHTP/STP/BTP, where basic duty and CVD is nil, such goods may be considered as non-excisable for the purpose of payment of duty.
- (k) In case of new EOUs, advance DTA sale will be allowed not exceeding 50% of its estimated exports for the first year except the pharmaceutical units where this will be based on its estimated exports for the first two years.

**Other Supplies in  
DTA**

6.9

Following supplies effected from EOU/EHTP/STP/BTP units to DTA will be counted for the purpose of fulfilment of positive NFE:



- (a) Supplies effected in DTA to holders of advance licence/advance licence for annual requirement/DFRC under the duty exemption / remission scheme /EPCG scheme.
- (b) Supplies effected in DTA against payment from the Exchange Earners Foreign Currency (EEFC) Account of the buyer in the DTA or against foreign Exchange remittance received from overseas.
- (c) Supplies to other EOU/EHTP/STP//BTP/SEZ units provided that such goods are permissible for procurement in terms of paragraph 6.2 of the Policy.
- (d) Supplies made to bonded warehouses set up under the policy and/ or under section 65 of the customs act and free trade and warehousing zones, where payment is received in foreign exchange.
- (e) Supplies of goods and services to such organizations which are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by the Ministry of Finance.
- (f) Supply of services (by services units) relating to exports paid for in free foreign exchange or for such services rendered in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI.
- (g) Supplies of Information Technology Agreement (ITA-1) items and notified zero duty telecom/ electronic items.

***Export through others***

- 6.10 An EOU/EHTP/STP/BTP unit may export goods manufactured/software developed by it through another exporter or any other EOU/EHTP/STP/SEZ unit subject to the conditions mentioned in para 6.19 of Handbook.

***Entitlement for supplies from the DTA***

- 6.11 (a) Supplies from the DTA to EOU/EHTP/STP/BTP units will be regarded as "deemed exports" and the DTA supplier shall be eligible for the relevant entitlements under chapter 8 of the Policy besides discharge of export obligation, if any, on the supplier. Notwithstanding the above, EOU/ EHTP/ STP/BTP units shall, on production of a suitable disclaimer from the DTA supplier, be eligible for obtaining the entitlements specified in chapter 8 of the Policy. For

the purpose of claiming deemed export duty drawback, they shall get Brand Rates fixed by the Development Commissioner, wherever All Industry Rates of Drawback are not available.

- (b) Suppliers of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOU shall be eligible for grant of Replenishment Licenses at the rates and for the items mentioned in the Handbook (Vol.1).
- (c) In addition, the EOU/EHTP/STP/BTP units shall be entitled to the following:-
  - i. Reimbursement of Central Sales Tax on goods manufactured in India.
  - ii. Exemption from payment of Central Excise Duty on goods procured from DTA on goods manufactured in India.
  - iii. Deleted
  - iv. Reimbursement of Duty paid on fuels procured from domestic oil companies as per the rate of Drawback notified by the DGFT from time to time.
  - v. CENVAT Credit on service tax paid.

### **Other Entitlements**

6.12

Other entitlements of EOU/EHTP/STP/BTP units are as under:

- (a) Exemption from payment of Income Tax as per the provisions of Section 10A and 10B of Income Tax Act.
- (b) Exemption from industrial licensing for manufacture of items reserved for SSI sector.
- (c) Deleted
- (d) Export proceeds will be realized within 12 Months.
- (e) Will be allowed to retain 100% of its export earning in the EEFC account.

- (f) The Units will not be required to furnish <sup>1</sup>bank guarantee at the time of import or going for job work in DTA, where the unit has (i) a turnover of Rupees 5 crores or above, (ii) the unit is in existence for at least three years and (iii) unit having an unblemished track record.
- (g) 100% FDI investment permitted through Automatic Route similar to SEZ units.

**Inter Unit Transfer** 6.13

- (a) Transfer of manufactured goods from one EOU/EHTP/STP/BTP unit to another EOU/EHTP/STP/BTP/ SEZ unit will be allowed.
- (b) Capital goods may be transferred or given on loan to other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ units with prior intimation to the concerned Development Commissioner and Customs authorities.
- (c) Goods supplied by one unit of EOU/EHTP/STP/BTP to another unit shall be treated as imported goods for the second unit for the purpose of payment of duty, on DTA sale by the second unit.

**Sub-Contracting** 6.14

- (a)(i) EOU/EHTP/STP/BTP units, including gem and jewellery units, may on the basis of annual permission from the Customs authorities, subcontract production processes to DTA through job work which may also involve change of form or nature of goods, through job work by units in the DTA.
- (ii) These units may also subcontract upto 50% of the overall production of the previous year in value terms for job work in DTA with the permission of the Customs Authorities.
- (b)(i) EOU may, on the basis of annual permission from the Customs authorities, undertake job work for export, on behalf of DTA exporter, provided that the goods are exported directly from EOU and export document shall jointly be in the name of DTA/EOU. For such exports, the DTA units will be entitled for refund of duty paid on the inputs by way of Brand Rate of duty drawback.
- (ii) Duty free import of goods for execution of export order placed on EOU by Foreign Supplier on job

work basis would be allowed subject to the condition that no DTA clearance shall be allowed.

- (iii) Subcontracting of both production and production processes may also be undertaken without any limit through other EOU/EHTP/ STP/SEZ/BTP units on the basis of records maintained in the unit.
- (iv) Subcontracting of part of production process may also be permitted abroad with the approval of the Development Commissioner.
- (c) Scrap/waste/remnants generated through job work may either be cleared from the job worker's premises on payment of applicable duty on transaction value or destroyed in the presence of Customs/ Excise authorities or returned to the unit. Destruction shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.
- (d) Sub-contracting/exchange by gems and jewellery EOUs through other EOUs or SEZ units or units in DTA shall be as per procedure indicated in Handbook (Vol-I).

***Sale of Un-utilised  
Material***

6.15

- (a) In case an EOU/EHTP/STP/BTP unit is unable to utilize the goods and services, imported or procured from DTA, it may be (i) transferred to another EOU/SEZ/EHTP/STP/BTP unit or (ii) disposed off in the DTA with the approval of the Customs authorities on payment of applicable duties and submission of import licence, if required, or (iii) exported. Such transfer from EOU/EHTP/STP/BTP unit to another such unit would be treated as import for the receiving unit.
- (b) Capital goods and spares that have become obsolete/surplus, may either be exported, transferred to another EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ or disposed of in the DTA on payment of applicable duties. The benefit of depreciation, as applicable, will be available in case of disposal in DTA. No duty shall be payable in case capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap/ waste/ remnants/rejects are destroyed within the Unit after intimation to the Custom authorities or destroyed outside the Unit with the permission of Custom authorities. Destruction as

stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.

- (c) In the case of textile sector , disposal of leftover material/fabrics upto 2% of CIF value or quantity of import whichever is lower, on payment of duty on transaction value may be allowed, subject to certification of central excise/custom officers that these are leftover items.
- (d) Disposal of used packing material will be allowed on payment of duty on transaction value.

***Reconditioning /  
Repair and  
Re-engineering***

- 6.16 EOU/EHTP/STP/BTP units may be set up with the approval of BOA to carry out reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, up-gradation of technology and re-engineering activities for export in foreign currency. The provisions of paragraphs 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 of policy and para 6.29 of Handbook shall not, however, apply to such activities.

***Replacement/  
Repair of imported/  
Indigenous Goods***

- 6.17
- (a) The general provisions of the Policy relating to export / import of replacement / repair of goods would also apply equally to EOU/EHTP/STP/BTP units. Cases not covered by these provisions shall be considered on merits by the Development Commissioner.
  - (b) The goods sold in the DTA and not accepted for any reasons may be brought back for repair/ replacement, under intimation to the concerned jurisdictional Customs/Excise authorities.
  - (c) Goods or parts thereof on being imported/ indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective subsequently may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, the goods may be brought back from the foreign suppliers or their authorized agents in India or indigenous suppliers. However destruction shall not apply to precious and semi precious stones and precious metals.

***Exit from EOU  
Scheme***

- 6.18
- (a) With the approval of the Development Commissioner, EOU units may opt out of the scheme. Such exit from the scheme shall be subject to payment of Excise and Customs duties and the industrial policy in force at the time of exit.

- (b) If the unit has not achieved the obligations under the scheme, it shall also be liable to penalty at the time of exit.
- (c) In the event of a gem and jewellery unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gem and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) at the price to be determined by that agency.
- (d) An EOU//EHTP/STP/BTP unit may also be permitted by the Development Commissioner, to exit from the scheme on payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG Scheme as a one time option. This will be subject to fulfilment of the eligibility criteria under that Scheme and standard conditions indicated in Handbook (Vol. 1).
- (e) The unit proposing to exit out of the EOU scheme shall intimate the Development Commissioner and Customs and Central Excise authorities in writing. The unit shall assess the duty liability arising out of debonding and submit the details of such assessment to customs and Central Excise authorities. The Customs and Central Excise authorities shall confirm the duty liabilities on priority basis. After payment of duty and clearance of all dues the unit shall obtain "No Dues Certificate" from the Customs and Central Excise authorities. On the basis of No dues certificate so issued by the Customs and Central Excise authorities the unit shall apply to the Development Commissioner for final debonding. In case there is no proceeding pending under FT(D&R) Act 1992, the Development Commissioner shall issue final debonding order within a period of 7 working days. During the period between "No dues certificate" issued by the Customs and Central Excise authorities and the final debonding order by the Development Commissioner the unit shall not be entitled to claim any exemption for procurement of capital goods or input. The unit can however, claim Advance License / DFRC / DEPB / Duty Drawback.
- (f) In cases where a unit is initially established as DTA unit with machine procured from abroad after payment of applicable import duty or from domestic market after payment of excise duty and the unit is subsequently converted to EOU, in such cases removal of such capital goods to DTA after debonding would be without payment of duty.

Similarly, in cases where a DTA unit imported capital goods under the EPCG Scheme and after completely fulfilling the export obligation under the EPCG scheme gets converted into EOU, the unit would not be charged customs duty on capital goods at the time of removal of such capital goods in DTA at the time of debonding.

### **Conversion**

- 6.19 (a) Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU/EHTP/STP/BTP unit, and Income Tax benefits under Section 10-A & 10-B will be available under the scheme for plant, machinery and equipment already installed.
- (b) The existing EHTP/STP units may also apply for conversion/merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, the units will remain in bond and avail the exemptions in duties and taxes as applicable under the relevant scheme.

### **Monitoring of NFE**

- 6.20 The performance of EOU/EHTP/STP/BTP units shall be monitored by the Units Approval Committee as per the guidelines given in Handbook (Vol-I).

### **Export through Exhibitions/Export Promotion Tours /Export through showrooms abroad/Duty Free Shops.**

- 6.21 EOU/EHTP/STP/BTP are permitted to :
- (i) Export goods for holding/ participating in exhibitions abroad with the permission of Development Commissioner.
  - (ii) Personal carriage of gold/ silver/ platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles.
  - (iii) Export goods for display/sale in the permitted shops set up abroad.
  - (iv) Display/sell in the permitted shops set up abroad or in the show rooms of their distributors/agents.
  - (v) Set up show rooms/retail outlets at the International Airports.

### **Personal Carriage Of Import / Export Parcels Including Through Foreign bound Passengers**

- 6.22 Import/ export through personal carriage of gem and jewellery items may be under-taken as per the procedure prescribed by Customs. The export proceeds shall, however, be realized through normal banking channel. Import/export through personal carriage by units, other than gem and jewellery units, shall be allowed provided the goods are not in commercial quantity.

<b><i>Export /Import by Post /Courier</i></b>	6.23	Goods including free samples, may be exported/imported by airfreight or through Foreign Post Office or through courier, subject to the procedure prescribed by Customs.
<b><i>Administration of EOUs/Power of Development Commissioner</i></b>	6.24	Details of administration of EOUs and Power of Development Commissioner are given in Handbook (Vol.1).
<b><i>Revival of Sick units</i></b>	6.25	Subject to a unit being declared sick by the appropriate authority, proposals for revival of the unit or its take over may be considered by the Board of Approval.
<b><i>Approval for EHTP/STP</i></b>	6.26	In the case of units under EHTP/STP Schemes, necessary approval / permission under relevant paragraphs of this Chapter shall be granted by the officer designated by the Ministry of Communication and Information Technology, Department of Information Technology for the purpose instead of the Development Commissioner and by the Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) instead of BOA.
<b><i>Approval of BTP</i></b>	6.27	Bio-Technology Parks (BTP) would be notified by the DGFT on the recommendations of Department of Biotechnology. In the case of units in the BTP, necessary approval/permission under relevant provisions of this chapter will be granted by designated officer of the Department of Biotechnology.



## CHAPTER-7

## SPECIAL ECONOMIC ZONES

**Note:** *Special Economic Zones (SEZ) are growth engines that can boost manufacturing, augment exports and generate employment. The private sector has been actively associated with the development of SEZs. The SEZs require special fiscal and regulatory regime in order to impart a hassle free operational regime encompassing the state of the art infrastructure and support services. The proposed legislation on SEZs to be enacted in the near future would cover the concepts of the developer and co-developer, fiscal concessions under the Income Tax and Customs Act, provide for Offshore Banking Units (OBUs) etc. A brief on the facilities available under the SEZ scheme is given as under:*

**Eligibility**

- 7.1 (a) Special Economic Zone (SEZ) is a specifically delineated duty free enclave and shall be deemed to be foreign territory for the purposes of trade operations and duties and tariffs.
- (b) Goods and services going into the SEZ area from DTA shall be treated as exports and goods coming from the SEZ area into DTA shall be treated as if these are being imported.
- (c) SEZ units may be set up for manufacture of goods and rendering of services.

**Export and Import of Goods.**

- 7.2 (a) SEZ units may export goods and services including agro-products, partly processed goods, sub-assemblies and components except prohibited items of exports in ITC (HS). The units may also export by-products, rejects, waste scrap arising out of the production process. Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in the ITC (HS) Classification of Export and Import Items.

SEZ units, other than trading/service units, may also export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit/Escrow Rupee Account of the buyer, subject to RBI clearance, if any.

- (b) SEZ unit may import/procure from the DTA without payment of duty all types of goods and services, including capital goods, whether new or second hand, required by it for its activities or in connection

therewith, provided they are not prohibited items of imports in the ITC(HS). However, any permission required for import under any other law shall be applicable. Goods shall include raw material for making capital goods for use within the unit. The units shall also be permitted to import goods required for the approved activity, including capital goods, free of cost or on loan from clients.

- (c) SEZ units may procure goods required by it without payment of duty, from bonded warehouses in the DTA set up under the Policy and/or under Section 65 of the Customs Act and from International Exhibitions held in India.
- (d) SEZ units, may import/procure from DTA, without payment of duty, all types of goods for creating a central facility for use by units in SEZ. The Central facility for software development can also be accessed by units in the DTA for export of software.
- (e) Gem & Jewellery units may also source gold/ silver/ platinum through the nominated agencies.
- (f) SEZ units may import/procure goods and services from DTA without payment of duty for setting up, operation and maintenance of units in the Zone.

<b><i>Leasing of Capital Goods</i></b>	7.3	SEZ unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic/foreign leasing company. In such a case the SEZ unit and the domestic/ foreign leasing company shall jointly file the documents to enable import/ procurement of the capital goods without payment of duty.
<b><i>Net Foreign Exchange Earning (NFE)</i></b>	7.4	SEZ unit shall be a positive Net Foreign exchange Earner. Net Foreign Exchange Earning (NFE) shall be calculated cumulatively for a period of five years from the commencement of production according to the formula given in Chapter 7 of the Handbook (Vol. 1)
<b><i>Monitoring of performance</i></b>	7.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) The performance of SEZ units shall be monitored by the Unit Approval Committee.</li> <li>(b) The performance of SEZ units shall be monitored as per the guidelines given in Appendix 14-IG of the Handbook (Vol. 1).</li> </ul>
<b><i>Legal Undertaking</i></b>	7.6	The unit shall execute a legal undertaking with the Development Commissioner concerned and in the event of

failure to achieve positive foreign exchange earning it shall be liable to penalty in terms of the legal undertaking or under any other law for the time being in force.

***Approvals and Applications***

7.7

- (a) Applications for setting up a unit in SEZ other than proposals for setting up of unit in the services sector (except software and IT enabled services, trading or any other service activity as may be delegated by the BOA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per procedure indicated in Appendix 14-IB of the Handbook (Vol. 1) . In other cases approval may be granted by the Board of Approval.
- (b) Proposals for setting up units in SEZ requiring Industrial Licence may be granted approval by the Development Commissioner after clearance of the proposal by the SEZ Board of Approval and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days on merits.

***DTA Sales and Supplies***

7.8

- (a) SEZ unit may sell goods, including by-products, and services in DTA in accordance with the import policy in force, on payment of applicable duty.
- (b) DTA sale by service/trading unit shall be subject to achievement of positive NFE cumulatively. Similarly for units undertaking manufacturing and services/trading activities against a single LOP, DTA sale shall be subject to achievement of NFE cumulatively.
- (c) The following supplies effected in DTA by SEZ units will be counted for the purpose of fulfillment of positive NFE:
  - (i) Supplies effected in DTA in terms of Chapter 8 of the Policy.
  - (ii) Supplies made to bonded warehouses set up under the Policy and/or under Section 65 of the Customs Act.
  - (iii) Supplies to other EOU/SEZ/ EHTP/ STP/BTP units provided that such goods or services are permissible to be procured/rendered by these units.
  - (iv) Supplies against special entitlement of duty free import of goods.

- (v) Supplies of goods and services to such organizations which are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by the Ministry of Finance.
- (vi) Supply of services (by services units) relating to exports paid for in free foreign exchange or for such services rendered in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI.
- (vii) Supplies of Information Technology Agreement (ITA-1) items and notified zero duty telecom/electronic items indicated in the Appendix 14-IC of the Handbook.

***Entitlement for  
Supplies from the  
DTA***

7.9

Supplies from DTA to SEZ shall be entitled for the following:

- (a) DTA supplier shall be entitled for:
  - (i) Drawback /DEPB/DFRC/Advance Licence
  - (ii) Discharge of Export performance, if any, on the supplier.
- (b) SEZ units shall be entitled for:-
  - (i) Exemption from Central Sales Tax.
  - (ii) Exemption from payment of Central Excise Duty on all goods eligible for procurement by the unit.
  - (iii) Deleted
  - (iv) Reimbursement of Duty paid on fuels or any other goods procured from DTA as per the rate of drawback notified by the Directorate General of Foreign Trade from the date of such notification.
- (c) Supplier of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from Domestic Tariff Area to the units situated in SEZ shall be eligible for grant of Replenishment Licenses at the rates and for the items mentioned in the Handbook (Vol. 1).
- (d) The entitlements under paragraphs (a) and (b) (ii)

above shall be available provided the goods supplied are manufactured in India.

***Export Through  
Status Holder***

7.10

SEZ unit may also export goods manufactured/software developed by it through a merchant exporter/ status holder recognized under this Policy or any other EOU/SEZ/ EHTP/STP unit.

***Inter-unit Transfer***

7.11

- (a) SEZ units may transfer manufactured goods, including partly processed/semi-finished goods and services from one SEZ unit to another SEZ/EOU/ EHTP/STP unit.
- (b) Goods imported/procured by a SEZ unit may be transferred or given on loan to another unit within the same SEZ which shall be duly accounted for, but not counted towards discharge of export performance.
- (c) Capital goods imported/procured may be transferred or given on loan to another SEZ/EOU/ EHTP/ STP unit with prior permission of the Development Commissioner and Customs authorities concerned.
- (d) Transfer of goods in terms of sub-para (a) and (b) above within the same SEZ shall not require any permission but the units shall maintain proper accounts of the transaction.

***Other Entitlements***

Other entitlements of SEZ units are indicated in the Chapter 7 of the Handbook (Vol. 1).

***Sub- Contracting***

7.12

- (a) SEZ unit, may subcontract a part of their production or production process through units in the DTA or through other SEZ/EOU/ EHTP/ STP, with the annual permission of Customs authorities. Subcontracting of part of production process may also be permitted abroad with the approval of the Development Commissioner.
- (b) Sub-contracting by SEZ gems and jewellery units through other SEZ units or EOUs or units in DTA shall be subject to following conditions
  - i) Goods, finished or semi-finished, including studded jewellery, taken outside the zone for sub- contracting shall be brought back to the unit within 90 days. No cut and polished

diamonds, precious and semi-precious stones (except precious and semi precious stone having zero duty) shall be allowed to be taken outside the zone for sub-contracting.

- ii) Receive plain gold/silver/platinum jewellery from DTA in exchange of equivalent quantity of gold/silver/ platinum, as the case may be, contained in the said jewellery.
  - iii) SEZ units shall be eligible for wastage as applicable for sub-contracting and against exchange.
  - iv) The DTA unit undertaking job work or supplying jewellery against exchange of gold/silver/platinum shall not be entitled to export benefits.
- (c) All units, including gem and jewellery; may sub-contract part of the production or production process through other units in the same SEZ without permission of Customs authorities subject to records being maintained by both the supplying and receiving units.
- (d) SEZ units other than gems and jewellery units may be allowed to undertake job-work for export, on behalf of DTA exporter, provided the finished goods are exported directly from SEZ units. For such exports, the DTA units will be entitled for refund of duty paid on the inputs by way of Brand Rate of duty drawback.
- (e) Scrap/waste/remnants generated through job work may either be cleared from the job worker's premises on payment of applicable duty or returned to the unit.
- (f) SEZ units engaged in production/processing of agriculture/horticulture products, may on the basis of annual permission from the Customs authorities take out inputs and equipments to the DTA farm subject to the procedure indicated in Chapter 7 of the Handbook (Vol. 1)

***Exit from SEZ Scheme***

7.13

- (a) SEZ unit may opt out of the scheme with the approval of the Development Commissioner. Such exit from the scheme shall be subject to payment of

applicable Customs and Excise duties on the imported and indigenous capital goods, raw materials etc. and finished goods in stock. In case the unit has not achieved positive NFE, the exit shall be subject to penalty, that may be imposed by the adjudicating authority under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

- (b) SEZ unit may also be permitted by the Development Commissioner, as one time option, to exit from SEZ scheme on payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG Scheme, subject to the unit satisfying the eligibility criteria of that Scheme and standard conditions for exit indicated in Appendix 14-IL of the Handbook (Vol. 1).

**Export through Exhibitions/Export Promotion Tours/Export through show rooms abroad/Duty Free Shops**

7.14

SEZ, units may :

- (i) Export goods for holding/ participating in exhibitions abroad with the permission of Development Commissioner.
- (ii) Personal carriage of gold/ silver/ platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles.
- (iii) Export of jewellery is also permitted for display/ sale in the permitted shops set up abroad.
- (iv) Display/sell in the permitted shops set up abroad or in the show rooms of their distributors/agents.
- (v) Set up show rooms/retail outlets at the International Airports.

**Personal Carriage of Export/ Import parcel.**

7.15

Import/ export through personal carriage of gem and jewellery items may be under-taken as per the procedure prescribed by Customs. Import/export through personal carriage for units, other than gem and jewellery unit, shall be allowed provided the goods are not in commercial quantity.

**Export /Import by post/ courier**

7.16

Goods including free samples, may be exported/imported by airfreight or through Foreign Post Office or through courier, subject to the procedure prescribed by Customs.

**Disposal of Rejects/Scrap/ Waste/ Remnants**

7.17

Rejects/scrap/waste/remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in the DTA on payment of applicable duty. No duty shall be payable in case scrap/waste/ remnants/ rejects are destroyed within the Zone after intimation to the Custom authorities or destroyed

outside the SEZ with the permission of Custom authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.

**Replacement/ Repair  
of Goods** 7.18

- (a) The general provisions of Policy relating to export of replacement/ repaired goods shall apply equally to SEZ units, save that, cases not covered by these provisions shall be considered on merits by the Development Commissioner.
- (b) The goods sold in the DTA and found to be defective may be brought back for repair/ replacement under intimation to Development Commissioner.
- (c) Goods or parts thereof, including gem stones and precious metal components for jewellery making, on being imported/ indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective after import/ procurement may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, the goods may be brought back from the foreign suppliers or their authorised agents in India or the indigenous suppliers. Destruction shall however not apply to gem stones and precious metals.
- (d) Goods may be transferred to DTA/abroad for repair/ replacement, testing or calibration, quality testing and R & D purpose under intimation to Customs authorities and subject to maintenance of records.

**Management of SEZ** 7.19

- (a) SEZ will be under the administrative control of the Development Commissioner.
- (b) All activities of SEZ units within the Zone, unless otherwise specified, including export and re-import of goods shall be through self certification procedure.

**Setting up of SEZ in  
Private/Joint/State  
Sector** 7.20

A SEZ may be set up in the public, private, joint sector or by state Government as per details indicated in Appendix 14-II O of the Handbook (Vol. 1).

**Samples** 7.21

SEZ units may, on the basis of records maintained by them, and on prior intimation to Customs authorities:

- (i) Supply or sell samples in the DTA for display/ market promotion on payment of applicable duties.
- (ii) Remove samples without payment of duty, on furnishing a suitable undertaking to Customs



authorities for bringing the goods back within a stipulated period.

- (iii) Export free samples, without any limit, including samples made in wax moulds, silver mould and rubber moulds through all permissible mode of export including through couriers agencies/post.

***Sale of Un-utilised  
Material/Obsolete  
goods***

7.22

- (a) In case an SEZ unit is unable, for valid reasons, to utilize the goods, including capital goods and spares, it may dispose them in the DTA in accordance with the import policy in force and on payment of applicable duties or export them.
- (b) Capital goods and spares that have become obsolete/surplus may either be exported or disposed of in the DTA on payment of applicable duties. The benefit of depreciation, as applicable, will be available in case of disposal in DTA.
- (c) No duty shall be payable in case capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged and scrap/waste/remnants/rejects are destroyed within the Zone after intimation to the Custom authorities or destroyed outside the Zone with the permission of Custom authorities. However destruction shall not apply to precious and semi precious and precious metals.
- (d) SEZ unit may be allowed by Customs authorities concerned to donate imported/ indigenously procured computer and computer peripherals without payment of duty, two years after their import/procurement and use by the units, to recognized non-commercial educational institutions, registered charitable hospitals etc as per the details given in Chapter 7 of the Handbook (Vol. 1).

***Entitlement for SEZ  
Developer***

7.23

For development, operation and maintenance of infrastructure facilities in SEZs, the developer shall be eligible for the following entitlements

- (a) Income tax exemption as per 80 IA of the Income Tax Act.
- (b) Import/ procure goods without payment of Customs/Excise duty.
- (c) Exemption from Service tax.
- (d) Exemption from CST.

## CHAPTER 7A

### FREE TRADE & WAREHOUSING ZONES

#### **Objective**

- 7A.1 The objective is to create trade-related infrastructure to facilitate the import and export of goods and services with freedom to carry out trade transactions in free currency. The scheme envisages creation of world-class infrastructure for warehousing of various products, state-of-the-art equipment, transportation and handling facilities, commercial office-space, water, power, communications and connectivity, with one-stop clearance of import and export formality, to support the integrated Zones as 'international trading hubs'. These Zones would be established in areas proximate to seaports, airports or dry ports so as to offer easy access by rail and road.

#### **Status**

- 7A.2 The Free Trade & Warehousing Zones (FTWZ) shall be a special category of Special Economic Zones with a focus on trading and warehousing.

#### **Establishment of Zone**

- 7A.3
- (i) Proposals for setting up of FTWZs may be made by public sector undertakings or public limited companies or by joint ventures in technical collaboration with experienced infrastructure developers. The proposals shall be considered by the Board of Approval in the Department of Commerce. On approval, the developer will be issued a letter of permission for the development, operation and maintenance of such FTWZ.
  - (ii) Foreign Direct Investment would be permitted up to 100% in the development and establishment of the zones and their infrastructural facilities.
  - (iii) The proposal must entail a minimum outlay of Rs.100 crores for the creation and development of the infrastructure facilities, with a minimum built up area of five lakh sq.mts.
  - (iv) The developer shall be permitted to import duty free such building materials and equipment as may be required for the development and infrastructure of the zone. Such equipment and materials as are sourced from the DTA shall be considered as physical exports for the DTA suppliers.

- (v) Once it has developed the FTWZ, the developer shall also be permitted to sale/lease/rent out warehouses/workshops/office-space and other facilities in the FTWZ to traders/exporters.

**Maintenance of Zone**

- 7A.4 The developer shall itself or through suitable special purpose arrangements, ensure a reliable mechanism for the proper maintenance of the common facilities and security of the FTWZ.

**Functioning**

- 7A.5
- (i) The scheme envisages duty free import of all goods (except prohibited items, arms and ammunitions, hazardous wastes and SCOMET items) for ware housing. As far as bond towards customs duty on import is concerned, the units would be subject to similar provisions as are applicable to units in SEZs.
  - (ii) Such goods shall be permitted to be re-sold/re-invoiced or re-exported. Re-export shall be permitted without any restrictions. However export of SCOMET items shall not be permitted except with the permission of Inter-Ministerial Committee.
  - (iii) These goods shall also be permitted to be sold in the DTA on payment of customs duties as applicable on the date of such sale. Payment of duty will become due only when goods are sold/delivered to DTA and no interest will be charged as in the case of bonded warehouses.
  - (iv) Packing or re-packing without processing, and labeling as per customer or marketing requirements could be undertaken within the FTWZ.
  - (v) The maximum period that goods shall be permitted to be warehoused within the FTWZ will be two years, after which they shall necessarily have to be re-exported or sold in the DTA. On expiry of the two year period, customs duties as applicable would automatically become due unless the goods are re-exported within such grace period, not exceeding three months, as may be permitted.

**Entitlement of units**

- 7A.6
- (i) Income Tax exemption as per 80 IA of the Income Tax Act.
  - (ii) **Exemption from Service Tax.**

(iii) Free foreign exchange currency transactions would be permitted.

(iv) Other benefits mutatis mutandi as applicable to units in SEZs.

***NFE criteria***

7A.7 Units in FTWZs shall be net foreign exchange earners. Net foreign exchange earning shall be calculated cumulatively for every block of five years from the commencement of warehousing and/or trading operations as per formula applicable for SEZ units.

## CHAPTER-8

### DEEMED EXPORTS

***Deemed Exports***

8.1 "Deemed Exports" refers to those transactions in which the goods supplied do not leave the country and the payment for such supplies is received either in Indian rupees or in free foreign exchange.

***Categories of Supply***

8.2 The following categories of supply of goods by the main/sub-contractors shall be regarded as "Deemed Exports" under this Policy, provided the goods are manufactured in India:

- (a) Supply of goods against Advance Licence / Advance Licence for annual requirement/DFRC under the Duty Exemption /Remission Scheme;
- (b) Supply of goods to Export Oriented Units (EOUs) or Software Technology Parks (STPs) or Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs) or Bio Technology Parks (BTP);
- (c) Supply of capital goods to holders of licences under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme;
- (d) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies/funds as notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those agencies/funds, where the legal agreements provide for tender evaluation without including the customs duty;
- (e) Supply of capital goods, including in unassembled/disassembled condition as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till the stage of commercial production and spares to the extent of 10% of the FOR value to fertilizer plants;
- (f) Supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits the import of such goods at zero customs duty;

- (g) Supply of goods to the power projects and refineries not covered in (f) above;
- (h) Supply of marine freight containers by 100% EOU (Domestic freight containers - manufacturers) provided the said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by the customs;
- (i) Supply to projects funded by UN agencies; and
- (j) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to International Competitive Bidding.

The benefits of deemed exports shall be available under paragraph (d), (e), (f) and (g) only if the supply is made under the procedure of International Competitive Bidding (ICB).

**Benefits for Deemed Exports** 8.3

Deemed exports shall be eligible for any/all of the following benefits in respect of manufacture and supply of goods qualifying as deemed exports subject to the terms and conditions as given in Handbook (Vol.1):-

- (a) Advance Licence for intermediate supply/ deemed export/DFRC/ DFRC for intermediate supplies.
- (b) Deemed Export Drawback.
- (c) Exemption from terminal excise duty where supplies are made against International Competitive Bidding . In other cases , refund of terminal excise duty will be given.

**Benefits to the Supplier** 8.4.1

- (i) In respect of supplies made against Advance Licence in terms of paragraphs 8.2(a) of the Policy, the supplier shall be entitled to Advance Licence for intermediate supplies.
- (ii) If the supplies are made against Advance Release Order (ARO) or Back to Back Letter of Credit issued against Advance Licence in terms of paragraphs 4.1.11 and 4.1.12 of the Policy, supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraphs 8.3(b) and (c) of the Policy, whichever is applicable.

- (iii) If the supplies are made against Advance Release Order (ARO) or Back to Back Letter of Credit issued against DFRC, the supplier shall be entitled to the benefit listed in paragraph 8.3(b) of the Policy.

8.4.2 In respect of supply of goods to EOU/ EHTP/ STP/BTP in terms of paragraphs 8.2 (b) of the Policy, the supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraph 8.3(a),(b)and (c) of the Policy, whichever is applicable.

8.4.3 In respect of supplies made under paragraph 8.2 (c) of the Policy, the supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraph 8.3(a), (b) and (c), of the Policy, whichever is applicable.

8.4.4 (i) In respect of supplies made under paragraphs 8.2 (d), (f) and (g) of the Policy, the supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraphs 8.3(a),(b) and (c),whichever is applicable.

(ii) In respect of supplies mentioned in paragraph 8.2(d), supplies to the projects funded by such agencies alone, as may be notified by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, shall be eligible for deemed export benefits. A list of such agencies/ funds is given in Appendix-13 of Handbook (Vol. 1).

(iii) The benefits of deemed exports under para 8.2(f) of the Policy shall be applicable in respect of items, import of which is allowed by the Department of Revenue at zero customs duty subject to fulfilment of conditions specified under Notification No.21/2002- Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time.

(iv) Supply of Capital goods and spares upto 10% of the FOR value of the capital goods to the power projects in terms of paragraphs 8.2(g) shall be entitled for deemed export benefits provided the International Competitive Bidding procedures have been followed at Independent Power Producer (IPP)/Engineering and Procurement Contract (EPC) stage. The benefit of deemed exports shall also be available for renovation/ modernization of power plants. The supplier shall be eligible for benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of the Policy, whichever is applicable. However, supply of goods required for setting

up of any mega power projects as specified in S.No. 400 of Department of Revenue Notification No.21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended, shall be eligible for deemed exports benefits as mentioned in paragraph 8.3(a), (b) and (c) of the Policy, whichever is applicable, if such mega power project is –

(a) an inter state thermal power plant of capacity of 1000 MW or more; or

(b) an inter state Hydel power plant of capacity of 500 MW or more.

(v) Supplies under paragraph 8.2(g) of the Policy to the new refineries being set up during the Ninth plan period and spilled over to the Tenth plan period shall be entitled for deemed export benefits in respect of goods mentioned in list 17 specified in S.No.228 of Notification No.21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time.

8.4.5 In respect of supplies made under paragraph 8.2(e) of the Policy, the supplier shall be eligible for the benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of the Policy, whichever is applicable. The benefit of deemed exports shall be available in respect of supplies of capital goods and spares to fertilizer plants which are set up or expanded/ revamped/ retrofitted/modernized during the Ninth Plan period. The benefit of deemed exports shall also be available on supplies made to Fertilizer plants, which have started in the 8th /9th Plan periods and spilled over to the 10th Plan period.

8.4.6 The supplies of goods to projects funded by UN agencies covered under Para 8.2(i) of the Policy are eligible for benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of the Policy, whichever is applicable.

8.4.7 In respect of supplies made to nuclear Power Projects under para 8.2(j) of the policy, the supplier would be eligible for benefits given in para 8.3 (a), (b) and (c) of the Policy, whichever is applicable. Supply of only those goods required for setting up any nuclear power project specified in list 43 at S.No.401 of Notification No.21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time having a capacity of 440 MW or more as certified by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy shall be entitled

for deemed exports benefits in cases where the procedure of competitive bidding (and not international competitive bidding) has been followed.

***Eligibility for  
refund of terminal  
excise  
duty/drawback***

8.5

Supply of goods will be eligible for refund of Terminal Excise Duty in terms of para 8.3 (c) of Policy provided the recipient of the goods does not avail CENVAT credit /rebate on such goods. Similarly, supplies will be eligible for deemed export drawback in terms of para 8.3(b) of Policy on the Central Excise paid on inputs /components, provided CENVAT credit facility/rebate has not been availed by the applicant. Such supplies will however be eligible for deemed export drawback on the customs duty paid on the inputs/components.

***Supplies to be made  
by the main/sub-  
contractor***

8.6.1

In all cases of deemed exports, supplies shall be made directly to the designated Projects/ Agencies/ Units/ Advance Licence / EPCG licence holders. The sub-contractor may, however, make the supplies to the main contractor as per paragraph 8.4 of Handbook instead of designated projects/ agencies.

8.6.2

Supplies made by an Indian sub-contractor of an Indian or foreign main contractor, shall also be eligible for deemed export benefits provided the name of the sub-contractor is indicated either originally or subsequently in the contract, and payment certificate is issued by the project authority in the name of the sub-contractor in the form given in Appendix 22C of Handbook (Vol. 1).



## CHAPTER-9

### DEFINITIONS

- 9.1 For the purpose of this Policy, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the following meanings attached to them.
- 9.2 "Accessory" or "Attachment" means a part, sub-assembly or assembly that contributes to the efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.
- 9.3 "Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992).
- 9.4 "Actual User" means an actual user who may be either industrial or non-industrial.
- 9.5 "Actual User (Industrial)" means a person who utilises the imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit.
- 9.6 "Actual User (Non-Industrial)" means a person who utilises the imported goods for his own use in
- (i) any commercial establishment carrying on any business, trade or profession; or
  - (ii) any laboratory, Scientific or Research and Development (R&D) institution, university or other educational institution or hospital; or
  - (iii) any service industry.
- 9.7 "AEZ" means Agricultural Export Zones notified by DGFT in Appendix 8 of Handbook (Vol 1).
- 9.8 "ALC" means the Advance Licensing Committee in the Directorate General of Foreign Trade for recommending grant of licences under Duty Exemption Scheme and for recommending Input Output norms and value addition norms to be notified by Director General of Foreign Trade.
- 9.9 "Applicant" means the person on whose behalf the application is made and shall, wherever the context so requires, include the person signing the application.

- 9.10 "BOA" means the Board of Approval as notified by the Department of Commerce
- 9.11 "BTP" means Biotechnology Park as notified by Director General of Foreign Trade on the recommendation of the Department of Biotechnology
- 9.12 "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation, technological upgradation or expansion. Capital goods also include packaging machinery and equipment, refractories for initial lining, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture as well as for use in the services sector.
- 9.13 "Competent Authority" means an authority competent to exercise any power or to discharge any duty or function under the Act or the Rules and Orders made thereunder or under this Policy.
- 9.14 "Component" means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment to the component.
- 9.15 "Consumables" means any item, which participates in or is required for a manufacturing process, but does not necessarily form part of the end-product. Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process will be deemed to be consumables.
- 9.16 "Consumer Goods" means any consumption goods, which can directly satisfy human needs without further processing and includes consumer durables and accessories thereof.
- 9.17 "Counter Trade" means any arrangement under which exports/imports from/to India are balanced either by direct imports/exports from the importing/exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise. Exports/Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. The

balancing of exports and imports could wholly or partly be in cash, goods and/or services.

- 9.18 "Developer" means a person or body of persons, company, firm and such other private or government undertaking, who develops, builds, designs, organises, promotes, finances, operates, maintain or manages a part or whole of the infrastructure and other facilities in the Special Economic Zones as approved by the Central Government.
- 9.19 "Development Commissioner" means the Development Commissioner of the Special Economic Zone.
- 9.20 "DFRC" means Duty Free Replenishment Certificate.
- 9.21 "Domestic Tariff Area" means area within India which is outside the Special Economic Zones and EOU/ EHTP/ STP/BTP.
- 9.22 "Drawback" in relation to any goods manufactured in India and exported, means the rebate of duty chargeable on any imported material or excisable material used in the manufacture of such goods in India. The goods include imported spares, if supplied with capital goods manufactured in India.
- 9.23 "EHTP " means Electronic Hardware Technology Park.
- 9.24 "EOU" means Export Oriented Unit for which an LOP has been issued by the Development Commissioner.
- 9.25 "Excisable goods" means any goods produced or manufactured in India and subject to a duty of excise under the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944).
- 9.26 "Exporter" means a person who exports or intends to export and holds an Importer-Exporter Code number unless otherwise specifically exempted.
- 9.27 "Export Obligation" means the obligation to export the product or products covered by the licence or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by the licensing or competent authority.
- 9.28 "Group Company" means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to —

(i) exercise twenty-six per cent. or more of the voting rights in the other enterprise; or

(ii) appoint more than fifty percent, of the members of the board of directors in the other enterprise; or

For the group companies to claim benefits or have their exports counted for benefits to be claimed by another member of the group, the group company should have been in existence atleast 2 years prior to the date of application under any of the export promotion schemes notified in the Policy.

- 9.29 "Handbook (Vol.1)" means the Handbook of Procedures (Vol. 1) and "Handbook (Vol. 2)" means Handbook of Procedures (Vol. 2) published under the provisions of paragraph 2.4 of the Policy.
- 9.30 "Importer" means a person who imports or intends to import and holds an Importer-Exporter Code number unless otherwise specifically exempted.
- 9.31 "Infrastructure facilities" means industrial, commercial and social infrastructure or any other facility for the development of the Special Economic Zone as notified.
- 9.32 "ITC(HS)" means ITC(HS) Classifications of Export and Import Items Book.
- 9.33 "Jobbing" means processing or working upon of raw materials or semi-finished goods supplied to the job worker so as to complete a part of the process resulting in the manufacture or finishing of an article or any operation which is essential for the aforesaid process.
- 9.34 "Licensing Authority" means the authority competent to grant a licence under the Act/Order.
- 9.35 "Licensing Year" means the period beginning on the 1<sup>st</sup> April of a year and ending on the 31<sup>st</sup> March of the following year.
- 9.36 "Managed Hotel" means hotels managed by a three star or above hotel/ hotel chain under an operating management contract for a duration of atleast three years between the operating hotel/ hotel chain and the hotel being managed. The management contract must necessarily cover the entire gamut of operations/ management of the managed hotel.

- 9.37 "Manufacture" means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes such as refrigeration, re-packing, polishing, labelling. Re-conditioning repair, remaking, refurbishing, testing, calibration, re-engineering. Manufacture, for the purpose of this Policy, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, viticulture and mining.
- 9.38 "Manufacturer Exporter" means a person who export goods manufactured by him or intends to export such goods.
- 9.39 "MAI" means Market Access Initiative Scheme notified by the Department of Commerce
- 9.40 "Merchant Exporter" means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods.
- 9.41 "NFE" means Net Foreign Exchange Earning.
- 9.42 "Notification" means a notification published in the Official Gazette.
- 9.43 "Order" means an Order made by the Central Government under the Act.
- 9.44 "Part" means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. A part may be a component, spare or an accessory.
- 9.45 "Person" includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person.
- 9.46 "Policy" means the Foreign Trade Policy 2004-2009 as amended from time to time.
- 9.47 "Prescribed" means prescribed under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) or the Rules or Orders made thereunder or under this Policy.
- 9.48 "Public Notice" means a notice published under the provisions of paragraph 2.4 of the Policy.

9.49 "Raw material" means:

- (i) basic materials which are needed for the manufacture of goods, but which are still in a raw, natural, unrefined or unmanufactured state; and
- (ii) for a manufacturer, any materials or goods which are required for his manufacturing process, whether they have actually been previously manufactured or are processed or are still in a raw or natural state.

9.50 "Registration-Cum-Membership Certificate" (RCMC) means the certificate of registration and membership granted by an Export Promotion Council/ Commodity Board/ Development Authority or other competent authority as prescribed in the Policy or Handbook (Vol.1).

9.51 "Rules" means Rules made by the Central Government under Section 19 of the Act.

9.52 "Services" include all the tradable services covered under General Agreement on Trade in Services and earning free foreign exchange.

9.53 "Service Provider" means a person providing

- (i) Supply of a 'service' from India to any other country;
- (ii) Supply of a 'service' from India to the service consumer of any other country in India; and
- (iii) Supply of a 'service' from India through commercial or physical presence in the territory of any other country.
- (iv) Supply of a 'service' in India relating to exports paid in free foreign exchange or in Indian Rupees which are otherwise considered as having being paid for in free foreign exchange by RBI..

9.54 "SEZ" means Special Economic Zone notified by the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce.

9.55 "Ships" mean all types of vessels used for sea borne trade or coastal trade and shall include second hand vessels.

- 9.56 "SION" means Standard Input Output Norms notified by DGFT in the Handbook (Vol.2), 2002-07/approved by Board of Approval.
- 9.57 "Spares" means a part or a sub-assembly or assembly for substitution, that is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly. Spares include a component or an accessory.
- 9.58 "Specified" means specified by or under the provisions of this Policy.
- 9.59 "Status holder" means an exporter recognized as One to Five Star Export House by DGFT/ Development Commissioner.
- 9.60 "STP" means Software Technology Park
- 9.61 "Supporting Manufacturer" means any person who manufactures any product or part/ accessories/ components of that product. The name of the supporting manufacturer as well as the exporter must be endorsed on the export documents.
- 9.62 "Third-party exports" means exports made by an exporter or manufacturer on behalf of another exporter(s). In such cases, export documents such as shipping bills etc shall indicate the name of both the manufacturing exporter/manufacturer and third party exporter(s). The BRC, GR declaration, export order and the invoice should be in the name of the third party exporter.
- 9.63 "Transaction Value" as defined in the Customs Valuation Rules of the Department of Revenue.
- 9.64 "Unit Approval Committee" means the Committee notified for Special Economic Zones to consider proposals on matters relating to Special Economic Zone unit under its jurisdiction.
- 9.65 "Wild Animal" means any wild animal as defined in Section 2(36) of the Wildlife (Protection) Act, 1972.